पौष कृष्ण पक्ष 06, संवत 2082 | रांची एवं डालटनगंज (मेदिनीनगर) से एक साथ प्रकाशित | रजिस्ट्रेशन नं: BIHHIN/1999/155 | www.rastriyanaveenmail.com

ईश्वर में हमारा विश्वास

राष्ट्रीय नवीन मेल

सत्यमेव जयते

हर पक्ष की खबर | हर पक्ष पर नजर

मूल्य 2 रु.

रांची, बुधवार
10 दिसंबर 2025
वर्ष-26, अंक- 305, पृष्ठ-12

रांची का तापमान

कांके	रांची
अधिक. 22.4°	अधिक. 24.6°
न्यून. 05.2°	न्यून. 10.6°

पेज 10

सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी

नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में कैसे जुड़ा नाम

कोर्ट ने सोनिया गांधी और पुलिस को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया

नई दिल्ली(आईएएनएस)

बिना भारतीय नागरिकता हासिल किए मतदाता सूची में नाम शामिल कराने से जुड़े मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। यह नोटिस वकील विकास त्रिपाठी द्वारा दायर रिवीजन पिटीशन पर जारी किया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 6 जनवरी, 2026 को होगी। वकील विकास त्रिपाठी का कहना है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 की नई दिल्ली की वोटर लिस्ट में शामिल था, जबकि उन्होंने 30 अप्रैल 1983 को भारत की नागरिकता हासिल की। इसी आरोप के आधार पर मजिस्ट्रेट कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच कराने की मांग की गई थी, लेकिन सितंबर 2025 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट के इसी आदेश को चुनौती देते हुए त्रिपाठी ने रिवीजन पिटीशन दाखिल की, जिस पर अब राऊज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है।

दाखिल याचिका में कहा गया है कि 1980 की वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम कैसे शामिल हुआ, जबकि तब तक उन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की थी। याचिका में यह भी पूछा गया है कि 1982 में उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया था, तो आखिर किन कारणों से यह कार्रवाई हुई?

शेष पेज 11 पर

अंडर-14 बालक फुटबॉल टीम ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात

खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास को सरकार प्रतिबद्ध : हेमंत सोरेन

- सीएम ने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी
- सीएम ने कहा, झारखंड में खेलों की अपार संभावनाएं मौजूद हैं

नवीन मेल संवाददाता

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को झारखंड विधानसभा में झारखंड की अंडर-14 बालक फुटबॉल टीम ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने टीम के सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं सहयोगियों को राष्ट्रीय चैंपियन बनने पर हार्दिक बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि झारखंड में खेल के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास तथा उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के युवाओं की प्रतिभा और समर्पण झारखंड के गौरव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने यह उम्मीद जताई कि इसी प्रकार झारखंड के खिलाड़ी भविष्य में भी खेल जगत में नए आयाम स्थापित करेंगे। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के उमरिया में 1 दिसंबर से 6 दिसंबर 2025 तक आयोजित 69वीं स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड की अंडर-14 बालक फुटबॉल टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब अपने नाम किया था।

फाइनल मुकाबले में झारखंड ने रोमांचक पेनल्टी शूटआउट में पंजाब को 6-5 से पराजित कर यह गौरव हासिल किया। यह प्रतियोगिता झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (जेईपीसी) के बैनर तले आयोजित हुई थी। खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री से बातचीत के दौरान बताया कि राज्य सरकार की खेल नीतियों एवं प्रोत्साहन योजनाओं से उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निरंतर प्रेरणा मिल रही है।

झारखंड पुलिस सेवा के नौ अधिकारियों को मिली आईपीएस में प्रोन्नति

रांची। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड राज्य पुलिस सेवा के नौ अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में प्रोन्नति देने की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रालय द्वारा जारी यह अधिसूचना सेलेक्ट लिस्ट 2020, 2022 और 2023 के आधार पर तैयार की गई है, जिसमें झारखंड कैडर में 9 रिक्तियों को भरने की मंजूरी दी गई है। यूपीएससी की 8 दिसंबर 2025 को हुई बैठक में इन नामों पर मुहर लगाई गई थी

शेष पेज 11 पर

जामताड़ा में 5 साइबर अपराधी हुए गिरफ्तार

जामताड़ा। जिले को पुलिस द्वारा लगातार साइबर क्राइम मुक्त जिला बनाने को लेकर छापेमारी जारी है।

इसी अभियान के तहत नारायणपुर थाना अंतर्गत हीरापुर गांव में छापेमारी की गई। एक स्कूल के निकट पेड़ के नीचे से पांच साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए साइबर अपराधियों में सद्दाम अंसारी, तस्लीम रजा, समीर अंसारी, सलामत अंसारी, तजाउल अंसारी शामिल हैं।

शेष पेज 11 पर

व्हाट्सएप से सीधे जुड़ें

सुझाव, शिकायत और समाचारों का स्वागत समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए सप्रमाण समाचारों का स्वागत है। आप सुझाव या शिकायत भी भेज सकते हैं। संपर्क/व्हाट्सएप 82925 53444 विज्ञापन देने या अखबार प्राप्त करने के लिए संपर्क +91 82923 73444 कार्यकारी संपादक।

सदन में ध्वनिमत से अनुपूरक बजट पारित, बोले मंत्री राधाकृष्ण

सरकार के खजाने में पैसे की नहीं है कोई कमी

नवीन मेल संवाददाता

रांची। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन वाद-विवाद के बाद ध्वनिमत से 7,721.25 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पारित हो गया। भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने कटौती प्रस्ताव लाया था। लेकिन सरकार के जवाब के दौरान भाजपा विधायकों ने सदन से वॉक आउट कर दिया। हेमलाल मुर्मू, बाबूलाल मरांडी, सुरेश बैठा, अरुप चटर्जी, सुरेश पासवान, सरयू राय, जनार्दन पासवान, निर्मल कुमार महतो, जयराम महतो, समीर कुमार मोहंती, सीपी सिंह और राजेश कच्छप ने चर्चा में भाग लिया। कई सदस्यों ने वित्तीय प्रबंधन को लेकर विचार साझा किए। भाजपा की ओर से सरकार को वित्तीय मोर्चे पर फ्लॉप बताया गया। कटौती प्रस्ताव लाने वाले नवीन जायसवाल ने सरकार को सात वचन याद दिलाते हुए फ्लॉप करार दिया।

वित्त मंत्री ने पेश किया वित्तीय ब्योरा : जवाब में संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आंकड़ों के जरिए राज्य की वित्तीय स्थिति बताई। उन्होंने कहा कि खजाने में पैसे की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि 6,554.61 करोड़ रुपए स्कीम हेड का है। इससे कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। बाकी स्थापना मद में 966.64 करोड़ है। ये जरुर वित्तीय भार पड़ेगा। लेकिन ये समझना होगा कि ये मामूली राशि है। इसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। आय के अतिरिक्त श्रोत बढ़ा पर स्थापना मद के पैसे जुटा लिए जाएंगे। मूल बजट का अभी 30 नवंबर तक स्टेट का अपना टैक्स, नॉन टैक्स, सेंट्रल टैक्स में हिस्सेदारी का ब्योरा जानना जरुरी है। दोनों मद में 61,056.12 करोड़ सरकार के खजाने मौजूद हैं। इस दौरान 98.8 प्रतिशत खर्च किया है। इससे अच्छे वित्तीय प्रबंधन का पता चलता है।

शेष पेज 11 पर

केंद्र ने दबा रखे हैं 28,863.64 करोड़ रुपए : वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 47,040 करोड़ रु. है। इसकी तुलना में 30,971 करोड़ मिला है. करीब 16 हजार करोड़ रुपए अभी भी बकाया है। केंद्र से अनुदान 17,057 करोड़ निर्धारित था। इसकी तुलना में मात्र 4,261.70 करोड़ मिला है। दोनों को मिला दें तो झारखंड को 28,863.64 करोड़ रुपए 30 नवंबर तक नहीं मिला है।

वादे पूरे नहीं होने की ये है वजह

वित्त मंत्री ने कहा कि ये लोग कहते हैं कि खजाना खाली हो गया है। राज्य में उज्ज्वला के लाभुकों की संख्या 65 लाख है। अगर हम 450 रुपए के हिसाब से उन्हें देते हैं तो एक माह में एक सिलेंडर के हिसाब से एक साल में 2,100 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। हम इसके लिए तैयार हैं। बशर्ते, केंद्र सरकार हमारा बकाया दे दे। जल जीवन मिशन केंद्र ने शुरु की। हमारी सरकार 6,300 करोड़ राज्यांश देने को तैयार थी। भारत सरकार कहती है कि हम ये पैसा नहीं देंगे। अब ये लोग कहते हैं छात्रवृत्ति नहीं मिलती। जबकि 890 करोड़ रुपए 30 नवंबर तक झारखंड को नहीं मिले हैं। झारखंड को दबाया और कुचला जा रहा है। वृद्धों को भारत सरकार से पैसे देने का प्रावधान है। इस मद में 132 करोड़ देना था जो नहीं मिला।

बालू के मुद्दे पर सदन हुआ गर्म, मंत्री ने कहा

374 घाटों पर 100 रु प्रति सीएफटी उपलब्ध है बालू

रांची। झारखंड विधानसभा के शीताकलीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन बालू के मुद्दे पर गर्म रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर बहस हुई। अल्पसूचित प्रश्न के तहत भाजपा के विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने झारखंड में बालू की किल्लत का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पलामू जिले में बालू के व्यवसाय को थाना के जरिए मैनेज किया जा रहा है। लोगों को दूसरे राज्यों से विवश होकर महंगी दर पर बालू मंगाना पड़ रहा है। इसके जवाब में विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पेसा कानून की घोषणा तक बालू घाटों से बालू के उठाव पर रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जनहित में राज्य के 374 घाटों पर 100 रुपए प्रति सीएफटी बालू लोगों को उपलब्ध करा रही है। उन्होंने बताया कि ऐसे 71 बालू घाट पलामू में भी हैं। मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जनता के प्रति संकल्पित है।

शेष पेज 11 पर

थैलिसिमिया के पीड़ित बच्चों पर सदन में हुई चर्चा

इलाज के लिए सरकार 14 लाख वहन करेगी : मंत्री

रांची। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य सरकार झारखंड के थैलिसिमिया से पीडित बच्चों को आयुष्मान योजना के तहत अन्य राज्यों की तर्ज पर 14 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च वहन करेगी। मंत्री ने यह बातें मंगलवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव के सवाल के जवाब में कही। प्रदीप यादव ने यह मामला ध्यानाकर्षण की सूचना के तहत उठाया था। जवाब में मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के पास झारखंड में थैलिसिमिया और सिकल सेल जैसी बीमारियों से पीड़ित बच्चों का कोई सर्वे रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। लेकिन सरकार ऐसे पीड़ित बच्चों का सर्वे कराएगी और मरीजों के हित में सदर

शेष पेज 11 पर

झारखंड शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई

दुमका में श्रवण जालान के रिश्तेदार के घर पर एसीबी ने की छापेमारी

नवीन मेल संवाददाता

रांची। झारखंड शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने दुमका में बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार की सुबह एसीबी की एक टीम विनय चौबे के करीबी माने जा रहे व्यवसायी श्रवण जालान के एक करीबी रिश्तेदार नवीन पटवारी के आवास पर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक, नवीन पटवारी और उनके तीन भाई इसी आवास में रहते हैं। कार्रवाई के दौरान पटवारी के आवास के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है और आवास के चारों ओर बैरिकेडिंग की गई है। विनय चौबे के करीबी और रांची के चर्चित व्यवसायी श्रवण जालान के घर व ऑफिस में एसीबी ने सोमवार को छापेमारी की थी। इस दौरान एसीबी को अलग-अलग कंपनी के दो-तीन मोबाइल फोन और जमीन से संबंधित दस्तावेज के अलावा कुछ डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। एजेंसी फिलहाल मोबाइल फोन और डिजिटल साक्ष्य को खंगालने में जुटी हुई है।

छापेमारी के दौरान श्रवण जालान अपने आवास पर मौजूद नहीं थे। जब तक रेड चलती रही, तब तक वह अपने घर और कार्यालय नहीं आए। ऐसे में अब एसीबी उन्हें नोटिस जारी कर सकती है। आशंका जताई जा रही है कि एसीबी जल्द ही श्रावण जालान को पूछताछ के लिए समन जारी करेगी। जिस मामले में श्रवण जालान के ठिकानों पर रेड हुई है, वह विनय चौबे से जुड़ा शराब घोटाला केस है। एसीबी को इस बात की जानकारी मिली है कि विनय चौबे ने अपनी अवैध कमाई का एक बड़ा हिस्सा श्रवण जालान के माध्यम से अलग-अलग जगहों पर इन्वेस्ट किया है। इससे पहले एसीबी की टीम ने रविवार को विनय चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता से 10 घंटे तक पूछताछ की थी।

शेष पेज 11 पर

शराब घोटाले में होटवार जेल में बंद आरोपियों से एसीबी ने की पूछताछ

रांची। झारखंड शराब घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, उससे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूछताछ किया। मंगलवार को ईडी की टीम होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार पहुंची, जिसके बाद ईडी की टीम ने महेश सीताराम, परेश ठाकोर, विक्रम ठाकोर, बिपिन जाधवभाई परमार और जगन ठाकोर देसाई से पूछताछ की है। उल्लेखनीय है कि ईडी ने पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में आवेदन देकर शराब घोटाले के उन अभियुक्तों से पूछताछ की अनुमति मांगी थी, जिसे एसीबी ने कांड संख्या 9/25 में गिरफ्तार किया है और वे फिलहाल बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। कोर्ट के द्वारा अनुमति देने के बाद ईडी ने जेल में पांच लोगों से पूछताछ किया। ईडी की ओर से कोर्ट में दिए गए आवेदन में कहा गया था कि एसीबी द्वारा पीई-3/2024 शेष पेज 11 पर

पूर्व उत्पाद आयुक्त आईएएस अमित कुमार से एसीबी ने की पूछताछ

रांची। शराब घोटाले की जांच कर रही एसीबी ने पूर्व उत्पाद

आयुक्त व वर्तमान में वाणिज्य कर आयुक्त अमित कुमार से मंगलवार को तकरीबन पांच घंटे से अधिक पूछताछ की। मंगलवार को 11 बजे अमित कुमार एसीबी कार्यालय पहुंचे थे, जहां केस के जांच पदाधिकारी ने उनसे सवाल जवाब किया। इससे पहले पांच दिसंबर को भी एसीबी ने अमित कुमार से पूछताछ की थी। तब एजेंसी अमित कुमार से शराब नीति के निर्माण, शराब कारोबार के लिए छत्तीसगढ़ की सरकारी कंपनी छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (सीएसएमसीएल) के एमडी अरुणपति त्रिपाठी को झारखंड में शराब कारोबार के सलाहकार नियुक्त करने व मानव संसाधन प्रदाता कंपनियों के चयन से जुड़े सवाल पूछे गए। मंगलवार को हुई पूछताछ के दौरान अमित कुमार ने कंपनियों के चयन से लेकर नीति निर्माण के विषय में एसीबी के समक्ष कुछ दस्तावेज पेश किए। आगे भी एसीबी अमित कुमार से पूछताछ कर सकती है। शेष पेज 11 पर

इंडिया | बाल विवाह से टूटते परिवार और जूझता बेखबर समाज

सुनील बादल
कार्यकारी संपादक

कभी बाल विवाह एक मजबूरी थी और आज एक कुप्रथा जो कम तो हुई पर समाप्त नहीं हुई।समाज सरकार और हम सभी की जिम्मेदारी है कि भूमिक दर्शक न बनें पर दोषी कौन है ? कुछ पुराने रीति रिवाज विकसित बनते भारत के कदम आज भी रोक रहे हैं जिसमें बचपन को लीलता बाल विवाह भी है जिसके कारण अनेक परिवार अवस्थ कुपोषित मां और बच्चे के जन्म से लेकर युवा होते तक अपने और समाज के लिए समस्याएं उत्पन्न करते हैं जिस कारण भारत सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है। यह देर से उठाया गया पर सही कदम है जिसकी सफलता से इससे जुड़ी अनेक समस्याओं की श्रृंखला का अंत हो सकता है । खनिज और प्राकृतिक संपदा से भरपूर होने के बावजूद झारखंड राज्य की गिनती देश के पिछड़े राज्यों में होती है जिसके मूल में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियां हैं । 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड में 3 लाख 58 हजार 64 लोगों का बाल विवाह हुआ जो कि पूरे देश के बाल विवाह का 3 प्रतिशत है। बाल विवाह के मामले में देशभर में झारखंड का 11वां स्थान है। यह आंकड़ा राज्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के नए आंकड़े के भी अनुसार देश में 20 से 24 साल की उम्र की 23.3 प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं जिनका बाल विवाह हुआ था । आंकड़े के अनुसार प्रदेश में साल 2019 में तीन, साल 2020 में तीन और साल 2021 में चार मामले ही बाल विवाह के दर्ज किए गए क्योंकि पुलिस में शिकायत ही नहीं की गई । लड़की की 18 वर्ष से पूर्व और लड़कों की 21 वर्ष से पूर्व विवाह विवाह बहुत पहले से कानूनन जुर्म है पर लोग इस सामाजिक बुराई के प्रति आंखें मूंदकर बैठे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़की जितनी जल्दी अपने घर चली जाए तो उनकी जिम्मेदार खतम । विवाह में अधिक खर्च आता है, जिससे बचने के लिए कई परिवार वाले अपने बच्चों का बाल विवाह कर देते है। घर में एक शादी तय होती है तो, मां-बाप सोचते हैं कि इसी के

एआई जेनरेटेड

साथ दूसरे बच्चे की शादी कर दी जाए। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि बच्चों की आयु क्या है। कुछ लोग मानते हैं कि असुरक्षा के कारण बाल विवाह प्रथा की शुरुआत हुई थी जब विदेशी आक्रमणकारी लूटपाट करने आते थे या चिकित्सा पद्धति ऐसी नहीं थी कि जीवन की गारंटी हो जिस कारण जल्दी से जल्दी हाथ पीले करने का दबाव बड़े बुजुर्गों का होता था । पर आज अपवादों को छोड़ दिया जाए तो दोनों कारण नहीं हैं जिस कारण बाल विवाह कम हुए हैं पर समाप्त नहीं हुए । कम आयु में विवाह से सदा बीमार रहने वाली मां और बच्चे दोनों घरेलू कलह के कारक बनते हैं जिससे कई बार तलाक तक हो जाते हैं क्योंकि लड़की का शरीर पूर्ण विकसित नहीं होने के कारण मां की भूमिका के साथ बहू की ज़िम्मेदारी नहीं निभा पाती । इस क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं का मानना है कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियां बाल विवाह के मामलों में गंभीरता बरते और सख्त कदम उठाए । बाल विवाह के मामले में अनिवार्य एफआईआर दर्ज करने, बाल विवाह को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पोक्सो एक्ट से जोड़ने का प्रावधान हो । हर जिले में बाल विवाह रोकने वाले अधिकारी (सीएमपीओ) की नियुक्ति हो और अधिकारियों को बाल विवाह रोकने के लिए उचित प्रशिक्षण देने के अलावा अभिभावकों को इसकी बुराई से अवगत किया जाए विरोध के स्वर यदि कहीं से उठें तो समाज को आगे आना चाहिए न कि आँखें मूंद लेना ।

विभागों को ठोस कदम उठाने का निर्देश

रांची के हालात सुधारने के लिए हाईकोर्ट ने बनाई उच्च स्तरीय कमेटी

नवीन मेल संवाददाता

रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने रांची की हालत पर चिंता जताते हुए सरकार व संबंधित विभागों को ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि रांची की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए सभी हितधारकों को एक मंच पर लाना आवश्यक है। इसके लिए अदालत ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि समिति की पहली बैठक दस दिसंबर शाम पांच बजे महाधिवक्ता राजीव रंजन के कार्यालय में आयोजित की जाए। अदालत ने अपेक्षा जताई कि समिति के सभी सदस्य बैठक में स्वयं उपस्थित रहेंगे। अगर बैठक में कोई सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं तो इस स्थिति में वर्चुअल उपस्थिति की अनुमति दी गई है।

झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने दाखिल की है जनहित याचिका : मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को निर्धारित की गई है। अदालत की ओर से गठित उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता महाधिवक्ता राजीव रंजन करेंगे। शेष पेज 11 पर

धान के एमएसपी को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला, विस परिसर में की नारेबाजी

नवीन मेल संवाददाता

रांची। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को सदन परिसर सरकार विरोधी नारों से गूंज उठा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों ने राज्य की विधि-व्यवस्था और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के मुद्दे पर सरकार को कठघरे में खड़ा किया।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों से वादा पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को 3200 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीद का आश्वासन दिया गया था, जबकि कैबिनेट ने सिर्फ 2450 रुपये का एमएसपी पास किया। इसे उन्होंने किसानों के साथ वादाखिलाफी बताया।

भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने भी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि धान खरीद की दर देर से तय की गई और जो वादा किया गया था उसे पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि किसानों को मजबूरन औने-पौने दामों में धान बेचना पड़ रहा है।

भाजपा की विधायक नीरा यादव ने आरोप लगाया कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की विधि-व्यवस्था इतनी खराब है कि सरकारी अस्पताल में चोरी तक हो रही है और मंत्री इसे मानते हुए भी असहज महसूस करते हैं।

विपक्ष की लगातार आवाज के बीच सत्ता पक्ष सरकार का बचाव करता दिखा। खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि किसानों से किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि धान खरीद को लेकर जो एमएसपी तय करने की प्रक्रिया है, वह पूरी की जाएगी और अनुपूरक बजट में इसके लिए राशि का प्रावधान भी किया गया है।

विपक्ष पर हमला करते हुए कच्छप ने कहा कि भाजपा जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है।

विस अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव पर जताई नाराजगी

रांची। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मंगलवार को कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव पर विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने नाराजगी जताई। अध्यक्ष ने कहा कि प्रदीप यादव बार-बार सवाल पूछकर अन्य सदस्यों का समय खराब कर रहे हैं। अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव से कहा कि विधानसभा केवल उनके सवालों के लिए नहीं है और अन्य सदस्यों को भी मौका मिलना चाहिए। उन्होंने विधायक को याद दिलाया कि वे एक जवाबदेह सदस्य हैं और उन्हें दूसरों के समय का भी सम्मान करना चाहिए। दरअसल, प्रदीप यादव ने ध्यानाकर्षण सूचना के तहत झारखंड में थैलिसिमिया और सिकल सेल जैसी घातक बीमारियों पर सवाल उठाए थे। वे विभागीय मंत्री इरफान अंसारी से कई जवाब जानना चाहते थे, लेकिन मंत्री के उत्तर से संतुष्ट न होने के कारण वे बार-बार सवाल पूछते रहे। इस पर अध्यक्ष ने उन्हें टोका।

बाबूलाल मरांडी ने उठाया एमबीबीएस नामांकन में गड़बड़ी का मामला

रांची। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एमबीबीएस नामांकन में कथित अनियमितताओं का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि राज्य में मेडिकल एडमिशन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हो रही हैं। मेडिकल काउंसलिंग के दौरान झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड (जेसीईसीबी) मेडिकल काउंसलिंग कमिटी (एमसीसी) की निर्धारित गाइडलाइन का पालन नहीं करता। मरांडी ने कहा कि एनटीए परीक्षा के बाद परिणाम जारी कर जेसीईसीबी को भेजता है, लेकिन एनटीए पोर्टल से सही तरीके से लिंक न होने के कारण काउंसलिंग प्रक्रिया में कई अनियमितताएं सामने आती हैं। उन्होंने दावा किया कि इस खामी का फायदा उठाकर कुछ छात्र गलत जाति, आवासीय प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज जमा कर देते हैं, जिससे कई योग्य छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि यह गड़बड़ियां जानबूझकर की जाती हैं, ताकि कुछ लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने राज्य सरकार से जेसीईसीबी के शीर्ष अधिकारियों को तत्काल हटाने, मौजूदा काउंसलिंग प्रक्रिया को रद्द कर पुन: संचालित करने और मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। मरांडी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार इस विषय पर शीघ्र कार्रवाई नहीं करती है, तो विपक्ष सदन की कार्यवाही बाधित करेगा।

अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन की टीम विरोध के बाद लौटी

रांची। रिम्स के अवैध हिस्से से अतिक्रमण हटाने मंगलवार को भी प्रशासन और रिम्स की टीम पहुंची। मंगलवार को डीआईजी ग्राउंड के आसपास के हिस्से से अतिक्रमण हटाया जाना था। रिम्स के पास तालाब के बगल वाले हिस्से में जब टीम पहुंची तो लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। अवैध तरीके से निर्मित अपार्टमेंट की बाउंड्री को पहले गिराया गया, उसके बाद टीम रुक गई। लोगों ने अपार्टमेंट को भी पूरी तरह से ध्वस्त करने की मांग कर रहे थे। लोगों का कहना था कि प्रशासन पहले इस अवैध अपार्टमेंट को हटाए, उसके बाद अन्य अवैध निर्माण को तोड़े। लोगों के विरोध के बाद प्रशासन ने काफी देर तक समझाने की कोशिश की, उसके बाद लौट गए। विरोध के कारण तालाब के किनारे और डीआईजी वाले हिस्से में एक भी अवैध निर्माण नहीं हटाया जा सका।

सरकार ने 1932 आधारित नियोजन नीति पर भी जनता को ठगा : प्रतुल

नवीन मेल संवाददाता

● 75% ठेका स्थानीय लोगों को देने के वादा भी नहीं हुआ पूरा

रांची। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने कहा कि 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति का वादा कर हेमंत सोरेन ने झारखंड के आदिवासी मूलवासी को ठगने का काम किया है और यह सरकार वास्तविक में ठगुआ सरकार है। झारखंड की जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि छह वर्ष की लंबी सत्ता के बाद भी हेमंत सोरेन सरकार एक भी स्थानीय नियोजन नीति क्यों नहीं ला सकी। आज तक न कटऑफ डेट घोषित हुई, न खतियान आधारित नीति बनी, न युवाओं को कोई ठोस रास्ता मिला। यह सरकार केवल आश्वासन देती है, और फिर उसपर मौन साध लेती है।

प्रतुल ने कहा कि यह वही हेमंत सोरेन हैं जिन्होंने 1932 के खतियान आधारित नीति के मुद्दे पर 2012 में अर्जुन मुंडा सरकार से समर्थन वापस लेकर बड़ा नाटक किया था। तब यह उनके लिए "असली जनभावना" थी। लेकिन आज, छह वर्षों तक मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बावजूद, नीति के नाम पर शून्य उपलब्धि—इससे बड़ा विडंबनापूर्ण उदाहरण कोई नहीं हो सकता। प्रतुल ने कहा कि सच यह है कि हेमंत सरकार की मंशा नहीं, सिर्फ़ माला–जपने वाली मुनादी है। झारखंड के बेरोजगार युवाओं को भरमाने का खेल अब खुलकर सामने आ चुका है।प्रतुल ने कहा कि खतियान आधारित नियोजन पर सरकार बार–बार जनता को गुमराह कर रही है। छह वर्षों में फ़ाइलें धूल झाड़ती रहीं और सरकार भाषण झाड़ती रही।राज्य के युवा पूछ रहे हैं कि 2012 में जिस नीति पर समर्थन वापस लिया, 2025 तक उसी नीति पर काम क्यों नहीं किया?

प्रतुल ने कहा कि वोट लेने के लिए हेमंत सरकार ने आदिवासी मूलवासियों के लिए बड़े-बड़े वादे किए थे जिसमें 75% ठेका स्थानीय लोगों को देने का भी जिक्र था। लेकिन सरकार में आते ही जहांपनाह के सुर बदल गए और अब तो टेंडर में ऐसी कंडीशन रखे जा रहे हैं जिससे स्थानीय कंपनियां हिस्सा ही नहीं दे सकती। यू टर्न करने में इस ठगुआ सरकार का कोई सानी नहीं।

हेमंत सरकार स्थानीय समुदायों के हितों के लिए प्रतिबद्ध : झामुमो

नवीन मेल संवाददाता

रांची। भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों पर झामुमो ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि भाजपा सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए भ्रामक बातें फैलाने में लगी है, जबकि हेमंत सोरेन सरकार राज्यहित में ठोस और संवेदनशील कदम उठा रही है। विनोद पांडेय ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा-भाजपा नेताओं को पहले यह बताना चाहिए कि 18 वर्षों के लंबे शासनकाल में उसने खतियान आधारित स्थानीय नीति पर क्या काम किया? जिन मुद्दों पर आज सवाल उठाए जा रहे हैं, उन्हीं पर भाजपा की सरकारें वर्षों तक चुप क्यों रहीं? उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने स्थानीय युवाओं के रोजगार, पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया और सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से काम किया है। नीति निर्माण एक संवैधानिक प्रक्रिया है। सरकार ने इसे जिम्मेदारी से आगे बढ़ाया है। यह जग जाहिर है कि भाजपा नेता झारखंड के विकास और यहां की अस्मिता से जुड़े हेमंत सरकार के फैसलों को अटकाने का काम करते हैं। 75% ठेका स्थानीय लोगों को देने के मुद्दे पर विनोद पांडेय ने कहा कि भाजपा तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश कर रही है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि स्थानीय ठेकेदारों और उद्यमियों को अधिक अवसर मिले। प्रक्रियाओं को सक्षम, पारदर्शी और व्यावहारिक बनाने के लिए सुधार किए जा रहे हैं। भाजपा बिना तथ्यों की जांच किए दिग्भ्रमित करने के लिए सोच-समझ कर बयान दे रही है। विनोद पांडेय ने कहा कि राज्य सरकार झारखंडी युवाओं और स्थानीय समुदायों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और भाजपा सिर्फ राजनीति के लिए अनावश्यक विवाद पैदा कर रही है। जनता सब देख रही है और झूठे आरोपों से गुमराह नहीं होगी।

चिकित्सा शिखर सम्मेलन की तैयारियों का हुआ शुभारंभ

झारखंड में सशक्त होम्योपैथिक अनुसंधान पर विशेष फोकस

नवीन मेल संवाददाता

रांची। द्वितीय डब्ल्यूएचओ वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन 2025 की तैयारियों के तहत नई दिल्ली में आयोजित कर्टेन-रेजर कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने बताया कि भारत पारंपरिक चिकित्सा में वैश्विक नेतृत्व निभा रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन 17-19 दिसंबर 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) द्वारा झारखंड की राजधानी रांची स्थित होम्योपैथिक नैदानिक अनुसंधान इकाई (सीआरयू) के योगदान को विशेष रूप से रेखांकित किया गया। यह इकाई 1984 से साक्ष्य आधारित होम्योपैथिक अनुसंधान और जनस्वास्थ्य सुधार के लिए कार्यरत है।

रांची इकाई रोग-विशिष्ट अनुसंधान, क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन और वैश्विक मानकों पर आधारित अनुसंधान प्रोटोकॉल के माध्यम से होम्योपैथी को एक सुरक्षित, प्रभावी और किफायती चिकित्सा प्रणाली के रूप में सशक्त बना रही है। यहां की ओपीडी सेवाएं प्रतिवर्ष हजारों रोगियों, विशेषकर ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों के मरीजों को लाभान्वित करती हैं।

इकाई द्वारा जीवनशैली रोग, महिला व बाल स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, कुपोषण, श्वसन रोग, माँ एवं शिशु स्वास्थ्य, स्वच्छता और कोविड जैसे विषयों पर अनुसंधान एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। साथ ही "स्वस्थ बच्चों के लिए होम्योपैथी (एचएचसीपी)" और "एससीपीएस स्वास्थ्य शिविर" जैसी सार्वजनिक पहलें समुदाय में सकारात्मक परिवर्तन ला रही हैं।

इकाई के प्रभारी अधिकारी डॉ. सुनील प्रसाद ने कहा कि "हमारा उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ उच्च गुणवत्ता वाला होम्योपैथिक शोध करना है, ताकि इस चिकित्सा प्रणाली का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सके।" रांची स्थित यह अनुसंधान इकाई, अपनी सतत शोध गतिविधियों, रोगी सेवाओं और जनस्वास्थ्य में योगदान के माध्यम से झारखंड ही नहीं, बल्कि पूरे पूर्वी भारत में होम्योपैथिक अनुसंधान की अग्रणी संस्था बन चुकी है।

भारतीय खो-खो महासंघ ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात

कॉमनवेल्थ खो-खो प्रतियोगिता से कराया अवगत

नवीन मेल संवाददाता

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को झारखंड विधानसभा में भारतीय खो-खो महासंघ (केकेएफआई) के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर कॉमनवेल्थ खो-खो महासंघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष आगामी 9 से 14 मार्च 2026 तक रांची में आयोजित होने वाली प्रथम कॉमनवेल्थ खो-खो प्रतियोगिता के आयोजन संबंधी विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार-विमर्श किया और राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। ज्ञात हो कि वर्ष 2026 में झारखंड को एक ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी मिलने जा रही है। यह प्रतियोगिता झारखंड की धरती पर आयोजित होने वाली पहली अंतरराष्ट्रीय खो-खो स्पर्धा होगी, जिसमें 23 देशों के बालक एवं बालिका वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री से भेंट करने वाले प्रतिनिधिमंडल में कॉमनवेल्थ खो-खो महासंघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल, अंतरराष्ट्रीय तकनीकी सचिव एमएस त्यागी तथा महासचिव उपकार सिंह विरक शामिल थे। राज्य स्तरीय प्रतिनिधियों में विधायक एवं झारखंड राज्य खो-खो संघ के महासचिव मथुरा प्रसाद महतो, संरक्षक विधायक सीपी सिंह, संघ के चेयरमैन संतोष प्रसाद, महासचिव नवीन कुमार ठाकुर, उपाध्यक्ष विनय कुमार जायसवाल, संयुक्त सचिव आलोक कुमार, डॉ. सुभाष साहू, रोहित कुमार सिंह, रांची जिला सचिव सुनील कुमार यादव, संयुक्त सचिव रवि मुंडा, मोनू शुक्ला, अमित कुमार यादव एवं तपन राउत उपस्थित थे।

झारखंड हाईकोर्ट ने कैलाश कोठी तोड़ने पर लगाई रोक

दस्तावेज सत्यापित करने का दिया निर्देश

नवीन मेल संवाददाता

रांची। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में डीआईजी ग्राउंड के निकट स्थित कैलाश कोठी तोड़ने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने कैलाश कोठी को तोड़ने पर रोक लगा दी।

कोर्ट ने मामले में रांची उपायुक्त को प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किए गए दस्तावेज का सत्यापन करने का निर्देश दिया है। अदालत ने डीसी से पूछा है कि दस्तावेज के आधार पर बताएं कि उक्त जमीन का अधिग्रहण किया है या नहीं। अगर इस जमीन का रिम्स ने अधिग्रहण किया है तो उसके मुआवजा का भुगतान किया गया है या नहीं? सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से बताया गया कि अवैध अतिक्रमण बताते हुए कैलाश कोठी को हटाने का नोटिस चिपकाया गया है। लेकिन इस जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया था। प्रार्थी ने कैलाश कोठी का स्वामित्व दस्तावेज भी कोर्ट में प्रस्तुत किया। बताया गया कि यह कोठी जिस जमीन पर बनी है, उसका रिम्स ने अधिग्रहण ही नहीं किया है। इस संबंध में प्रार्थी खुशबू सिंह की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। बता दें कि हाई कोर्ट ने पिछले दिनों एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान रिम्स परिसर के निकट के अतिक्रमण को 72 घंटे के भीतर हटाने का आदेश दिया है। इस आदेश के आलोक में रिम्स परिसर के आसपास का अतिक्रमण को जिला प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है।

अस्पताल कर्मी ने की आत्महत्या, एक पर केस

रांची। बूटी मोड़ स्थित एक अस्पताल में काम करने वाली विद्यांचल गुड़िया ने फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। उसका शव किराए के एक मकान में फंदे से लटका मिला। मामले में सदर थाना में एक युवक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। गया निवासी नरेंद्र कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। कहा कि उनकी बहन किराए के मकान में कमरा लेकर रहती थी। सोमवार को पता चला कि उनकी बहन फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली है। मकान मालिक से बातचीत में पता चला कि एक काला जैकेट पहने युवक सोमवार को पहुंचा और मृतका के कमरे का दरवाजा खटखटाया। लेकिन, दरवाजा नहीं खुला। खिड़की से देखने पर पता चला कि विद्यांचल फंदे से झूल रही है। आनन-फानन में दरवाजा तोड़कर लड़का घुसा और उसे अस्पताल ले गया, जहां पर मौजूद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

हटिया रेलवे स्टेशन से 23 किलो गांजा बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

नवीन मेल संवाददाता

रांची। आरपीएफ ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हटिया रेलवे स्टेशन से 23 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। इस कार्रवाई में बिहार के पश्चिमी चंपारण के रहने वाले दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आरपीएफ से मिली जानकारी के अनुसार, कमांडेंट पवन कुमार के निर्देश पर हटिया स्टेशन परिसर में संयुक्त जांच अभियान चलाया गया। इसी दौरान ड्यूटी पर मौजूद उपनिरीक्षक संतोष कुमार सिंह और फ्लाइंग टीम ने प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध रूप से बैठे दो व्यक्तियों को रोका और उनकी तलाशी ली। जांच में उनके बैगों से चार पैकेटों में बंद कुल 23 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी बाजार कीमत लगभग 11.50 लाख रुपए आंकी गई है। आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त अशोक कुमार सिंह की उपस्थिति में जब्त किए गए पैकेटों की डीडी किट से जांच की गई, जिसमें गांजा होने की पुष्टि हुई। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए बरामद सामग्री और दोनों आरोपितों को आगे की कार्रवाई के लिए जीआरपी हटिया को सौंप दिया गया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान मोहम्मद फिरोज और राम बिलास चौधरी के रूप में हुई है।

न्यूज बॉक्स

प्रधानमंत्री मोदी से मिले प्रदेश भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू

रांची। भाजपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सांगठनिक, राजनीतिक विषयों पर चर्चा की,मार्गदर्शन प्राप्त किया।

दो सेवानिवृत्त एसीएफ की सेवा विस्तार की मांग वाली याचिका खारिज

रांची। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मंगलवार को दो सेवानिवृत्त सहायक वन संरक्षक अधिकारियों (एसीएफ) की एक साल की सेवा विस्तार देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नौकरी में विस्तार देना समाधान नहीं है और न ही इसे नियम बनाया जा सकता है। हाईकोर्ट ने इस तरह की मांग को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की तिथि से भलीभांति अवगत रहती है और उसे इसकी पहले से ही योजना बनानी चाहिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि सेवानिवृत्ति से पहले ही राज्य सरकार को उस पद को भरने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए, जो कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से खाली होने वाली है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में राज्य ने पद भरने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवा विस्तार देकर कार्य जारी रखने की अनुमति दी है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विस्तार देना संस्था के विकास के लिए ठीक नहीं है।

2450 रुपए में बोनस के साथ धान की खरीदारी गलत : पवन साहू

रांची। भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने कहा कि झारखंड की कैबिनेट ने निर्णय लिया की धान की खरीदारी 2450 रुपए में बोनस के साथ किया जाएगा। यह हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा सरासर अन्याय व गलत है। सरकार इस तरह से किसानों के साथ अन्याय नहीं कर सकती है। विधानसभा चुनाव के समय हेमंत सोरेन सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था, झारखंड में सरकार बनने पर धान की खरीदारी 3200 में किया जाएगा। किसानों ने लालच में आकर बढ़ चढ़कर झामुमो को वोट दिया। सरकार बनते हीं अपना रंग दिखाना हेमंत सोरेन शुरू कर दिया। आज राज्य में बिचौलियों के द्वारा धान की खरीदारी 1700 से 1800 रुपए में कर रही है। हेमंत सोरेन के उदासीनता के कारण धान का क्रय केंद्र अभी तक चालू नहीं हो पाया है। सरकार जल्द से जल्द अपने निर्णय पर पुनः विचार करते हुए किसानों के साथ न्याय करे। धान की खरीदारी 3200 में करें। 2450 रुपए में बोनस के साथ धान की खरीदी के घोषणा के बाद किसान आक्रोशित हैं। भाजपा किसान मोर्चा इस निर्णय का पूरजोर विरोध करती है। किसानों के साथ भाजपा किसान मोर्चा खड़ा है। यह जानकारी भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश मीडिया प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने दी।

जनता के बुनियादी सवालों से मुंह मोड़ रही है भाजपा : विजय शंकर नायक

रांची। झारखंड का शीतकालीन सत्र जिस तरह भाजपा के हंगामे की भेंट चढ़ गया, वह लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधी चोट है। यह केवल सदन की कार्यवाही बाधित होने का मामला नहीं, बल्कि झारखंड की करोड़ों जनता की उम्मीदों और अधिकारों की हत्या है। झारखंड के शीतकालीन सत्र का हंगामे में समाप्त होना लोकतंत्र और जनता-दोनों के साथ सीधा विश्वासघात है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब राज्य के गरीब, मजदूर, किसान, युवाओं और आदिवासी–मूलवासी समाज के सामने बेरोजगारी, महंगाई, पेयजल संकट, सड़क–बिजली–स्वास्थ्य जैसी बुनियादी समस्याएँ खड़ी हैं, तब सदन को जवाबदेही का मंच बनाने के बजाय भाजपा ने उसे जानबूझकर मछली बाजार बना दिया है। उपरोक्त बातें आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच के केंद्रीय उपाध्यक्ष विजय शंकर नायक ने कही। उन्होने कहा कि भाजपा का काम अब मुद्दों पर बहस करना नहीं, बल्कि सदन को ठप कराकर जनता की आवाज को दबाना बन गया है।

छात्र अधिकार पदयात्रा विधानसभा पहुंचने से पहले रोकी गई

रांची। छात्र हित और शिक्षा से संबंधी मुद्दों को लेकर डुमरी से निकाली गई छह दिवसीय छात्र अधिकार पदयात्रा मंगलवार को अंतिम चरण में रांची पहुंची। इसका नेतृत्व जेएलकेएम नेता देवेंद्रनाथ महतो ने किया। इसमें बड़ी संख्या में छात्र, युवा प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। विधानसभा की ओर बढ़ रही पदयात्रा को सुरक्षा बलों ने विधानसभा परिसर से पहले ही बैरिकेडिंग कर रास्ता बंद कर दिया। अचानक रोके जाने पर यात्रा में शामिल युवा आक्रोशित हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। पदयात्रा को पुराने विधानसभा भवन तक की ही अनुमति मिली थी। छात्रों का आरोप है कि राज्य में सरकारी नौकरी बहाली, प्रतियोगी परीक्षाओं और छात्रवृत्ति मामलों में लगातार देरी हो रही है। रोजगार की गंभीर स्थिति पर उन्होंने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि छात्रों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए यह यात्रा निकाली गई थी, लेकिन रोकने से आवाज और बुलंद होगी।

रांची जिले के सभी अंचलों में जनता दरबार का हुआ आयोजन

समस्याओं का हुआ त्वरित समाधान कई आवेदनों का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन

नवीन मेल संवाददाता। रांची। उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशानुसार जिले के प्रत्येक अंचल में मंगलवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया। आमजनों की समस्याओं के त्वरित समाधान को प्राथमिकता देते हुए अंचल अधिकारियों, अंचल निरीक्षकों तथा राजस्व कर्मियों की उपस्थिति में बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदनों पर मौके पर ही कार्रवाई की गई।

जनता दरबार में अंचलवार किए गए निष्पादन

- सोनाहातू अंचल में दानाडीह ग्राम की सरला देवी को पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।
- सिल्ली अंचल में छोटा मुरी ग्राम की गुड़ी देवी एवं सुकरामनी देवी को पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र सौंपा गया।
- मांडर अंचल में मौजा ततकुण्डो के ए.के. महतो को केसीसी लोन हेतु भूमि सत्यापन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया। ग्राम बुढ़ाखुखरा के हनीफ मियां तथा कंजिया के लेदा पात्रिक के पंजी-2 में आवश्यक सुधार किया गया।
- ओरमांझी अंचल में नारायण महतो के पंजी-2 में सुधार की कार्रवाई पूर्ण की गई।
- हेहल अंचल में लक्ष्मीनगर निवासी प्रेम कुमार की ऑनलाइन रसीद निर्गत की गई।
- ईटकी अंचल में आवासीय, जाति, आय, केसीसी, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र आदि से संबंधित कुल 84 आवेदनों का त्वरित निष्पादन किया गया।
- खलारी अंचल में विभिन्न प्रमाण पत्र एवं राजस्व कार्यों से संबंधित 34 आवेदनों पर कार्रवाई की गई। सिल्ली में 49, चान्हो में 106, बेड़ो में 143, नगड़ी में 54, रातू में 106, माण्डर में 28 सहित अन्य अंचलों में भी सैकड़ों मामले निपटाये गये।
- जनता दरबार के दौरान जिलों के सभी अंचलों में राजस्व संबंधी कई लंबित मामलों का भी निष्पादन किया गया। अधिकारियों द्वारा तत्परता के साथ की गई इन कार्रवाइयों से आवेदकों को काफी सुविधा हुई और जनता दरबार का उद्देश्य समस्याओं का स्थल पर समाधान कर सफलतापूर्वक पूरा हुआ।
- डीसी मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर आयोजित यह जिलास्तरीय पहल पारदर्शिता, शीघ्रता और उत्तरदायित्व पर आधारित प्रशासनिक दृष्टिकोण का सशक्त उदाहरण है, जो प्रशासन को जनता के और निकट लाने का प्रयास है।

ईटकी में 84, खलारी में 34, सिल्ली में 49, चान्हो में 106, बेड़ो में 143, नगड़ी में 54, रातू में 106, मांडरर में 28 सहित अन्य अंचलों में सैकड़ों आवेदनों का निष्पादन

रोटरी क्लब ऑफ रांची ने मुख्यमंत्री को किया आमंत्रित

नवीन नेल संवाददाता। रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं कल्पना सोरेन से रोटरी क्लब ऑफ रांची के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के क्रम में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को आगामी डिस्ट्रीक्ट कॉन्फ्रेंस "समागम" में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। यह कॉन्फ्रेंस 19 से 21 दिसंबर तक आयोजित की जा रही है। प्रतिनिधिमंडल में क्लब के अध्यक्ष अमित अग्रवाल, अनिल सिंह, रेखा सिंह तथा रश्मि अग्रवाल शामिल थे। मुख्यमंत्री ने कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होने का आश्वासन दिया। उन्होंने रोटरी क्लब के सदस्यों को आगामी तीन दिवसीय सम्मेलन की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी प्रदान कीं।

सीयूजे : क्षमता निर्माण कार्यक्रम ने प्रतिभागियों में जगाई शोध की जिज्ञासा

नवीन मेल संवाददाता। रांची। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग तथा अर्थशास्त्र एवं विकास अध्ययन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित "सामाजिक विज्ञान में मात्रात्मक एवं गुणात्मक शोध विधियां" विषयक दो-सप्ताहिक आईसीएसएसआर-प्रायोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी) के नौवें दिन की शुरुआत उत्साहपूर्ण और चिंतनशील वातावरण में हुई। दिन की शुरुआत प्रार्थना और "आज का विचार" प्रस्तुत करने से हुई, जिसने प्रतिभागियों में नए सीखने के प्रति ऊर्जा भरी। कार्यक्रम निदेशक प्रो. तपन कुमार बसन्तीआ एवं डॉ. संहिता सुचरिता ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और दिन के विशिष्ट वक्ताओं को सम्मानित करते हुए सत्रों की शुरुआत की।

मेटा-विश्लेषण पर सरल और प्रभावी मार्गदर्शन

दिन के अधिकांश सत्र एक्सएलआरआई, जमशेदपुर के प्रोडक्शन, ऑपरेशन्स एवं डिसीजन साइंसेज विभाग के सह प्राध्यापक डॉ. आलोक राज द्वारा लिए गए। अपने पहले सत्र "मात्रात्मक शोध पद्धति: मेटा-विश्लेषण" में उन्होंने बताया कि मेटा-विश्लेषण अलग-अलग शोध अध्ययनों के निष्कर्षों को जोड़कर अधिक ठोस और विश्वसनीय परिणाम देता है। उन्होंने फॉरेस्ट प्लॉट, इफेक्ट साइज, पब्लिकेशन बायस, कोरिलेशन मैट्रिक्स तथा हेट्रोजेनिटी जैसी अवधारणाओं को सरल उदाहरणों से समझाया। साथ ही प्रिस्मा फ्रेमवर्क पर विस्तार से बताते हुए यह स्पष्ट किया कि व्यवस्थित साहित्य समीक्षा के लिए यह कितना जरूरी होता है। सत्र के दूसरे चरण में डॉ. राज ने प्रतिभागियों को आर सॉफ्टवेयर के व्यावहारिक उपयोग का प्रशिक्षण दिया—डेटा इम्पोर्ट, डेटा क्लीनिंग, सांख्यिकीय परीक्षण, ग्राफ निर्माण, रिग्रेशन आउटपुट आदि का लाइव प्रदर्शन किया। उन्होंने कैजुअल इन्फ्रेंस की अवधारणाएं जैसे काउंटरफैक्चुअल, मैचिंग, इंस्ट्रूमेंटल वैरिएबल्स, रेग्रेशन डिस्कॉन्टिन्यूटी व डिफरेंस-इन-डिफरेंसेज (डीआईडी) को सरल शब्दों में समझाया। उन्होंने चेतावनी दी कि गलत मान्यताएं कारण-परक निष्कर्षों को भटका सकती हैं, इसलिए सावधानी और शोध-स्वच्छता बेहद आवश्यक है।

नैचुरलिस्टिक इंक्वायरी, सहभागी शोध और एथनोग्राफी पर डाला गया प्रकाश

दिन का तीसरा सत्र डॉ निरंजन साहू, प्रोफेसर, ग्रामीण प्रबंधन विभाग, एक्सआईएसएस रांची द्वारा लिया गया। उन्होंने बताया कि नैचुरलिस्टिक इंक्वायरी वास्तविक परिस्थितियों में बिना हस्तक्षेप के घटनाओं को समझने का माध्यम है। सहभागी शोध को उन्होंने एक सहयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया, जिसमें समुदाय स्वयं शोध की धुरी बनता है। नृवंशविज्ञान को उन्होंने संस्कृति, व्यवहार और सामाजिक संबंधों की गहन और दीर्घकालिक समझ विकसित करने की प्रक्रिया बताया। अपने फील्ड अनुभवों के उदाहरणों ने प्रतिभागियों को गुणात्मक शोध की वास्तविक दुनिया से जोड़ दिया।

पुस्तक लेखन और पुस्तक समीक्षा पर सारगर्भित कार्यशाला

अंतिम सत्र प्रो. श्रेया भट्टाचार्जी, प्रोफेसर एवं डीन, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेज, सीयूजे द्वारा संचालित था। उन्होंने शैक्षणिक पुस्तक लेखन की संरचना, शैली, नैतिकता और मौलिकता पर प्रकाश डाला। पुस्तक समीक्षा कैसे लिखी जाए—तर्कों का मूल्यांकन, प्रमाणों की जांच, कमियों की पहचान और पुस्तक के समग्र योगदान का विश्लेषण—इन सभी पहलुओं को उन्होंने उदाहरणों के साथ समझाया। इस सत्र ने प्रतिभागियों को अपनी अकादमिक लेखन क्षमता को और निखारने का अवसर दिया।

खादगढ़ा बस टर्मिनल में एमआरएफ सेंटर बनाने के लिए रांची नगर निगम का निरीक्षण

नवीन मेल संवाददाता। रांची

रांची नगर निगम शहर में कचरा मैनेजमेंट को दुरुस्त करने के लिए अलग-अलग जगहों पर एमआरएफ सेंटर बना रहा है, ताकि कचरा आसानी से अलग हो सके और उसका सही तरीके से निपटान किया जा सके। इसी काम को देखते हुए मंगलवार को अपर प्रशासक संजय कुमार खादगढ़ा में भगवान बिरसा मुंडा बस टर्मिनल पहुंचे। यहां MRF सेंटर बनाने के लिए जमीन देखी जा रही है। निरीक्षण के दौरान पता चला कि जिस जगह सेंटर बनना है, वहां कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। इस पर अपर प्रशासक ने साफ कहा कि 7 दिन के अंदर कब्जा खुद ही हटा लें, वरना निगम कार्रवाई करेगा।

इसके अलावा, जिस एजेंसी मेसर्स टीपीएस को एमआरएफ सेंटर बनाना है, उसे 2 दिनों में लेआउट प्लान बनाकर निगम को देने के लिए कहा गया है, ताकि काम जल्दी शुरू हो सके। निरीक्षण के समय सहायक प्रशासक राहुल यादव, पीएमसी के लोग और निगम के अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे।

झारखंड में आनेवाले दिनों में सताएगी ठंड

तापमान में होगा उतार चढ़ाव, चलेगी पछुआ हवा

नवीन मेल संवाददाता। रांची

झारखंड के सभी जिलों में आनेवाले दिनों में ठंड सताएगी। राज्य भर में अगले एक-दो सप्ताह में न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री का उतार-चढाव होगा। यह जानकारी मौसम विभाग ने मंगलवार को दी। विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण पछुआ हवाएं चलेंगी। इसके प्रभाव से आनेवाले दिनों में तापमान में दो डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। इसके बाद अगले दो दिनों के दौरान तापमान में धीरे-धीरे दो से तीन डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है। विभाग के अनुसार 10 से 13 दिसंबर तक राज्य के कई जिलों में सुबह में कुहासा छाया रहेगा, जबकि बाद में मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगी।वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे अधिक तापमान चाईबासा में 27.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं मंगलवार को रांची और आसपास के इलाकों में सुबह से मौसम साफ रहा और दिनभर कनकनी महसूस की गई।

टेंपरेचर अपडेट : मंगलवार को रांची में अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री और न्यूतनतम तापमान 10.6 डिग्री, जमशेदपुर में 26.7 और 10.6 डिग्री, डालटेनगंज में 28.4 डिग्री और 7.3 डिग्री, बोकारो में 24.1 और 10.1 डिग्री और चाईबासा में अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री और न्यानूतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

बस टर्मिनल के आधुनिकीकरण के निर्णय का चैंबर ने किया स्वागत

नवीन मेल संवाददाता। रांची

रांची के तीन प्रमुख बस स्टैंड आईटीआई बस स्टैंड, सरकारी बस डिपो और बिरसा मुंडा टर्मिनल को नेशनल स्टैंडर्ड के अनुरूप आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार के निर्णय का फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्राचार में चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि इस महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी देना सराहनीय कदम है। यह पहल रांची की परिवहन व्यवस्था को एक नई दिशा देगी और राजधानी की छवि को मजबूत करेगी।चैंबर के सह सचिव नवजोत अलंग ने कहा कि बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सुदृढ़ होना न केवल यात्रियों बल्कि व्यापार, पर्यटन और समग्र आर्थिक विकास के लिए भी आवश्यक है। बस स्टैंड पर अत्याधुनिक टर्मिनल, विस्तृत शेल्टर, स्वच्छ प्रतीक्षालय, डिजिटल टिकटिंग, पार्किंग, मेंटेनेंस यार्ड, सुरक्षा व्यवस्था और वाणिज्यिक सुविधाओं का विकास निश्चित रूप से परिवहन तंत्र को गति देगा और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा।

निगम अपने स्वामित्व वाली परिसंपति का तैयार करेगा डिजिटल अभिलेख

रांची। रांची नगर निगम अपने स्वामित्व वाली सभी राजस्व सृजन करने वाली परिसंपत्तियों होर्डिंग साइट्स, बाजार परिसर की दुकानें, बस स्टैंड परिसर, पार्किंग स्थल, वाणिज्यिक उपयोग की इकाई तथा अन्य बंदोबस्ती परिसंपत्ति का क्रमांकन एवं डिजिटल अभिलेखीकरण किया जाएगा। इससे परिसंपत्ति प्रबंधन एवं राजस्व निगरानी की क्षमता को और मजबूत होगा। निगम प्रशासक सुशांत गौरव की अध्यक्षता में मंगलवार को राजस्व सुदृढ़ीकरण, अवैध वाणिज्यिक गतिविधियों पर कार्रवाई और बस स्टैंड, बाजार परिसंपत्तियों के विकास को लेकर समीक्षा बैठक हुई।

मेरी आवाज मेरी पहचान का सिंगर टैलेंट शो में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा

नवीन मेल संवाददाता। रांची

मेरी आवाज मेरी पहचान के तत्वावधान मे सिंगर टैलेंट शो कार्यक्रम का आयोजन धुर्वा में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में 5 से 12 वर्ष एवं 13 से 18 वर्ष के 30 बच्चों ने पनी शानदार गायन से दर्शकों को मंत्रमुक्त कर दिया। इस ऑडिशन कार्यक्रम में निर्णायक की भूमिका में संस्था के संस्थापक गायक कुमार गहलोत एवं संस्था की सचिव गायिका कविता होरो थीं। उन्होंने बताया कि हमारे झारखंड में गायक प्रतिभाएं काफी हैं बस उन्हें खोज कर निखारना की आवश्यकता है और उन्हें सारेगामापा और इंडियन आइडल जैसे मंच प्रदान करवाना है।इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है इसी तरह के 3-4 ऑडिशन कार्यक्रम अन्य स्थानों पर आयोजित कर चुनकर आए गायको के लिए ग्रैंड फिनाले का आयोजन करना। इस ऑडिशन का लगभग 150 अभिभावकों तथा स्थानीय लोगों ने आनंद उठाया और तालियों की गड़गड़ाहट से बढ़ाया। मौके पर इस कार्यक्रम के विशिष्ठ अतिथि के तौर पर समाजसेवी पीसी मंडल, कुंदन कुमार,बिंदु सिंह,मानु तिग्गा,अकील अहमद लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट के प्रभात कुमार राजन,छात्र क्लब में के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवकिशोर शर्मा मौजूदगी रही।

श्याम मंदिर में 182 वां सुंदरकांड व हनुमान चालीसा का हुआ पाठ

नवीन मेल संवाददाता। रांची

श्री श्याम मित्र मंडल द्वारा हरमू रोड के श्री श्याम मंदिर में मंगलवार को 182 वां श्री सुंदरकांड श्री हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया गया। राम सिया राम सिया राम जय जय राम के गायन व बजरंग बली की जय जयकारों से हरमू रोड का श्री श्याम मंदिर गूंज रहा था। मंडल के निर्वतमान महामंत्री विश्वनाथ नारसरिया ने अखंड ज्योति एवं पूजन के सभी कार्य सम्पन्न करवाएं। यजमान सुनील मोदी ने बालाजी महाराज की अखंड ज्योति प्रज्जवलित कर केसरिया पेड़ा गुड़ चना फल का भोग बालाजी महाराज को अर्पित किया। सुनील मोदी ने श्रीरामचरितमानस ग्रंथ की पूजा करके पाठ वाचकों का चंदन वंदन

कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पाठ वाचक मनीष सारस्वत ओम शर्मा ने अपने सहयोगियों के साथ ढोलक ढपली के स्वर के साथ श्री गणेश वंदना कर श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया। श्री सुंदरकांड का संगीतमय पाठ उपस्थित जनों से करवाया गया। भक्तजन श्री हनुमान जी की आराधना में लीन थे। पाठ के मध्य में भजनों का गायन भी किया गया। श्री सुंदरकांड के पाठ के उपरांत पुनः श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके महाआरती करके भक्तजनों को प्रसाद वितरित किया गया। श्रवण ढानढनिया ने चना प्रसाद सेवा पुष्पा देवी पोद्दार ने केसरिया पेडा सेवा मुकेश मित्तल ने गिरिगोला सेवा एवम राजेश जयसवाल ने फल प्रसाद सेवा निवेदित की। इस अवसर पर मंडल के महामंत्री गौरव अग्रवाल उपाध्यक्ष श्रवन ढानढनिया रिषभ कुमार हर्ष कृष्णा अंकित कुमार आदि भक्त उपस्थित थे।

मांडर में आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ने किया कंबल व खिचड़ी वितरण

नवीन मेल संवाददाता

मांडर। आनंद मार्ग प्रचारक संघ, रांची भुक्ति के यूनिवर्सल रिलीफ टीम के तत्वाधान में मंगलवार को मांडर के बूढ़ा खुखरा स्थित प्रोग्रेसिव चिल्ड्रन स्कूल परिसर में सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जरूरतमंद लोगों के बीच कंबलों का वितरण किया गया। साथ ही लगभग 300 लोगों के बीच "नारायणी सेवा" के रूप में खिचड़ी का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र-छात्राओं को कॉपी, पेंसिल एवं बिस्किट भी प्रदान किए गए। साथ ही बच्चों को आध्यात्मिक बातें सिखाई गई एवं योगासन के फायदे भी बताए गए इसके अलावा तांडव और कौशिकी की जानकारी भी दी गई। मौके पर रांची भुक्ति के भुक्ति प्रधान विजय कुमार ने कहा कि आनंद मार्ग की यूनिवर्सल रिलीफ टीम द्वारा लगातार जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक सुविधाएं पहुंच रही हैं। उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी सरकार द्वारा इस टीम का चयन किया जाता है।कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के संचालक शैलवाहन कुमार द्वारा किया गया। इस मौके पर आचार्य मुक्तेश्वरानंद अवधूत, आचार्य सतप्रियानंद अवधूत, अवधूतिका आनंद प्रीति, आचार्या संहिता दीदी, अवधूतिका लोकातिता आचार्या, विजय कुमार, बूधनाथ भगत, उमेश कुमार, धनेश्वर भगत, जय कुमार, रविंद्र प्रसाद, उदय कुमार, प्रवीण कुमार, बबीता देवी, नमिता देवी, सरिता देवी, कलावती देवी, परशुराम प्रसाद, अर्पण जयदेव, संगीता बड़ाइक, पॉलिना खेस सहित कई लोग उपस्थित रहे और कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया।

केशव कृपा छाया फाउंडेशन ने छात्रों के बीच कंबल बांटे, गौ सेवा की

रांची । केशव कृपा छाया फाउंडेशन ने मंगवाकर को भक्तिवेदांत विद्या भवन गुरुकुल में जरूरतमंद विद्यार्थियों और आश्रित लोगों के लिए विशेष सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर फाउंडेशन की ओर से 101 कंबलों का वितरण, 124 लोगों के लिए तीनों समय के भोजन की व्यवस्था तथा गौ माता को गुड़ का भोग लगाकर गौसेवा का संदेश दिया गया। संस्था ने सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन के रूप में 11 हजार की नगद सहायता राशि भी गुरुकुल प्रबंधन को प्रदान की। फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि सेवाभाव ही संस्था का मूल उद्देश्य है और आगे भी ऐसे कार्यक्रम निरंतर जारी रहेंगे।इस अवसर पर फाउंडेशन की अध्यक्ष मीरा अग्रवाल, सचिव सुमिता अग्रवाल, संतोष नथानी, सुनीता उरांव समेत अन्य लोग मौजूद थे।

लोकहित अधिकार पार्टी ने किया कंबल वितरण, सामाजिक न्याय का लिया संकल्प

पिठौरिया । कांके विधानसभा अंतर्गत कोकदोरो पंचायत के बालू गांव में लोकहित अधिकार पार्टी रांची जिला ग्रामीण के अध्यक्ष अशोक राम के नेतृत्व में 100 कंबल अत्यंत पिछड़े और दलित परिवारों के बीच बांटे गए। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण गुप्ता ने सभी लाभुक बुजुर्गों और उपस्थित ग्रामीणों को सामाजिक न्याय और वंचित शोषित उपेक्षित वर्गों को राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित कराने का संकल्प दिलाया।पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हरिनाथ साहू ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि देश स्तरीय सभी स्तर का उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा निःशुल्क लागू कराने, सामाजिक न्याय हेतु जाति जनगणना के साथ जिसकी जितनी संख्या भारी उसको मिले उतनी हिस्सेदारी और आबादी अनुसार पिछड़ों को आरक्षण, माननीयों के तर्ज पर वोटरों मिले वोटर पेंशन सहित खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति, शिक्षा, रोजगार और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के लिए गांव-गांव सदस्यता अभियान माध्यम से लोगों को जागरूक करना पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश महासचिव प्रमोद गुप्ता, महासचिव सूरज यादव, मीडिया प्रभारी अंशु ठाकुर, सहिया देवंती देवी सहित सैकड़ों लोगे मौजूद थे।

न्यूज बॉक्स

बंधु तिर्की ने मदरसा महमुदिया इस्लामिया के बच्चों के बीच किया कंबल का वितरण

मांडर। दिसंबर माह में ठंड का प्रकोप काफी बढ़ गया है। लोग शाम होने से पहले ही अपने घरों में दुबक जाते हैं। सुबह में लोग काफी दिन निकलने के बाद अपने घरों से निकलते हैं। बढ़ती ठंड को देखते हुए पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने शाम मदरसा महमुदिया इस्लामिया सुरसा, मुड़मा, मेशाल में तालीम याफ्ता 200 गरीब बच्चों के बीच कंबल का वितरण किया। मौके पर कांग्रेस अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष शमीम अख्तर, विधायक प्रतिनिधि आबिद अंसारी, हुसैन अंसारी उपस्थित थे।

मांडर में अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित

मांडर । प्रखंड के अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी मांडर द्वारा एक बैठक रखी गई। इसमें प्रखंड अल्पसंख्यक अध्यक्ष अमानत अंसारी, प्रखण्ड उपाध्यक्ष, प्रखण्ड सचिव एवं 19 पंचायतों के कांग्रेस पार्टी के पंचायत अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता संबंधित पंचायतों के कांग्रेस अध्यक्षों द्वारा की गई। इस दौरान कांग्रेस पार्टी की नीतियों, सिद्धांतों तथा जमीनी स्तर पर पंचायत संगठन को और अधिक मजबूत करने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही एस आई आर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित प्रखंड उपाध्यक्ष माशुक, अली, समीम अंसारी, प्रखण्ड सचिव आजाद अंसारी, मुस्ताकिम अंसारी जहरुद्दीन अंसारी, नेसार अख्तर, हासिम अंसारी,अतहर इमाम, शाहिद अंसारी, पंचायत अध्यक्ष सलीम अंसारी, रूस्तम अंसारी, कलीम अंसारी, तबरेज अंसारी,तनवीर आलम,इरफान, मुस्तफा, मिन्हाज, जुनैद, फिरोज अंसारी, गुलजार, इमरोज अंसारी, जुमाऊदीन अंसारी, नसीम अंसारी इस्तियाक अंसारी समेत अन्य लोग मौजूद थे।

जंगली हाथी के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों में दहशत का माहौल

लापुंग। लापुंग थाना क्षेत्र के जरिया मंगरा टोली जंगल और जरिया स्थित लोहागाड़ा नदी क्षेत्र में एक विशालकाय जंगली हाथी के पहुंचने के बाद ग्रामीणों में काफी दहशत छा गया। हालांकि कुछ साहसी युवकों जिनमें विपिन होरो,दाऊद होरो, इस्तानिस्ला होरो,सुमित होरो सहित अन्य लोगों ने मिलकर जंगली हाथी को खदेड़ने का प्रयास किया। मंगलवार को दिन में ही जंगली हाथी के पहुंचने से ग्रामीणों के बीच दहशत व्याप्त हो गया। जंगल में लकड़ी चुनने वाली महिलाएं जंगली हाथी को देखकर चुनी हुई लकड़ियों को छोड़कर भाग खड़ी हुई। इभांजालिस्ता टोप्पनो ने बताया कि जंगली हाथी ने कुछ ग्रामीणों के खेतों में लगी मड़ुआ की फसल तथा खलिहानों में रखे धान की फसलों को नुकसान पहुंचाया। जरिया मंगरा टोली, जरिया पतराटोली, जरिया खास तथा कथकुंवारी झोरा टोली, ससनटोली सहित गुमला जिले के सीमावर्ती मुरूमकेला के ग्रामीणों ने मिलकर जंगली हाथी को खदेड़कर खूंटी जिले के सीमावर्ती बकसपुर लापा की ओर जंगली हाथी को खदेड़ दिया। उल्लेखनीय है कि रांची, गुमला और खूंटी जिले के सीमावर्ती इलाकों में विचरण कर रहा जंगली हाथी के पुनः देर रात वापस लौटने की आशंका जताई है। आसपास के लोगों ने वन विभाग से ग्रामीणों की फसलों को जंगली हाथी से रक्षा करने की मांग की है।

करकट मोड़ के पास कवर बिजली तार लगाने के दौरान बाइक सवार घायल

चान्हो। थाना क्षेत्र के करकट मोड़ के पास मंगलवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार बिजली ठेकेदार के द्वारा अंधेरे में कवर तार लगाया जा रहा था, इसी दौरान चान्हो की ओर से मांडर कीओर जा रहे एक मोटरसाइकिल सवार तार में फंस गया। अचानक तार के बाइक में उलझ जाने से बाइक सवार सड़क पर गिर पड़ा। हादसे में उसका बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और उसे गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद की और घायल युवक को एंबुलेंस से निजी अस्पताल भेजा गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अंधेरे में बिना सुरक्षा व्यवस्था के तार लगाने से यह हादसा हुआ है।

कड़ाके की ठंड से राहत दिलाने खलारी में शुरू हुई अलाव की व्यवस्था

खलारी। कड़ाके की ठंड ने खलारी में दस्तक दे दी है। बढ़ती ठिठुरन से लोगों को राहत दिलाने के उद्देश्य से अंचल अधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रणव अम्बष्ट ने प्रखंड क्षेत्र के प्रमुख चौक-चौराहों पर अलाव की व्यवस्था शुरू करा दी है। शाम ढलते ही विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाए जा रहे हैं, जहां स्थानीय लोग जुटकर आग सेकते हुए आपस में चर्चा और परिचर्चा करते नजर आ रहे हैं। मंगलवार की शाम केडी हिंदूगढ़ी चौक पर भी अलाव के आसपास लोगों की भीड़ देखने को मिली, जहां सभी ने प्रशासन की इस पहल की सराहना की। ग्रामीणों का कहना है कि ठंड बढ़ने के साथ ऐसी व्यवस्था बेहद जरूरी है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी राहत मिल रही है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि ठंड के दिनों में सभी प्रमुख चौक-चौराहों पर नियमित रूप से अलाव जलाए जाएंगे।

ट्रांसफर नीति के उल्लंघन को लेकर रनिंग स्टाफ ने किया विरोध

मुरी/सिल्ली। मंगलवार के दिन रनिंग स्टाफ ने आरोप लगाया है कि मुरी लाबी के एक लोको पायलट को सीनियरिटी सूची एवं स्थापित नियमों को दरकिनार करते हुए "आउट ऑफ टर्न" हटिया स्थानांतरित कर दिया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि बिना किसी पैरवी या सोर्स वाले कई ड्राइवर पिछले 7–8 वर्षों से हटिया ट्रांसफर के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं,जबकि जिनका विशेष कौशल भी अन्य ड्राइवरों की तुलना में अलग नहीं है, उन्हें सीधे हटिया भेज दिया गया। रनिंग स्टाफ के अनुसार, संबंधित लोको पायलट को कुछ माह पहले ही प्रमोशन के बाद मुरी लाया गया था, लेकिन अचानक लगभग 120–130 स्टाफ को पीछे छोड़कर बॉटम से हटिया ट्रांसफर कर दिया गया,जिससे स्टाफ में रोष व्याप्त है कर्मचारियों का कहना है कि इस तरह के निर्णय से न केवल ट्रांसफर पॉलिसी की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं,बल्कि रेलवे को भी वित्तीय हानि पहुँच रही है।इसी कथित गलत ट्रांसफर नीति के विरोध में सभी रनिंग स्टाफ ने सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक ट्रेड यूनियन Act-1926 के तहत शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन की है।.स्टाफ ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की पारदर्शी जांच कर स्थापित नियमों के अनुरूप उचित कार्रवाई की जाए।

मृतक ग्रामीणों के स्वजनों को मजदूर नेता ने दी सहायता

खलारी। सामाजिक सरोकार का परिचय देते हुए मजदूर नेता अब्दुल्ला अंसारी ने प्रखंड के तीन दिवंगत ग्रामीणों राय बस्ती के स्व. कमेश महतो, डुण्डू के स्व. रवि महतो और स्व. महेश महतो के स्वजनों की सहायता की है। कुछ दिन पूर्व बीमारी के कारण इन तीनों ग्रामीणों का निधन हो गया था। जानकारी मिलने पर अब्दुल्ला अंसारी गांव पहुंचे और मृतक के परिवारों से मिलकर ढांढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने स्वजनों को आवश्यक खाद्य सामग्री प्रदान की, ताकि मुश्किल घड़ी में उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। साथ ही आश्वासन दिया कि भविष्य में भी किसी प्रकार की जरूरत पड़ने पर वे परिवारों के साथ खड़े रहेंगे।

झारखंड सीनियर पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती टीम अहमदाबाद हुई रवाना

रांची। 2025 सीनियर राष्ट्रीय, पुरुष फ्री स्टाइल/ग्रीको रोमन एवं महिला फ्रीस्टाइल राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता जिसका आयोजन 12 से 14 दिसंबर 2025 तक अहमदाबाद में आयोजित हो रहा है। इस कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने से पूर्व झारखंड कुश्ती टीम का 10 दिवसीय विशेष कुश्ती प्रशिक्षण शिविर का आयोजन खेलगांव होटवार रांची में किया गया था। इसके पश्चात झारखंड पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती टीम के खिलाड़ी जिसमें 10 खिलाड़ी एवं 2 प्रशिक्षक शामिल है जो आज अहमदाबाद के लिए रांची से रवाना हुए। उक्त प्रतियोगिता के लिए टीम रवाना होने से पहले झारखण्ड खेल विभाग के सहयोग द्वारा खिलाड़ियों को ट्रैक सूट, खेल किट देकर ,झारखंड सीनियर पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती टीम को रवाना किया गया।

खलारी में झरिया जैसी तबाही का खतरा, ग्रामीणों ने विस्थापन की लगाई गुहार

दहकती धरती से लोग दहशत में

- **हालात ऐसे ही बने रहे, तो यह पूरा इलाका झरिया की तरह कभी भी जमींदोज हो सकता है। प्रभावित क्षेत्र की भयावह स्थिति को देखते हुए राज्यसभा सांसद महुआ माजी स्वयं यहां पहुंची थीं**

नवीन मेल संवाददाता

खलारी। विगत एक दशक से भूमिगत खदान को खोलकर छोड़ दिए जाने की लापरवाही अब करकट्टा, विश्रामपुर और खिलानधौड़ा के ग्रामीणों पर भारी पड़ रही है। जमीन के भीतर लगातार धधक रही आग, दमघोटू गैसों का निकलना और जगह-जगह हो रहे भू-धसान ने पूरे क्षेत्र को भय और असुरक्षा के साये में ढक दिया है। इसी चिंता को लेकर मंगलवार को ग्रामीणों ने अंचल अधिकारी खलारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा और त्वरित विस्थापन प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। झामुमो नेता अनिलकुमार पासवान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल अंचल कार्यालय पहुंचा, जहां वरीय लिपिक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि करकट्टा स्थित बंद भूमिगत कोयला खदान को करीब 10 वर्ष पूर्व खुला खदान बनाकर खुला छोड़ दिया गया था। तब से लेकर आज तक इस खदान को भरने या सुरक्षा के अन्य उपाय करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। परिणामस्वरूप जमीन के भीतर आग लगातार फैलती जा रही है और आसपास के गांवों में दमघोटू गैसों के कारण लोगों की जिंदगी संकट में पड़ गई है। ग्रामीणों ने बताया कि कई स्थानों पर जमीन अचानक धंस रही है। यदि हालात ऐसे ही बने रहे, तो यह पूरा इलाका झरिया की तरह कभी भी जमींदोज हो सकता है। प्रभावित क्षेत्र की भयावह स्थिति को देखते हुए राज्यसभा सांसद महुआ माजी स्वयं यहां पहुंची थीं और उन्होंने स्थिति का निरीक्षण किया था। इसके बाद सीसीएल एनके एरिया प्रबंधन द्वारा विस्थापन प्रक्रिया के तहत घरों की नापी शुरू की गई थी, परंतु ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ ही दिनों में यह पूरी प्रक्रिया ठंडे बस्ते में डाल दी गई और दोबारा कोई पहल नहीं की गई। आशंका जताई गई है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो आने वाले समय में यहां मानवीय त्रासदी से इनकार नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों ने अंचल अधिकारी से आग्रह किया है कि करकट्टा, विश्रामपुर और खिलानधौड़ा के निवासियों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर विस्थापित कराया जाए ताकि किसी बड़ी अनहोनी को टाला जा सके। इधर खबर छपने के बाद मंगलवार दोपहर 12 बजे एनके एरिया सेफ्टी आफिसर नितिन झा करकट्टा स्थित बंद केडीएच पैच खदान का मुआयना कर आला अधिकारियों को हालात से अवगत कराए।

एनके प्रबंधन संग सकारात्मक वार्ता के बाद मोर्चा की 18 दिसंबर की बंदी स्थगित

खलारी। रैयत विस्थापित मोर्चा द्वारा उठाई गई 24 सूत्री मांगों पर मंगलवार की शाम एनके एरिया महाप्रबंधक कार्यालय स्थित कान्फ्रेंस हाल में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। अध्यक्षता एनके क्षेत्र के महाप्रबंधक दिनेशकुमार गुप्ता ने की। बैठक में मोर्चा के प्रतिनिधि और एनके प्रबंधन के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में रैयत विस्थापितों से संबंधित नौकरी मुआवजा, पुनर्वास, रोजगार, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता जैसी महत्वपूर्ण मांगों पर क्रमवार चर्चा की गई। मोर्चा की ओर से बताया गया कि लंबे समय से ये समस्याएं जस की तस बनी हैं, जिसके कारण विस्थापित परिवारों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। महाप्रबंधक ने सभी मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि प्रबंधन रैयत विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने इन सभी मुद्दों पर ठोस पहल करने के लिए एक महीने का समय मांगा तथा आश्वस्त किया कि निर्धारित समय के भीतर प्रगति जमीन पर दिखेगी। इसी क्रम में मोर्चा के एरिया अध्यक्ष बिगनसिंह भोगता ने कहा कि प्रबंधन को तय समय सीमा के भीतर ईमानदारी से कार्य करना होगा। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि एक माह के भीतर समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो मोर्चा जोरदार आंदोलन और बंदी के लिए तैयार रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह सीसीएल एनके प्रबंधन की होगी। सकारात्मक वार्ता के बाद मोर्चा ने 18 दिसंबर की प्रस्तावित बंदी को स्थगित करने का निर्णय लिया।

मोरहाबादी की चौपाल में भ्रष्टाचार पर हुई चर्चा

रांची। वरिष्ठ नागरिक संतोष अग्रवाल ने बताया कि मोरहाबादी की चौपाल से आज किसी ने बताया कि आज के दिन यानि कि साल में एक दिन मनाया जाता है" विश्व भ्रष्टाचार निरोध दिवस" यानि कि आज किसी को भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, सभी विभागों को बिना रिश्वत सबका काम कर देना चाहिए, जिस से आज एक दिन में लोगों की समस्याएं खत्म हो जाए, राज्य और राष्ट्र का विकास हो जाए। है ना भ्रष्टाचार करने के लिए बाकी 364 दिन। एक विचार आया कि समाचार पत्र प्रतिदिन 10, 20 खबर भ्रष्टाचार की जरूर छाप देता है, मिलती होगी तभी छपती होगी। अब इन खबरों को पढ़ने में किसी की दिलचस्पी नहीं, आम आदमी मान बैठा है कि किसी भी तरह का सरकारी काम के लिए पैसा देना ही होगा । कुछ विभाग के दस पांच हजार वाले पकड़े जाते है,बड़ी रकम वाले एक दो मामले हो जाते है और कुछ समय बाद सब खत्म हो जाता है। चौपाल का सुझाव है समाचार पत्रों से रोज इन खबरों को मत छापीए, महीने में एक दिन या साल में एक दिन भ्रष्टाचार विशेषांक निकाल दीजिए ,जिनको ये खबरें पढ़ने में दिलचस्पी होगी। वह पढ़ेगा बाकी को क्या मतलब , कम से कम 364 दिन इन खबरों को पढ़कर बोर तो नहीं होगा। चौपाल समाप्त हुई इस वादे के साथ कि भ्रष्टाचार पर अब बात होगी अगले साल "विश्व भ्रष्टाचार निरोध दिवस पर।

किसान मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड से सात किसान हुए सम्मानित

नवीन मेल संवाददाता

बेड़ो। बेड़ो प्रखंड के तीन गांवों चरिमा, कुदारखो एवं फादिलमर्चा के सात अलग-अलग प्रगतिशील किसानों को मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। चरिमा गांव के पंकज कुजुर,सुमित्रा कुजुर व विशेश्वर मिंज कुदारखो के वीरेंद्र कुमार व यमुना मेहता फादिल मर्चा के पिंकी कुमारी व अवध कुमार है। इन्हें आईएआरआई नई दिल्ली में कृषि जागरण द्वारा आयोजित मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिक सह सचिव डेयर एवं महानिदेशक भाकृअनुप के डा मांगी लाल जाट ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। इन सातों किसानों ने अपने गांव, प्रखंड सहित जिले का नाम रौशन किया है। सातों किसानों ने खेती के क्षेत्र में नवाचार,बेहतर व उत्कृष्ट उत्पादन के साथ आर्थिक समृद्धि कर उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। मौके पर किसानों ने अपने अनुभव साझा किए तथा आधुनिक कृषि तकनीक, स्टार्टअप, मार्केटिंग और उद्यमिता पर विशेष सत्र आयोजित किए गए थे जिसमें किसान उपस्थित हुए जिससे उन्हें विशेष लाभ मिला। इस प्रतिष्ठित आयोजन में झारखंड राज्य से बीस किसानों का चयन हुआ था जो पूरे राज्य के लिए गौरव का विषय रहा। इन किसानों की दिल्ली यात्रा, आवास और सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का संपूर्ण खर्च टीआरआई संस्था द्वारा वहन किया गया। राष्ट्रीय मंच पर झारखंड के किसानों को सम्मानित होते देख पूरे राज्य में हर्ष और उत्साह का वातावरण रहा। यह सम्मान समारोह किसानों के मनोबल को बढ़ाने वाला साबित हुआ। आयोजकों के अनुसार ऐसे आयोजन किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने, कृषि को लाभकारी बनाने और खेती को नए आयाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। झारखंड के किसानों की यह उपलब्धि न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। बेड़ो के किसानों की यह सफलता न केवल रांची जिले, बल्कि पूरे झारखंड के लिए गौरव का विषय है। कृषि विशेषज्ञ भी उनके मॉडल को आधुनिक खेती का एक प्रभावी उदाहरण बता रहे हैं। यह उपलब्धि दर्शाती है कि नवाचार से खेती में बदलाव आता है, जिससे पैदावार बढ़ती है और किसानों का भविष्य सुरक्षित होता है।

69वीं राष्ट्रीय स्कूली शूटिंग प्रतियोगिता में झारखंड को स्वर्ण

नवीन मेल संवाददाता

रांची। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची की अगुवाई में इंदौर, मध्यप्रदेश स्थित द एमराल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली शूटिंग प्रतियोगिता (एसजीएफआई) में झारखंड को एक और स्वर्णिम सफलता मिली है। अंडर-17 बालक वर्ग के प्रतिभाशाली निशानेबाज अभिनव पाठक ने 10 मीटर एयर राइफल ओपन साइट स्पर्धा में अपने सटीक और लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 6 से 9 दिसंबर 2025 तक आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देशभर से आए श्रेष्ठ खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से अभिनव ने कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच यह गौरव हासिल किया। झारखंड दल का नेतृत्व कोच/मैनेजर अनुज कुमार एवं संजय कुमार यादव कर रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस उपलब्धि पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह, परियोजना निदेशक श्री शशि रंजन, प्रशासी पदाधिकारी सच्चिदानंद द्विवेदी तिग्गा, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग सहित राज्य खेल कोषांग के सदस्यों ने अभिनव को हार्दिक बधाई दी है और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

सैमसंग ने लॉन्च किया गैलेक्सी जेड ट्राइफोल्ड

रांची। सैमसंग ने अपने नए फोल्डेबल स्मार्टफोन गैलेक्सी जेड ट्राइफोल्ड को पेश किया है, जो दो बार फोल्ड होने वाले डिजाइन और बड़ी स्क्रीन के साथ आता है। कंपनी के डिवाइस एक्सपीरियंस डिवीजन के प्रमुख टीएम रोह ने कहा कि यह मॉडल पोर्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस और उत्पादकता के बीच सही संतुलन बनाते हुए फोल्डेबल तकनीक का अगला कदम साबित होगा। नया ट्राइफोल्ड एआई आधारित फीचर्स और उन्नत फोल्डिंग मैकेनिज़्म के साथ पेश किया गया है, जबकि लॉन्च के साथ ग्राहकों के लिए कुछ विशेष लाभ भी उपलब्ध कराए गए हैं।

बहुप्रतीक्षित तिलैया डैम ग्रामीण जलापूर्ति योजना पर विधायक ने उठाई आवाज

सदन में बरही प्रखंड के हजारों ग्रामीणों के शुद्ध पेयजल को लेकर मंत्री से पूछे सवाल

- तिलैया डैम से बरही के ग्रामीण क्षेत्रों को पानी उपलब्ध कराने की यह योजना वर्ष 2007–08 में डीवीसी की सीएसआर मद से शुरू हुई थी

नवीन मेल संवाददाता

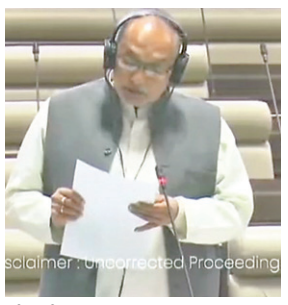

बरही । करीब 15 वर्षों से लंबित तिलैया डैम ग्रामीण जलापूर्ति योजना पर आखिरकार स्थानीय विधायक मनोज कुमार यादव ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जोरदार तरीके से मुद्दा उठाया। उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से मांग की कि बरही प्रखंड के हजारों ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इस महत्वपूर्ण योजना को तुरंत पूरा किया जाए। विधायक ने कहा कि गर्मी के दिनों में पेयजल को लेकर मारामारी की स्थिति बन जाती है, जिससे ग्रामीणों में असंतोष लगातार बढ़ रहा है। तिलैया डैम से बरही के ग्रामीण क्षेत्रों को पानी उपलब्ध कराने की यह योजना वर्ष 2007–08 में डीवीसी की सीएसआर मद से शुरू हुई थी। 05 एमएलडी क्षमता वाली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (डब्ल्यूटीपी) योजना में पहले चरण के तहत इंटेक वेल, राइजिंग मेन और डिस्ट्रीब्यूशन मेन का निर्माण होना था, जबकि अंतिम चरण में इलेक्ट्रिकल सब-स्टेशन एवं पावर सप्लाई शामिल थे। लेकिन वर्ष 2009 तक केवल 65% कार्य ही पूरा हो सका। 2012 तक भी कार्य पूरा नहीं हुआ, और योजना अधर में पड़ती चली गई। आज तक कई पंचायतों के लोग स्वच्छ पानी के लिए तरस रहे हैं।

- 2013 में शुरू हुआ संयुक्त प्रयास भी अटका

वर्ष 2013 में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और डीवीसी ने संयुक्त रूप से योजना को पूरा करने का निर्णय लिया। इसके लिए कुल 17,24,65,024 रुपये की स्वीकृति दी गई, जिसमें डीवीसी द्वारा 7,83,36,275 रुपये तथा विभाग द्वारा 6 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए थे। इसके बावजूद कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे नहीं हो सके और उपलब्ध राशि का पूरी तरह उपयोग भी नहीं हुआ। ग्रामीणों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने की यह महत्वाकांक्षी योजना कागजों में ही सीमित रह गई। विधायक द्वारा मामला उठाए जाने के बाद विभाग ने 09.10.2023 को 2761.85475 लाख रुपये तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के तहत 1037.20451 लाख रुपये की मंजूरी दी है। इसके बावजूद योजना धरातल पर आगे नहीं बढ़ पाई है। विधायक का कहना है कि सरकार को अविलंब हस्तक्षेप कर कार्य को पूरा कराना चाहिए, ताकि बरही प्रखंड के लोग वर्षों से चली आ रही जल संकट की समस्या से निजात पा सकें। ग्रामीणों ने भी उम्मीद जताई है कि विधायक के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद इस बार योजना पर ठोस कार्रवाई होगी और गर्मी से पहले उन्हें शुद्ध पेयजल की सुविधा मिल सकेगी।

बरही प्रशासन ध्यान दे: बैरीसाल में रोज हो रहा अवैध बालू का कारोबार : मो. कयूम

बरही। अल्पसंख्यक कल्याण मोर्चा के बरही विधानसभा अध्यक्ष मो. कयूम अंसारी ने बैरीसाल क्षेत्र में प्रतिदिन हो रहे अवैध बालू कारोबार पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से बैरीसाल घाट पर खुलेआम बालू का अवैध उठाव जारी है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। ग्रामीणों के अनुसार, रोजाना भोर करीब 3 बजे से ही ट्रैक्टर व भारी वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाती है, जिससे पूरा क्षेत्र एक अस्थायी मंडी में बदल जाता है। मो. अंसारी ने कहा कि इस अवैध गतिविधि से सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। दूसरी ओर, लगातार बालू लदे वाहनों के चलने से सड़कें जर्जर हो रही हैं और स्थानीय लोगों को आवागमन में दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोगों के संरक्षण में यह कारोबार फल-फूल रहा है, जिसके कारण अवैध खनन करने वालों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने बरही प्रशासन से मांग की है कि तत्काल छापेमारी अभियान चलाकर अवैध बालू उठाव को रोका जाए और इस काम में संलिप्त लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाए। मो. कयूम अंसारी ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन समय रहते कदम नहीं उठाता, तो स्थानीय लोग आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। कहा कि क्षेत्र की सुरक्षा, सड़कों की बचत और राजस्व संरक्षण के लिए यह कार्रवाई अत्यंत आवश्यक है।

न्यूज बॉक्स

प्रखंड क्षेत्र के शिलाडीह पंचायत में पुस्तक और कार्य पत्रक का हुआ वितरण

बरकट्ठा। मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड पालक चंदन सिन्हा बरही निवासी के प्रवास के दौरान शिलाडीह पंचायत में आगमन हुआ। जिसमें पुस्तक और कार्य पत्रक वितरण कर चर्चा की गई। वहीं पंचायत अध्यक्ष शिवलाल यादव को यह कार्य सौंपा गया। मौके पर चंदन सिंहा ने कहा बरकट्ठा के सभी 17 पंचायत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर उनकी उपलब्धि को लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यपत्रक और पुस्तक का वितरण सभी घरों में किया जा रहा है। मौके पर कृष्णजय पांडेय,सूरज देव प्रजापति, मंटू पांडेय, देवलाल पंडित, किशुन पंडित के अलावे कई लोग उपस्थित थे।

साइबर सिक्योरिटी विषय पर आयोजित विशेष कक्षा का दूसरा दिन

रामगढ़। डॉ० एस० राधाकृष्णन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सुकरीगढ़ा, लारी, रामगढ़ के बहुउद्देशीय सभागार में 9 दिसंबर को महाविद्यालय आईक्यूएसी प्रकोष्ठ के अंतर्गत मूल्य संवर्धित पाठ्यक्रम में साइबर सुरक्षा विषय पर विशेष अतिरिक्त कक्षा के दूसरे दिन विषय विशेषज्ञ के तौर पर मुख्य वक्ता रोहन नायक ने प्रशिक्षुओं को साइबर ठगी, साइबर क्राइम, वीडियो साइबर,जीमेल, फेसबुक, निजी दिनचर्या, मोबाइल, बैंक संबंधित आदि बातों को विस्तृत रुप से पीपीटी के माध्यम से बताया । साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी के लिए प्रशिक्षुओं द्वारा साइबर जोखिम से बचने के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न पूछे गए । विषय विशेषज्ञ द्वारा सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर देकर छात्रों की जिज्ञासा का समाधान किया गया। कार्यक्रम का संचालन एवं देखरेख सहायक अध्यापक डॉ० अशोक राम द्वारा किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय शिक्षकों में नयन कुमार मिश्रा ,इंदु कुमारी झा ,मुरारी कुमार दुबे , सुप्रिया बर्मन, सुलेखा कुमारी, वरुण कुमार आदि शामिल हुए ।

स्वर्गीय सीता साव की स्मृति में गरीब व असहायों के बीच कंबल का हुआ वितरण

रामगढ़ । बरबीघा के प्रसिद्ध समाजसेवी सह व्यवसायी रहे स्वर्गीय सीता साहू के 16वीं पुण्यतिथि पर स्वर्गीय सीता साव के नाती अमित साहू एवं परिवार के द्वारा के द्वारा जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया। अमित साहू ने बताया कि हमारे नाना जी स्वर्गीय सीता साव बरबीघा के बहुत ही प्रखर समाजसेवी एवं प्रसिद्ध व्यवसायी रहे। एवं उनके ही बताएं मार्ग पर हम लोग चलकर समाज के जरूरतमंद अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए कटिबद्ध थे और कटिबद्ध रहेंगे। इसी क्रम में आज स्वर्गीय सीता साव जी के 16वीं पुण्यतिथि पर इस कड़ाके की ठंड में कंबल वितरण किया गया और स्वर्गीय सीता साव जी को पुष्पांजलि अर्पित किया गया।

विधायक ने बरकट्ठा डिग्री कॉलेज का मुद्दा विधानसभा में उठाया

बरकट्ठा। विधायक अमित कुमार यादव ने षष्ठम झारखंड विधानसभा का चतुर्थ (शीतकालीन) सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए बरकट्ठा डिग्री कॉलेज की गंभीर समस्याओं को सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बावजूद न पढ़ाई शुरू हुई है और ना ही लेक्चरर और प्रिंसिपल की नियुक्ति की गई है। आवश्यक व्यवस्थाओं का पूर्ण अभाव होने से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। इस संबंध में विधायक अमित कुमार यादव ने सदन के पटल पर विभिन्न मुद्दों को रखते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया। इस कार्य के लिए विधानसभा क्षेत्र की जनता ने विधायक के प्रति आभार व्यक्त किया। वहीं विधायक अमित कुमार यादव ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं से सरकार को अवगत कराना मेरा कर्तव्य है। इसपर सरकार कितना पहल करेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा।

कूच बिहार एलिट अंडर-19 के पहले मैच में झारखंड ने 206 रन बनाए

हजारीबाग। कूच बिहार ट्रॉफी (इलीट अंडर-19) के चार दिवसीय मुकाबले के पहले दिन हजारीबाग के संजय सिंह क्रिकेट स्टेडियम में पहले दिन झारखंड की टीम ने 207 रन का लक्ष्य दिया। पूरी टीम 206 रन पर ऑल आउट हो गई। पहले दिन झारखंड के बल्लेबाजों का प्रदर्शन औसत रहा। टीम 64.3 ओवर में 206 रन पर ऑल आउट हो गई। ओपनर वत्सल तिवारी ने 30 रन और एल. कौशिक ने सर्वाधिक 39 रन का योगदान दिया। मध्यक्रम और निचले क्रम के बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं कर सके, जिससे टीम मजबूत स्कोर तक नहीं पहुंच पाई। कप्तान ईशान ओम और प्रिंस मिश्रा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। केरल के गेंदबाज मोहम्मद इनाम ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट हासिल किए। जवाब में केरल की टीम ने पहली पारी में शुरुआत की। खेल समाप्ति तक केरल ने 62 रन पर दो विकेट खो दिए। जोबीन जोबी 8 रन पर दीपांशु रावत का शिकार बने, जबकि संगीत सागर 18 रन पर पगबाधा आउट हुए। थॉमस मैथ्यू 15 रन और अमय मनोज 10 रन पर नॉट आउट रहे। अगले दिन का खेल सुबह 9 बजे से शुरू होगा। सेकेंड हाफ में केरल टीम ने अपनी पहली पारी को आगे बढ़ाया। केरल ने खेल शुरू होने पर 62/2 से पारी आगे बढ़ाई और संयमित बल्लेबाजी कर रही थी। झारखंड की ओर से गेंदबाजों ने शुरुआत में दबाव बनाया, लेकिन इसके बावजूद केरल के बल्लेबाजों ने विकेट संभालकर खेलते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। थॉमस मैथ्यू ने धैर्यपूर्ण पारी खेलते हुए महत्वपूर्ण रन जोड़े, जबकि अमय मनोज ने भी दूसरे छोर से साझेदारी निभाई। झारखंड की ओर से दीपांशु रावत और सार्थक ने किफायती गेंदबाजी करते हुए कई बार केरल के बल्लेबाजों को परेशान किया।

इनरव्हील क्लब ने पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए उद्यान विकसित किया

रामगढ़। इनरव्हील क्लब रामगढ़ ने पर्यावरण संरक्षण और जन-जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्रिगेडियर पुरी पार्क में एक सुंदर और उपयोगी औषधीय पौधों का उद्यान विकसित किया है। इस उद्यान में कुल 20 औषधीय पौधों का रोपण सावधानीपूर्वक किया गया, जिनमें आंवला, नींबू, धतूरा, पाथरचट्टा, अश्वगंधा, रोजमेरी, पलाश, नीम, करी पत्ता, हल्दी, अदरक, गुड़हल, तुलसी, गिलोय आदि प्रमुख हैं। प्रत्येक पौधे के साथ जानकारीपूर्ण प्लाकार्ड लगाए गए हैं, जिन पर पौधे का वैज्ञानिक नाम उसके मुख्य औषधीय उपयोग तथा इनर व्हील का नाम व लोगो अंकित है। साथ ही प्लाकार्ड पर लगे क्यूआर कोड के माध्यम से लोग सीधे क्लब के इंस्टाग्राम पेज से जुड़ सकते हैं, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक प्रकृति और स्वास्थ्य से जुड़े संदेश पहुंच सकें। उद्यान में एक आकर्षक मुख्य साइनिज बोर्ड भी स्थापित किया गया है, जो आगंतुकों को इस पहल के उद्देश्य और औषधीय पौधों के महत्व के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ब्रिगेडियर पुरी पार्क शहर का एक प्रसिद्ध स्थल है, जहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग मॉर्निंग वॉक, व्यायाम और मनोरंजन के लिए आते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण स्थल पर औषधीय पौधों का उद्यान की स्थापना न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक कदम है, बल्कि लोगों को प्रकृति की उपचार शक्ति से भी परिचित कराता है।

जिला अनाबद्ध निधि के तहत हो रहे कार्यों की उपायुक्त ने की समीक्षा

योजनाओं का समय-समय पर निरीक्षण करने का दिया निर्देश

- जिला अनाबद्ध निधि के माध्यम से संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने अब तक हुए कार्यों की विस्तार से जानकारी ली

नवीन मेल संवाददाता

रामगढ़। उपायुक्त रामगढ़ फैज अक अहमद मुमताज की अध्यक्षता में मंगलवार को उनके कार्यालय कक्ष में रामगढ़ जिले में अनाबद्ध निधि माध्यम से हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सर्वप्रथम जिला अनाबद्ध निधि की पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में किए गए कार्यों की जानकारी जिला योजना पदाधिकारी संतोष भगत से ली। उपायुक्त ने अनाबद्ध निधि के तहत संचालित विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली एवं सभी कार्यकारी एजेंसियों को उनके तहत किए जा रहे हैं योजनाओं को गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला अनाबद्ध निधि के माध्यम से संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने अब तक हुए कार्यों की विस्तार से जानकारी ली एवं वित्तीय वर्ष 2023- 24 , 2024-25 एवं 2025-26 में स्वीकृत योजनाओं को पूर्ण कराने का निर्देश दिया वहीं बैठक के दौरान उपायुक्त ने उपस्थित सभी सहायक अभियंता को योजनाओं का समय-समय पर निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने सभी प्रक्रियाएं पूर्ण करने के उपरांत ही योजनाओं में निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया। बैठक में कार्यपालक अभियंताओं, सहायक अभियंताओं सहित अन्य उपस्थित थे।

हजारीबाग में छात्र–छात्राओं का उबाल उतरे सड़क पर

छात्रवृत्ति भुगतान की मांग को लेकर आजसू का आक्रोश मार्च

- 11.34 लाख छात्रों में से केवल 7.45 लाख को आंशिक भुगतान हुआ है, जबकि 3.5 लाख ओबीसी छात्र पहली किस्त के इंतज़ार में हैं

नवीन मेल संवाददाता

बरही/हजारीबाग । राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति भुगतान में हो रही देरी के खिलाफ मंगलवार को हज़ारीबाग में आजसू छात्र संघ के बैनर तले बड़े पैमाने पर छात्र–छात्राएं सड़क पर उतरे। "शिक्षा के लिए भिक्षा – जन आक्रोश मार्च" के नाम से आयोजित इस आंदोलन में विभिन्न कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों के हजारों छात्र शामिल हुए। गांधी मैदान से शुरू हुआ यह पैदल मार्च उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुआ, जहाँ प्रतिनिधियों ने डीसी को ज्ञापन सौंपा। छात्रों को संबोधित करते हुए हज़ारीबाग लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी संजय मेहता ने कहा कि छात्रवृत्ति छात्रों का संवैधानिक अधिकार है और सरकार इसे रोककर उनकी शिक्षा पर प्रहार कर रही है। उन्होंने सरकार से तत्काल सत्र 2024–25 की लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की। मेहता ने चेताया कि छात्रों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता और यह आंदोलन अब जिलावार तेज़ी से आगे बढ़ेगा। छात्र नेताओं ने कहा कि झारखंड के लाखों छात्र महीनों से पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके कारण उनका अकादमिक वर्ष संकट में है। उन्होंने बताया कि 11.34 लाख छात्रों में से केवल 7.45 लाख को आंशिक भुगतान हुआ है, जबकि 3.5 लाख ओबीसी छात्र पहली किस्त के इंतज़ार में हैं। सरकार की चुप्पी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आक्रोश मार्च में छात्र संघ अध्यक्ष ओम वर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष बबलू महतो, उपाध्यक्ष ऋतुराज शाहदेव, जिला संयोजक शुभम राणा सहित कई छात्र नेता और बड़ी संख्या में छात्र–छात्राएँ शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक सभी छात्रों को उनकी पूर्ण छात्रवृत्ति नहीं मिल जाती, आंदोलन जारी रहेगा।

मारपीट के आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी

चरही। सीसीएल हजारीबाग क्षेत्र की केदला उत्खनन परियोजना में शनिवार 6 दिसंबर को अधकिारियों से मारपीट मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। सीसीएल सुरक्षा प्रभारी वरुण कुमार साव की शिकायत पर घाटो थाना में बिहारी महतो समेत अन्य पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इधर सोमवार को कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि जल्द कड़ी कार्रवाई नहीं होने पर वे हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे।सोमवार को अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि यह हमला अवैध कोयला उत्खनन को रोकने के दौरान हुई कार्रवाई के प्रतिशोध में किया गया है।अधिकारियों ने पुलिस प्रशासन से दोषियों पर त्वरित कानूनी कार्रवाई की मांग की है ताकि वे निर्भीक होकर सरकारी कार्य कर सकें। साथ ही कार्यालय और परियोजना स्थल पर सीआईएफ व होमगार्ड जवानों की तैनाती की मांग भी उठाई गई है। प्रेस वार्ता में अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह सहित एरिया के सभी अधिकारी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि हमले में सबसे गंभीर रूप से घायल जयकांत नारायण का दाहिना हाथ टूट गया है।

जनता उच्च विद्यालय होन्हे में बैठक का हुआ आयोजन

नवीन मेल संवाददाता

रामगढ़। दुलमी प्रखंड के जनता उच्च विद्यालय होन्हे में अनुदान राशि वितरण एवं विद्यालय विकास कार्यों को लेकर मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्ष 2024–25 के अंतर्गत विद्यालय को प्राप्त शेष 12 प्रतिशत अनुदान राशि एवं अन्य आवंटित मदों के उपयोग, वितरण तथा आगामी विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। विधायक ममता देवी के निर्देशानुसार बैठक में दुलमी प्रखंड बीस सूत्री अध्यक्ष सुधीर मंगलेश प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन, शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के साथ बैठक कर विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण, पठन-पाठन व्यवस्था तथा आवश्यक भौतिक संसाधनों को सुदृढ़ करने पर अपना सुझाव दिया।

उन्होंने कहा कि अनुदान राशि का उपयोग पारदर्शिता एवं प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, जिससे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा व संसाधन उपलब्ध हों। बैठक में विद्यालय विकास की आगामी योजनाओं पर भी सहमति बनाई गई। बैठक में सचिव गंगाधर महतो,प्रधानाध्यापक नवरोतम कुमार, भेदोराम महतो, दीपक कुमार, सुनील महतो, मनोज महतो, पवन कुमार, राहुल पांडेय, हरिदास महतो, शिक्षक-शिक्षिकाएँ एवं संबंधित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

हौसला बुलंद हौसले और जज्बे से हारी ग़रीबी ,दिव्यांग युवक बना श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

रिजल्ट प्रकाशित के दिन ही दिव्यांग बहन की हो गयी मौत आंखों में गम के आंसू के साथ छलके खुशी के आंसु

- दिन-रात मेहनत कर, लोगों के तानों को सहकर, समाज के कटाक्षों को जहर का घूंट समझकर पीते हुए भी संदीप ने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा

नवीन मेल संवाददाता

बरकट्ठा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है बरकट्ठाडीह निवासी संदीप कुमार दास ने जो दोनों पैरो और हाथों से दिव्यांग होने के बावजूद भी उन्होंने गरीबी और लाचारी को कामयाबी में बदल दिया। उन्होंने अंतिम रूप से श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बनकर माता पिता व क्षेत्र का नाम रौशन किया है। पिता अर्जुन रविदास पेशे से राज मिस्त्री हैं। जीवन में उन्हें जितनी कठिनाइयाँ मिलीं, शायद उतनी कठिनाई के बाद एक साधारण इंसान टुट जाता है ,बावजूद संदीप कभी टूटे नहीं। गिरे, संभले, फिर उठे, और अपनी मेहनत से इस कामयाबी को पाया। दिन-रात मेहनत कर, लोगों के तानों को सहकर, समाज के कटाक्षों को जहर का घूंट समझकर पीते हुए भी संदीप ने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा और अंततः जेएसएससी सीजीएल में "श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बनकर बता दिया कि सपनों पर विश्वास और मेहनत से कोई भी मंज़िल दूर नहीं। लेकिन किस्मत ने उसी दिन एक बड़ा दर्द भी दे दिया रिज़ल्ट प्रकाशित के दिन ही उसी शाम उनकी दिव्यांग बहन की मौत हो गई एक तरफ जहां आंखों में ग़म के आंसु थे तो वहीं दूसरी ओर आखों से खुशी की आंसु छलक पड़े। ऐसा दर्द और ऐसा गौरव एक साथ शायद ही किसी के हिस्से आता होगा। फिर भी संदीप ने खुद को संभाला और अपनी बहन की याद को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ा। उन्होंने बताया कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य विद्यालय बरकट्ठा, माध्यमिक शिक्षा हाई स्कूल बरकट्ठा, बारहवीं संत कोलंबस कालेज व ग्रेजुएशन की पढ़ाई घर बैठे इग्नू से पूरा किया , उन्होंने बताया कि सीजीएल की तैयारी वह घर बैठे स्वाध्याय कर सफलता अर्जित की है ।आगे बताया कि उनकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान उनके माता-पिता,व पूरे परिवार, समाज और उनके शिक्षकों का है। इन्हीं की मेहनत, आशीर्वाद और संस्कारों ने उन्हें यहाँ तक पहुंचाया है। संदीप कुमार दास की कहानी सिर्फ सफलता की कहानी नहीं,यह साहस, संघर्ष और आत्मविश्वास का ऐसा उदाहरण है जिसे पढ़कर हर युवा प्रेरणा ले सकता है।

शिक्षा विभाग के केलाघाघ डैम में जिला स्तरीय मुखिया सम्मेलन

डीसी व एसपी ने शिक्षा सुधार और गुणवत्ता पर दिया जोर

नवीन मेल संवाददाता

सिमडेगा। झारखंड शिक्षा परियोजना समग्र शिक्षा, सिमडेगा द्वारा जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल केलाघाघ डैम में जिला स्तरीय मुखिया सम्मेलन–2025 का भव्य आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों—विशेषकर मुखियाओं—को विद्यालय प्रबंधन, पठन-पाठन की गुणवत्ता, नामांकन वृद्धि, ड्रॉपआउट रोकथाम, आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा समुदाय की सक्रिय भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण शैक्षिक पहलुओं के प्रति जागरूक एवं सक्षम बनाना था।कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त कंचन सिंह, पुलिस अधीक्षक एम. अर्शी, जिला परिषद उपाध्यक्ष सोनी पैंकरा तथा मुखिया संघ के अध्यक्ष और सचिव द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथलेश केरकेट्टा, जिला शिक्षा अधीक्षक दीपक राम, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सुरज मुन्नी कुमारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पलटू महतो, सांसद प्रतिनिधि डीडी सिंह, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित थे।उपायुक्त कंचन सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि पंचायत प्रतिनिधि ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की सबसे प्रभावी इकाई हैं। उन्होंने कहा कि मुखिया अपने क्षेत्र के विद्यालयों के संरक्षक होते हैं और विद्यालय की प्रगति सीधे तौर पर उनके नेतृत्व और सक्रियता पर निर्भर करती है। उन्होंने विद्यालयों में नियमित निरीक्षण, शिक्षक-छात्र उपस्थिति की निगरानी, साफ-सफाई तथा मध्यान्ह भोजन व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की अपील की। उपायुक्त ने कहा कि यदि पंचायत में पाँच गांव हैं तो वार्ड सदस्य अलग-अलग विद्यालयों का दौरा कर सकते हैं। कई बार बिना बताए विद्यालय में बैठ जाना भी प्रभावी निरीक्षण साबित होता है।उपायुक्त ने आवासीय विद्यालयों पर विशेष जोर देते हुए कहा कि ऐसे विद्यालयों में रहने वाले छोटे बच्चों को मानसिक, नैतिक और भावनात्मक सहयोग की आवश्यकता होती है। उन्होंने मुखियाओं से सप्ताह में कुछ समय बच्चों के बीच बिताने, खेल-कूद कराने और प्रेरणात्मक बातें साझा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह छोटा सा प्रयास बच्चों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है।

पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण पर जोर

उपायुक्त ने बताया कि सम्मेलन को केलाघाघ पर्यटन स्थल में आयोजित करने का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों को जिले के पर्यटन स्थलों की स्थिति और संभावनाओं से अवगत कराना था। उन्होंने पंचायत स्तर पर पर्यटन समितियों को सक्रिय करने, पार्किंग शुल्क व्यवस्था लागू करने, गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने तथा पिकनिक स्थलों पर पॉलिथीन, प्लास्टिक और थर्मोकोल के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सिमडेगा पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर है और इसमें पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका अहम है। उन्होंने जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र या अन्य संवेदनशील मामलों से जुड़ी परेशानियों की सूची सीधे उपलब्ध कराने को भी कहा, ताकि समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

शिक्षा को लेकर ग्राम स्तर तक जागरूकता जरूरी : एसपी एम. अर्शी

पुलिस अधीक्षक एम. अर्शी ने कहा कि मुखिया सम्मेलन का उद्देश्य शिक्षा को लेकर गांव-गांव तक गंभीरता और जागरूकता फैलाना है। उन्होंने कहा कि मुखिया अपने क्षेत्र के सबसे जागरूक और सक्षम व्यक्ति होते हैं। यदि वे संकल्पित होकर कार्य करें तो गांव का हर बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकता है। उन्होंने प्रतिनिधियों से अपनी जिम्मेदारियों को निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाने की अपील की।

जनप्रतिनिधियों ने रखी कई महत्वपूर्ण समस्याएं

सम्मेलन में जिला परिषद उपाध्यक्ष सहित विभिन्न पंचायतों के मुखियाओं ने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उपायुक्त के समक्ष रखे। उपाध्यक्ष ने कहा कि डोमरा, चिकबड़ाईक, मलार, तुरी आदि समुदायों के बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाने में गंभीर समस्याएँ आती हैं, जिससे वे शिक्षा और छात्रवृत्ति योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। परित्यक्त या एकल महिलाओं के बच्चों के प्रमाण पत्र बनवाने में भी दिक्कतें सामने आती हैं। उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि ऐसे मामलों में प्राथमिकता से कार्रवाई की जाएगी और सभी बच्चों के अधिकार सुरक्षित किए जाएंगे।सम्मेलन में पिरामल फाउंडेशन के सोमेन ने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न मानकों में हुए सुधार की जानकारी दी। समसेरा और बीरु के मुखियाओं ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का स्वागत संबोधन जिला शिक्षा अधीक्षक ने दिया तथा धन्यवाद ज्ञापन एडीपीओ द्वारा किया गया।

जेएसएलपीएस की ब्लॉक समीक्षा बैठक संपन्न, डीडीसी ने दिए निर्देश

नवीन मेल संवाददाता

- **परिकल्पना निधि व सामुदायिक निवेश को एक माह में पोर्टल पर दर्ज करने का आदेश**

सिमडेगा। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जेएसएलपीएस की ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक ग्रामीण विकास परिसर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त ने की। जिला परियोजना प्रबंधक, सभी जिला प्रबंधक और प्रखंड परियोजना प्रबंधक बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में स्वसहायता समूह सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन, गैर-कृषि आजीविका तथा जापान सहयोग परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई।उप विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि जिले के सभी निष्क्रिय स्वसहायता समूहों को दो सप्ताह में सक्रिय किया जाए तथा सभी रजिस्टरों को एक माह में अद्यतन किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वसहायता समूहों के परिकल्पना निधि और सामुदायिक निवेश को एक माह में पोर्टल पर दर्ज किया जाए तथा ऋण-संबंधन हेतु सभी आवश्यक कागजात 20 दिसंबर तक बैंकों में जमा कर दैनिक प्रगति भेजी जाए।कृषि आधारित आजीविका गतिविधियों का सत्यापन, किसान उत्पादक समूह को अनुदान के लिए पात्र बनाने, पलाश मार्ट हेतु भूमि चयन और आजीविका सुविधा केंद्र के लिए भवन चिह्नित करने का निर्देश दिया गया। कम प्रगति वाले प्रखंडों को समयबद्ध कार्य पूरा करने को कहा गया, ताकि स्वसहायता समूहों को अधिक लाभ मिल सके।

सिमडेगा जिले के सभी 14 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों की हुई समीक्षा बैठक

नवीन मेल संवाददाता

सिमडेगा। जिले में संचालित सभी 14 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों की समीक्षा बैठक सोमवार को उप विकास आयुक्त दीपांकर चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, मत्स्य विभाग, उद्योग विभाग, नाबार्ड, जेएसएलपीएस, बैंकिंग संस्थानों और बाजार समिति के प्रतिनिधियों के साथ-साथ सभी एफपीओ के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव और लेखापाल उपस्थित रहे।बैठक के दौरान एफपीओ की अद्यतन स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन किया गया। इसमें पिछले वित्तीय वर्ष के टर्नओवर, शेयरधारकों की संख्या, शेयर पूंजी, कंपनियों की वर्तमान गतिविधियों और किसानों को प्रदान की जा रही सेवाओं की समीक्षा शामिल थी। एफपीओ के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने संगठन की प्रगति, उपलब्धियों और मौजूदा चुनौतियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया।उप विकास आयुक्त ने सभी एफपीओ को निर्देश दिया कि वे अपनी आगामी व्यापार योजना जल्द से जल्द तैयार कर जिला प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि सुव्यवस्थित व्यापार योजना एफपीओ को मजबूत करेगी और किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्राथमिकता के आधार पर जेएसएलपीएस द्वारा संचालित दो कंपनियों—महिला जागृति फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, सिमडेगा और कोलेबिरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी—को तत्काल व्यापार योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया।बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा एफपीओ को उपलब्ध सरकारी योजनाओं, तकनीकी सहायता, अनुदान, ऋण सुविधा, विपणन सहयोग और लाइसेंस प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही सभी एफपीओ को ई-नाम पोर्टल में पंजीकरण कराने और सीड लाइसेंस प्राप्त करने के लिए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी, अग्रणी जिला प्रबंधक डी.डी.एम. नाबार्ड, जेएसएलपीएस के जिला प्रबंधक और प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक समेत कई विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने एफपीओ प्रतिनिधियों को आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक सहयोग देने का आश्वासन भी दिया।

बानो के बुरुहोंजेर में सहायता वितरण कार्यक्रम संपन्न

बानो। बानो प्रखंड के बुरुहोंजेर कर्राजरा में एमसीकेएस फाउंडेशन दिल्ली और सहयोग विलेज सिमडेगा के संयुक्त तत्वावधान में सहायता वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एमसीकेएस दिल्ली से नौनित कुमार तथा सहयोग विलेज सिमडेगा से जसमींदर सिंह, अमृत तोपनो, अरविंद कुमार एवं दीपक कुमार मौजूद रहे। साथ ही रौतिया समाज के प्रखंड अध्यक्ष महेश सिंह भी उपस्थित थे।कार्यक्रम के दौरान करीब 300 जरूरतमंद महिलाओं और पुरुषों के बीच कंबल व साड़ी का वितरण किया गया। प्रतिनिधियों ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य ठंड के मौसम में असहाय परिवारों को राहत पहुंचना है।

- एमसीकेएस फाउंडेशन दिल्ली व सहयोग विलेज का संयुक्त प्रयास

कोनपाला पंचायत में बेकार पड़ा बीएसएनएल टावर, पूर्व उप मुखिया ने उठाए सवाल

ठेठईटांगर। प्रखंड के कोनपाला पंचायत में स्थापित बीएसएनएल टावर शुरू न होने से ग्रामीणों में नाराज़गी बढ़ती जा रही है। पूर्व उप मुखिया व समाजसेवी दीपक लकड़ा ने कहा कि यह टावर केवल दिखावा बनकर खड़ा है और लोगों के पैसों की बंदरबांट का स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि टावर का चालू न होना सरकारी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।नेटवर्क ठप होने से छात्र ऑनलाइन पढ़ाई और फॉर्म भरने में असमर्थ हैं, किसानों को मौसम और योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पा रही है तथा आपात स्थिति में फोन करना भी मुश्किल हो गया है।दीपक लकड़ा ने जिला प्रशासन से टावर को तत्काल चालू कराने या परियोजना की जांच कराने की मांग की है।

आदिवासी छात्रसंघ की कड़ी आपत्ति, छात्र हितों की लड़ाई और मजबूत करने पर जोर

नवीन मेल संवाददाता

सिमडेगा। अंबेडकर चौक सिमडेगा में आदिवासी छात्रसंघ जिला समिति की बैठक जिलाध्यक्ष रोशन डुंगडुंग की अध्यक्षता और संयोजक अजय एक्का की उपस्थिति में आयोजित की गई। बैठक में संगठन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। समिति ने बताया कि पिछले रविवार को विकास केंद्र सामटोली में कुछ लोगों ने जिला समिति की जानकारी और सहमति के बिना संगठन के नाम का गलत उपयोग करते हुए एक अनाधिकृत बैठक कर ली। इसे संगठनात्मक मर्यादा का उल्लंघन एवं चल रहे छात्र आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास बताया गया।जिला समिति ने स्पष्ट कहा कि ऐसे बाहरी और विघटनकारी तत्व संगठन की एकता, पारदर्शिता और संघर्षशील छवि को नुक़सान पहुँचाने में लगे हैं, जिसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस मामले की समीक्षा कर प्रतिवेदन केंद्रीय समिति को भेज दिया गया है और दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई है।आदिवासी छात्रसंघ ने कहा कि संगठन छात्र-युवा हित, शिक्षा अधिकार, छात्रवृत्ति भुगतान, रोजगार और संविधानिक अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करता आया है और भविष्य में भी संगठित रूप से अपनी लड़ाई जारी रखेगा। समिति ने छात्र-युवाओं व समर्थकों से अपील की कि अफवाहों से दूर रहें और केवल संगठन के आधिकारिक निर्णयों पर ही भरोसा करें।बैठक में संगठन को मजबूत करने, बसों में छात्र-छात्राओं से होने वाली छेड़खानी तथा छात्रसंघ मिलन समारोह को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, गांव में शोक की लहर

कोलेबिरा। कोलेबिरा थाना क्षेत्र के शाहपुर पंचायत अंतर्गत चयोटोली चर्च के समीप बने जलमीनार पर मंगलवार सुबह एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान 21 वर्षीय एरिक कुल्लू, पिता प्रताप कुल्लू, राजस्व ग्राम शाहपुर चयोटोली निवासी के रूप में हुई है। घटना से पूरे गांव में शोक की लहर व्याप्त हो गई है।परिजनों ने बताया कि सोमवार की रात खाना खाने के बाद सभी लोग सो गए थे। सुबह लगभग 5:30 बजे उठने पर एरिक घर पर नहीं मिला। परिजनों ने आसपास खोजबीन शुरू की, जिसके बाद घर से थोड़ी दूरी पर स्थित जलमीनार पर उसे रस्सी के फंदे से झूलते हुए देखा गया।

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की राशि का वितरण संपन्न

- **सिमडेगा की 89,935 बहनों को मिला लाभ**

नवीन मेल संवाददाता

सिमडेगा। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत नवंबर 2025 माह की सम्मान राशि का वितरण सिमडेगा जिले में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। जिले की कुल 89,935 लाभुक बहनों को प्रति लाभुक 2,500 रुपये की दर से राशि उनके बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की गई। आधार आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से कुल 22,48,37,500 की राशि सुरक्षित रूप से ट्रांसफर की गई। प्रखंडवार लाभुकों में ठेठईटांगर 14,826, बानो 12,423, सिमडेगा 12,040, कोलेबिरा 9,740, जलडेगा 9,002, कुरडेग 6,700, नगर परिषद 6,104, पाकरटांड़ 6,138, केरसई 5,307, बांसजोर 4,008 और बोलबा 3,647 लाभुक शामिल हैं। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने बताया कि भुगतान प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी की गई और सभी लाभुकों तक समय पर राशि पहुंची। योजना से जिले की हजारों बहनों को आर्थिक सशक्तिकरण मिल रहा है।

अतिक्रमण हटाओ | अतिक्रमण को लेकर दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार करे सरकार : विधायक भूषण बाड़ा

गरीबों की आजीविका प्रभावित, व्यवस्था की उठी मांग

- **फुटपाथ, ठेला और अस्थायी दुकानों पर निर्भर परिवार बिना विकल्प के बेघर हो रहे**

नवीन मेल संवाददाता

सिमडेगा। विधायक भूषण बाड़ा ने विस सत्र के शून्यकाल में जिला मुख्यालय में लगातार चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर कड़ी आपत्ति और गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह अभियान जिस तरह से बार-बार चलाया जा रहा है, इससे शहर की व्यवस्था तो प्रभावित होती ही है। साथ ही उन गरीब परिवारों की आजीविका पर भी सीधा असर पड़ रहा है जो फुटपाथों, छोटे ठेलों या अस्थायी दुकानों के सहारे अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। विधायक ने कहा कि यह लोग मजबूरी में सड़क किनारे दुकान लगाते हैं क्योंकि प्रशासन की ओर से इन्हें अब तक कोई वैकल्पिक या सुरक्षित ठिकाना उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसे में अचानक अभियान चलाकर इन्हें हटाना इन परिवारों के सामने भूखमरी जैसी स्थिति खड़ी कर देता है। विधायक भूषण बाड़ा ने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई एक अस्थायी व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार गरीबों के लिए उचित जगह, व्यवस्थित हाट-बाज़ार, स्थायी दुकान या पुनर्वास की तैयारी नहीं करती, तब तक हर बार की कार्रवाई केवल कमजोर और गरीब तबके को ही नुकसान पहुंचाएगी। शहर की सुंदरता और व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर गरीबों का हक़ छीना जाना किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। विधायक ने सरकार से आग्रह किया कि वह जल्द से जल्द दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार करे। जिसमें अतिक्रमण की समस्या के साथ-साथ गरीब परिवारों के पुनर्वास, आजीविका सुरक्षा और शहर के व्यवस्थित विकास तीनों का संतुलित समाधान हो। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन सही नीति बनाकर आगे बढ़े, तो शहर भी सुव्यवस्थित हो सकता है और गरीबों का जीवन भी सुरक्षित रह सकता है। विधायक ने शहरी क्षेत्र में मार्केट कंपलेक्स निर्माण कराने की भी मांग की है।

स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार कराने की विधायक ने रखी मांग

सिमडेगा। विधायक भूषण बाड़ा ने अपने विस सत्र के तारांकित प्रश्न के माध्यम से जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार कराने की सरकार से मांग की है। विधायक ने सत्र के माध्यम से सरकार से पूछा है कि जिले के लोग एकमात्र सदर अस्पताल के भरोसे जीवन गुजार रहे हैं। लेकिन यहां भी चिकित्सकों को भारी कमी है। सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में लंबे समय से चिकित्सक नहीं रहने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। साथ ही मरीजों के समक्ष गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। विधायक के सवाल पर सरकार द्वारा बताया कि जिले में सदर अस्पताल के अलावे छह सीएचसी है। जहां कुल 19 चिकत्सक पदस्थापित हैं। वहीं सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में चिकित्सकों के रोस्टर के अनुसार ब्लड बैंक का कार्य संचालित किया जा रहा है। साथ ही रक्त की जांच स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा नियमित रुप से किया जा रहा है। साथ ही सदर अस्पताल में मरीजों का समय पर समुचित उपचार भी किया जा रहा है। सरकार ने बताया कि चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

न्यूज बॉक्स

जन वितरण प्रणाली दुकानदारों की बैठक 20 को शत-प्रतिशत राशन वितरण का निर्देश

जलडेगा। प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार कक्ष में जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी डॉ प्रवीण कुमार कि अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीडीओ ने स्पष्ट निर्देश दिया कि 20 दिसंबर तक सभी कार्डधारियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी कार्ड धारियों जिनमें ग्रीन राशन कार्डधारी भी शामिल हैं उनके बीच निर्धारित मात्रा में राशन का शत-प्रतिशत वितरण हर हाल में पूरा किया जाए।इसके साथ ही बैठक में यह भी बताया गया कि जिन लाभुकों और उनके परिवार के सदस्यों का ई-केवाईसी अब तक लंबित है, उनका काम दिसंबर माह के अंत तक हर हाल में पूरा किया जाए ताकि किसी भी लाभुक को राशन मिलने में बाधा न आए।अधिकारियों ने सभी दुकानदारों से समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करने, पारदर्शिता बनाए रखने और ई-केवाईसी अभियान को तेजी से पूरा कराने का निर्देश दिया।

बानो के जेएलकेएम कार्यकर्ता विधानसभा घेराव कार्यक्रम में हुए शामिल

बानो। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा द्वारा रांची में आयोजित विधानसभा घेराव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बानो प्रखंड कमिटी के सदस्य मंगलवार को रांची पहुंचे। बानो प्रखंड अध्यक्ष रविंद्र सिंह, बुद्धिजीवी मोर्चा अध्यक्ष बनेश्वर सिंह, छात्र संघ अध्यक्ष गोपाल सिंह, सीताराम भुइंया सहित अन्य पदाधिकारी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।प्रखंड अध्यक्ष रविंद्र सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि छात्रों व युवाओं के हित में आवश्यक फंड उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। इसके कारण युवा मजबूर होकर पलायन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता की आवाज सदन तक पहुंचाने और सरकार का ध्यान बुनियादी समस्याओं की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से यह घेराव कार्यक्रम आयोजित किया गया है।रविंद्र सिंह ने बताया कि प्रस्थान से पूर्व प्रतिनिधिमंडल ने डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो से मुलाकात कर बानो प्रखंड की विभिन्न समस्याओं से उन्हें अवगत कराया।

शिव मंदिर व बजरंगबली का वार्षिक उत्सव 11 से 13 जनवरी तक, तैयारियां अंतिम चरण में

बोलबा। बोलबा प्रखंड के लेटाबेड़ा स्थित शिव मंदिर और बजरंगबली मंदिर में होने वाले वार्षिक धार्मिक महोत्सव की तैयारियाँ पूरी रफ्तार पर हैं। आयोजन समिति ने बताया कि तीन दिवसीय महोत्सव 11 जनवरी से 13 जनवरी तक भक्तिभाव और श्रद्धा के साथ आयोजित किया जाएगा। समिति अध्यक्ष हीरालाल प्रधान ने कहा कि उत्सव की शुरुआत 11 जनवरी को कृष्ण पक्ष माघ अष्टमी पर कलश यात्रा से होगी, जिसके बाद अधिवास पूजन और रात्रि 8 बजे से 36 घंटे का अखंड हरि-कीर्तन एवं नाम-यज्ञ प्रारंभ होगा।12 जनवरी को गणेश प्रतिमा स्थापना, जलाभिषेक, अन्न-अभिषेक और देव प्रतिमाओं की प्राण-प्रतिष्ठा सहित विभिन्न पूजन कार्यक्रम संपन्न होंगे। रात्रि 7 बजे भव्य महाआरती तथा 8 बजे से 11 बजे तक वाराणसी के आचार्य सनातन पाठक प्रवचन देंगे। मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष कौशल राज सिंह देव और बाबा उमाकांत महाराज आमंत्रित रहेंगे।13 जनवरी को शोभायात्रा, हवन-पूजन, पूर्णाहुति, महाप्रसाद एवं महाभंडारा आयोजित होगा।

बांसजोर में आयुष विभाग की ओर स्वास्थ्य कैंप आयोजित

बांसजोर। सिहरजोर साप्ताहिक बाजार परिसर के समीप मंगलवार को आयुष विभाग के जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डॉ सुभद्रा कुमारी के निर्देश पर ऑस्टियोआर्थराइटिस एवं मस्कुलोस्केलेटल स्वास्थ्य कैंप आयोजित किया गया। कैंप में डॉ इंजमामुल हक खान ने 125 मरीजों की जांच कर कमर, पीठ, गर्दन, पैर दर्द, खुजली तथा अन्य बीमारियों के लिए निशुल्क दवा वितरित की कैंप में योग प्रशिक्षक कार्तिक द्विवेदी और बसंती कछुआ ने विभिन्न रोगों के अनुरूप योगाभ्यास की जानकारी दी तथा लोगों को दैनिक योग और प्राणायाम अपनाने के लिए प्रेरित किया। मौके पर सहिया दीदी मंडलेन बरवा, सुहावनी बुढ़, चोनहांती किडो, उकौली केरकेट्टा, हिलेरिया केरकेट्टा सहित बड़ी संख्या में मरीज उपस्थित रहे।

सुपर लीग टूर्नामेंट: छठे दिन बारूद क्रिकेट क्लब व फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब की जीत

सिमडेगा। मंगलवार को सिमडेगा जिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा शहर के अलबर्ट एक्का स्टेडियम में आयोजित सुपर लीग टूर्नामेंट के छठे दिन दो मुकाबले खेले गए। पहले मैच में खालसा क्रिकेट क्लब का सामना बारूद क्रिकेट क्लब से हुआ। बारूद क्रिकेट क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 40 ओवर में 8 विकेट पर 215 रन बनाए। जवाब में खालसा क्रिकेट क्लब 23.3 ओवर में 122 रन पर सिमट गई। बारूद क्रिकेट क्लब ने 83 रन से जीत दर्ज की। अर्जुन कुमार मैन ऑफ द मैच घोषित हुए।दूसरे मैच में फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब और यूनाइट क्रिकेट क्लब आमने-सामने थे। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब ने 28.1 ओवर में 185 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए यूनाइट क्रिकेट क्लब 20.3 ओवर में 120 रन पर ऑल आउट हो गई। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब ने 65 रन से जीत दर्ज की। उत्कर्ष सक्सेना को मैन ऑफ द मैच चुना गया।

कोलेबिरा विधायक नमन बिक्सल कोनगाड़ी ने विधानसभा में उठाए जनसरोकार के मुद्दे

सिमडेगा। विधायक नमन बिक्सल कोनगाड़ी ने झारखंड विधानसभा के सदन में अपने क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि ठेठईटांगर, बोलबा, जलडेगा, बांसजोर सहित कई प्रखंडों में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। हाथी घरों को तोड़-फोड़ कर नुकसान पहुँचा रहे हैं, अनाज नष्ट कर देते हैं और कई स्थानों पर जनहानि भी हुई है। यहां तक कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी हाथियों के आने से घंटों जाम की स्थिति बनती है। लोग रात भर जागकर भय के साए में जीवन जीने को मजबूर हैं, जिससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विधायक ने मांग की कि सरकार प्रभावित परिवारों को पटाखा, टॉर्च, जूट मोबिल जैसे सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए और दीर्घकालिक समाधान निकाले।विधायक ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से सिमडेगा सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड और ईको मशीन मौजूद होने के बावजूद रेडियोलॉजिस्ट/सोनोलॉजिस्ट व तकनीशियन के अभाव का मुद्दा भी उठाया। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया।पर्यटन विकास पर जोर देते हुए विधायक ने ठेठईटांगर प्रखंड स्थित रचाकोना टोंगरी को आकर्षक प्राकृतिक स्थल बताते हुए इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यहां प्रतिवर्ष मेला लगता है, लेकिन सड़क, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी है। इस पर पर्यटन विभाग ने भी सकारात्मक जवाब दिया।

जीएससीसी योजना में लापरवाही बरतने वाले बैंक अधिकारियों पर करें कार्रवाई: विधायक

सिमडेगा। विधायक भूषण बाड़ा ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के क्रिवान्वयन में बैंक अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरते जाने को लेकर भी विधानसभा सत्र में सवाल उठाया है। विधायक ने कहा है कि जिले में गरीब एवं मेघावी छात्रों के उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना संचालित है। लेकिन बैंक अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरते जाने बहुतायत गरीब एवं मेघावी छात्रों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। विधायक ने छात्रों को योजना का लाभ देने एवं दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस पर विधायक को बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बैंकों द्वारा 1028 एवं वर्ष 2025-26 में 1065 अनुमोदित आवेदनों के बिरुद्ध लोन विद्यार्थियों के बीच लोन वितरण किया गया है। इसके अतिरिक्त 1146 आवेदनों पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। योजना के सुचारु क्रियान्वयन हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित है।

मौत का बदला मौत, मुरहू में बदले के लिए हुई हत्या मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार

नवीन मेल संवाददाता

खूंटी। मुरहू थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज सीनू पूर्ति हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों में मंगरा मुंडा उर्फ दशाय मुंडा, किनु पूर्ति और सोम मुंडा शामिल हैं. इनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुदाल बरामद कर लिया गया है. एसपी मनीष टोप्पो ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हत्याकांड का खुलासा किया है. एसपी ने बताया कि मृतक की बहन मांगी कुमारी ने लिखित आवेदन देकर बताया था कि उसका भाई 22 वर्षीय सीनू पूर्ति एक दिसंबर को अपने दोस्त सुंबर भेंगरा के साथ घर से निकला था. लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटा था. मोबाइल से पूछने पर सीनू ने बताया था कि वह अपने चाचा मंगरा मुंडा के घर पर है, जहां सुंबर भेंगरा, सुनील भेंगरा और मंगरा मुंडा मिलकर उससे मारपीट कर रहे हैं. इसके बाद सीनू पूर्ति का मोबाइल बंद हो गया और वह लापता हो गया. तीन दिसंबर को ग्राम इट्ठठे के सड़गीगढ़ा में एक गड्ढे से मानव पैर दिखाई देने पर पुलिस ने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव बरामद किया. जिसकी पहचान सीनू पूर्ति के रूप में हुई. मामले में मुरहू थाना कांड संख्या 69/25 दर्ज कर एसपी के निर्देश पर टीम गठित की गई. टीम ने सात दिसंबर को आरोपी मंगरा मुंडा उर्फ दशाय मुंडा, किनु पुर्ति और सोम मुंडा को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त कुदाल बरामद किया. पूछताछ में अभियुक्तों ने पुलिस के समक्ष स्वीकार किया कि वर्ष 2022 में मंगरा मुंडा के बेटे कानु मुंडा का अपहरण कर धारदार हथियार से गला काटकर दफना दिया गया था. इस कांड में सीनु पुर्ति, सागर मुंडा, अनमोल टूटी, जयमसीह ओडेया और अमरजीत पूर्ति शामिल था. आरोपियों ने इसी बदले की भावना से सीनू की हत्या कर शव को दफना दिया था.

आपत्तिजनक तस्वीर शेयर करने के आरोप में युवक गिरफ्तार

चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम की जगन्नाथपुर थाना पुलिस ने साइबर अपराध और ब्लैकमेलिंग के संगीन मामले को लेकर कार्रवाई की है. पुलिस ने आरोपी 39 वर्षीय मो. शमसेर अली उर्फ शमसेर आलम को बिहार के औरंगाबाद जिले के कासमा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है. आरोपी पर पीड़िता की आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल कर 5 लाख रुपए की उगाही करने और मानसिक प्रताड़ना का आरोप है. सूत्रों के अनुसार पीड़िता ने लिखित शिकायत में बताया कि आरोपी ने लॉकडाउन के दौरान अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क स्थापित कर शादी का भरोसा दिलाया था. लेकिन वर्ष 2023 में आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया था. इसके बाद पता चला कि आरोपी के भाई निसार अली ने उसकी शादी बिहार की किसी दूसरी लड़की से करा दी. शिकायत के मुताबिक शादी से इनकार के बाद आरोपियों ने पीड़िता की आपत्तिजनक एडिटेड तस्वीरें वायरल कर दी. इसके साथ ही उन्हें हटाने के बदले पीड़िता से 5 लाख रुपए की मांग की गई. रकम नहीं देने पर लगातार धमकियों के कारण पीड़िता मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो गई. घटना पर पुलिस ने जगन्नाथपुर थाना कांड संख्या 73/25 (दिनांक 04 दिसंबर 2025) दर्ज किया. जिसमें आईटी एक्ट 2000 सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पश्चिमी सिंहभूम पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीपीओ जगन्नाथपुर के नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम गठित की गई. तकनीकी सेल की मदद से आरोपी को पुलिस ने 8 दिसंबर 2025 (सोमवार) को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से एक स्मार्टफोन और पीड़िता की आपत्तिजनक तस्वीरें बरामद हुईं, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है. इसके साथ ही पुलिस ने आम जनता से कहा कि सोशल मीडिया पर अनजान व्यक्तियों से निजी जानकारी या तस्वीरें साझा न करें.

शिक्षा के क्षेत्र में जिला प्रशासन हजारीबाग की नई पहल

छात्रों को मिलेगी निःशुल्क सरल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा : उपायुक्त

नवीन मेल संवाददाता

हजारीबाग/बरही । शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने तथा विद्यार्थियों तक सरल व सुलभ शिक्षण सामग्री पहुँचाने के उद्देश्य से उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह की पहल पर जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए "Hazaribag Educates" नामक यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री कार्यालय एवं सूचना जन संपर्क विभाग झारखंड के मार्गदर्शन में शुरू की गई यह पहल जिले सहित पूरे राज्य के विद्यार्थियों के लिए बेहद उपयोगी मानी जा रही है। इस यूट्यूब चैनल पर अनुभवी, योग्य और विषय-विशेषज्ञ शिक्षक कला, विज्ञान और गणित जैसे प्रमुख विषयों के अध्यायों को सरल, स्पष्ट और सहज भाषा में समझा रहे हैं। कठिन विषयों को आसान तरीके से प्रस्तुत किए जाने के कारण यह चैनल प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी लाभदायक सिद्ध होगा। जिला प्रशासन का मानना है कि डिजिटल माध्यम से शिक्षण सामग्री उपलब्ध होने से दूर-दराज क्षेत्रों के बच्चे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक आसानी से पहुँच सकेंगे। उपायुक्त के अनुसार चैनल का उद्देश्य शिक्षा के अवसरों को सबके लिए समान बनाना और विद्यार्थियों को बेहतर भविष्य के लिए सशक्त करना है। प्रशासन ने सभी छात्र-छात्राओं, अभिभावकों, शिक्षकों और युवाओं से अपील की है कि वे इस शैक्षणिक पहल से अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और अन्य लोगों को भी जोड़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि ज्ञान की रोशनी हर घर तक पहुँचे।
हजारीबाग एजुकेट्स चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन ने डिजिटल शिक्षा को नई दिशा देने का प्रयास किया है, जो आने वाले समय में शिक्षण व्यवस्था को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा।

पैसे के लिए आईआरबी के जवान ने की चचेरे दादा की हत्या

साहिबगंज। पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के तालबन्ना निवासी विश्वनाथ गुप्ता की हत्या का मामला सुलझा लिया है. विश्वनाथ गुप्ता के चचेरे भाई के पोते सुमित कुमार गुप्ता ने अपने दोस्त अमन जायसवाल के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था. सुमित आईआरबी का जवान है. सुमित ने बिहार के मधेपुरा के रहने वाले अपने दोस्त अमन के साथ मिलकर विश्वनाथ गुप्ता के बैंक अकाउंट से पैसे निकालने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया. अमन भी आईआरबी में ही नौकरी करता है. इस मामले में दुमका जिले के जरमुंडी थाना क्षेत्र के हटिया टोला निवासी सोहित कुमार राउत को भी गिरफ्तार किया गया है. इन सभी को देर शाम जेल भेज दिया गया. एसपी अमित कुमार सिंह ने पूरी घटना की जानकारी दी. एसपी ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,24,000 रुपये नकद, गहने, बैंक अकाउंट के सभी दस्तावेज, सात मोबाइल फोन, एक पिस्तौल और चार जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.

उपायुक्त के जनता दरबार में सुनी आमजनों की समस्याएं

दिए त्वरित समाधान के निर्देश

- उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी आवेदन निर्धारित समयसीमा में निष्पादित किए जाएं

नवीन मेल संवाददाता

हजारीबाग। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में आज समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण अपने आवेदन एवं शिकायतों के साथ उपस्थित हुए। उपायुक्त ने प्रत्येक आवेदक की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित पदाधिकारियों को मामलों के त्वरित एवं संवेदनशील निपटारे का निर्देश दिया। जनता दरबार में मुख्य रूप से पेंशन स्वीकृति, राशन कार्ड त्रुटि सुधार, आवास, आपूर्ति व्यवस्था, भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, रोजगार एवं विभिन्न योजनाओं से जुड़ी शिकायतें सामने आईं। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी आवेदन निर्धारित समयसीमा में निष्पादित किए जाएं।

जमीन अधिग्रहण से जुड़ा मामला (केरेडारी): मोहन कुमार ने एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहित भूमि के बाद विस्थापन मुआवजा दिलाने का अनुरोध किया। उपायुक्त ने एनटीपीसी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

भूमि विवाद एवं अतिक्रमण (डाड़ी) : मनोहर साव ने पैतृक भूमि पर जबरन अतिक्रमण और दबंगई की शिकायत दर्ज कराई। उपायुक्त ने एसडीओ, को मामले की जांच कर शीघ्र कार्रवाई करने का आदेश दिया।

कृषि में सौर ऊर्जा सुविधा (बरही): पंचम महतो ने पीएम-कुसुम योजना के तहत सोलर पंप उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। इस पर उपायुक्त ने कृषि विभाग को आवश्यक सहयोग करने का निर्देश दिया।

रोजगार व विस्थापन से जुड़ा अनुरोध (बड़कागांव): रोशन कुमार ने गरीबी और बेरोजगारी से निजात दिलाने तथा एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहित भूमि के बाद बाहरी स्रोत से रोजगार की मांग की। उपायुक्त ने इस पर डीएएलओ एवं एसडीओ को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया।

खाशमहल भूमि लीज नवीकरण (सदर प्रखंड): एक आवेदक ने खाशमहल भूमि का लीज नवीकरण न होने की शिकायत की। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री शशि प्रकाश सिंह ने कहा कि "प्रशासन का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान करना है। सभी अधिकारी जनता की शिकायतों को प्राथमिकता पर लेकर निर्धारित समयसीमा में निष्पादित करें।"

अस्पताल में चोरी का मामला विधानसभा में उठा

दुमका। जिला में हंसडीहा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में चोरी के मामले ने तूल पकड़ लिया है. मंगलवार को झारखंड विधानसभा शीत सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के द्वारा कार्रवाई की मांग की गयी. इसके बाद इस मामले की जांच में तेजी आ गयी. एसपी और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने अस्पताल पहुंच कर जांच की और एसआईटी गठित करने की बात कही. वैसे दो दिन पूर्व जब चोरी का यह बड़ा मामला सामने आया, उसके दूसरे दिन से स्वास्थ्य विभाग और पुलिस द्वारा अपने-अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है. आज मंगलवार को जब मामला विधानसभा में प्रदीप यादव के द्वारा उठाया गया उसके बाद जांच में और तेजी नजर आई. साथ ही घटनास्थल पर फिंगरप्रिंट जुटाने के लिए एएसआई सुखदेव महतो और सीताराम विश्वकर्मा अपनी टीम के साथ पहुंचे. एसपी ने टीम के साथ पूरे परिसर का निरीक्षण किया और वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्र करने के निर्देश दिए।

प्लंबर सिकंदर प्रसाद हत्या मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार

- 19 नवंबर 2025 को रामजड़ी बाजार में चोरी के आरोप लगाते हुए अज्ञात युवकों ने सिकंदर प्रसाद की बुरी तरह पिटाई कर दी थी

नवीन मेल संवाददाता

कोलेबिरा। प्लंबर सिकंदर प्रसाद की हत्या मामले में कोलेबिरा पुलिस ने मंगलवार को एक और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी के अनुसार,19 नवंबर 2025 को रामजड़ी बाजार में चोरी के आरोप लगाते हुए अज्ञात युवकों ने सिकंदर प्रसाद की बुरी तरह पिटाई कर दी थी। गंभीर रूप से घायल सिकंदर का इलाज रिम्स,रांची में चल रहा था, जहां 25 नवंबर 2025 को उसकी मौत हो गई।घटना के बाद मृतक की पत्नी मुन्नी देवी ने कोलेबिरा थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।यह मामला कांड संख्या 89/25 के रूप में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 126(2), 191(2), 190, 103(1), 3(5) के तहत दर्ज किया गया।पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 28 नवंबर को इस कांड में सम्मिलित दो आरोपियों एसेज डांग,अनिल डांग (दोनों पोगलोया वरटांड़, पंचायत ऐडेगा,प्रखंड कोलेबिरा)को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।वहीं,मंगलवार को पुलिस ने एक और आरोपी निरल सुरिन (उम्र 28 वर्ष),पिता स्व. मरसलन सुरिन,निवासी टंगराटोली

80 हजार में कर दिया था नाबालिग का सौदा

दुमका। जिला में सरैयाहाट थाना क्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर बिहार के मोतीहारी में 80 हजार रुपए में बेच देने का मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है. जिसमें नाबालिग की बरामदगी के साथ चार लोगों को गिरफ्तार कर विगत सोमवार को जेल भेज दिया. जिसमें एक युवक और तीन महिलाएं शामिल हैं. गिरफ्तार लोगों में मोतीहारी जिला के राजेफुर थाना क्षेत्र के सगहरी गांव के अरुण सिंह, चुड़की देवी, पार्वती देवी (दुमका के सरैयाहाट थाना क्षेत्र की रहनेवाली) और गोड्डा जिला के बक्सरा गांव की पिंकी देवी शामिल है.

सड़क दुर्घटना में पिता-पुत्र की मौत

बोकारो। जिले में एक सड़क हादसे में पिता और बेटे की मौत हो गई, आरोप है कि इसमें ओएनजीसी की गाड़ी शामिल थी. परिवार के लोग और गांव वाले पिता और बेटे के शवों को ओएनजीसी गेट के सामने रखकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. परिवार का आरोप है कि हादसे के बावजूद ओएनजीसी का कोई भी अधिकारी जिम्मेदारी लेने के लिए आगे नहीं आया है. यह घटना कल रात हुई. पिता और बेटा बोकारो के बंगड़िया ओपी क्षेत्र के पर्वतपुर ब्लॉक के पास एक शादी में जा रहे थे, तभी उन्हें एक स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी. मृतकों की पहचान कैलाश सिंह और उनके बेटे कृष्ण सिंह के रूप में हुई है, दोनों स्थानीय निवासी थे. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. परिवार को सुबह घटना की जानकारी मिली और वे मौके पर पहुंचे, जहां उन्हें शव मिले. इसके बाद परिवार और गांव वाले शवों को लेकर पर्वतपुर कोल ब्लॉक में ओएनजीसी गेट के सामने विरोध प्रदर्शन करने लगे. परिवार और गांव वालों का आरोप है कि यह हादसा ओएनजीसी की गाड़ी से हुआ, जिससे पिता और बेटे की मौत हो गई. प्रदर्शनकारी मृतकों के परिवार के लिए मुआवजे और नौकरी की मांग कर रहे हैं.

विभावि के राजनीति विज्ञान विभाग में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

भ्रष्टाचार न केवल आर्थिक विकास में बाधक है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करता है : डॉ प्रमोद

- युवाओं से आह्वान किया कि वे पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी को अपने व्यवहार और कार्यशैली का हिस्सा बनाकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं

नवीन मेल संवाददाता

हजारीबाग। विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हज़ारीबाग के राजनीति विज्ञान विभाग के सेमिनार हॉल में मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस के अवसर पर एक खाली विनोद को बोल सकते हो जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस वर्ष का वैश्विक थीम– "भ्रष्टाचार के विरुद्ध युवाओं की एकजुटता : आने वाले कल की ईमानदारी के निर्माण की दिशा में" कार्यक्रम के केंद्र में रहा। मुख्य वक्ता के रूप में विभाग के प्राध्यापक डॉ. प्रमोद कुमार ने उपस्थित छात्रों और शोधार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार न केवल आर्थिक विकास में बाधक है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी को अपने व्यवहार और कार्यशैली का हिस्सा बनाकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं। उन्होंने भ्रष्टाचार के चार "पी" पर भी जानकारी दी अर्थात, प्रेफरेंस, पावर प्रिविलेज और पेमेंट। कार्यक्रम की अध्यक्षता विभाग के अध्यक्ष डॉ. सुकल्याण मोइत्रा ने की। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी चुनौती है कि इस मामले में समाज में जागरूकता और सही समझा की कमी है। इस विषय की सही समझ को साझा करने के लिए ही ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन आवश्यक है। उन्होंने विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित 180 राष्ट्रों की भ्रष्टाचार सूचकांक के बारे में जानकारी दी। इस सूचकांक के अनुसार सोमालिया, दक्षिण सूडान और वेनेजुएला में भ्रष्टाचार सबसे अधिक है। वही डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर, न्यू जीलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड तथा स्वीडन इस सूची में सर्वोच्च स्थान पर है जहां भ्रष्टाचार नहीं के बराबर है। बताया कि भारत का स्थान इस सूची में 93वां है जिसे सुधारने की सख्त जरूरत है। भारत में बदलाव तभी हो सकेगा जब आज के युवा, अर्थात भविष्य का भारत, इस ओर जागरूक होंगे और नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। संगोष्ठी का संचालन शोधार्थी प्रतीक कुमार ने किया।

AFFIDAVIT

I RANJU KUMARI W/O NAKUL KUMAR MAHTO, aged about-26 years, by Caste-Kurmi (Mahto), by faith-Hindu, R/o village+P.O.-Narayanpur, P.S.-Penk (Narayanpur), Dist. Bokaro, State-Jharkhand do hereby solemnly affirm and declare as follows:-

That my nationality is Indian. That my Aadhar Number is 2008 7929 1322. That I passed Matric Examination-2015 (JAC-BOARD) from BINOD HIGH SCHOOL-AOURA P.S. Bagodar Dist. Giridih Vide Candidate Name- ANJU KUMARI father's name-CHETLAL MAHTO, MOTHER'S NAME-KESHO DEVI, Roll Code-22082, Roll No. 0067 Registration No. 22082-22910-13, Admission Card No. 2130136 D.O.B.-4/9/1999. That I am known by two names viz; (i) ANJU KUMARI D/O CHETLAL MAHTO, (ii) RANJU KUMARI W/O NAKUL KUMAR MAHTO.

That aforementioned both names represent to one and same person i.e. myself. That my name is mentioned as RANJU KUMARI W/O NAKUL KUMAR MAHTO in my said Aadhar Card, while ANJU KUMARI D/O CHETLAL MAHTO is mentioned in my said educational certificate. That my paternal house is situated at ISRI BAZAR KURMI TOLA P.S. Nimiyaghat Dist. Giridih. That I want to rectify my name as ANJU KUMARI in place of RANJU KUMARI in my said Aadhar card. That contents of this affidavit are true correct and genuine, if any statement found false or contrary then I shall be liable to punish.

I, RANJU KUMARI do hereby declare that the statement made in the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge information and belief.

Affidavit No. 8026, Date:- 04/12/2025

विस्थापित | केंदुआडीह इलाका खतरे से खाली नहीं, घरों पर चिपकाया गया नोटिस

क्षेत्र को असुरक्षित बताते हुए शिफ्टिंग के लिए अपील की

- लोगों का कहना है कि वर्षों से हम यहां रह रहें हैं, बीसीसीएल को गैस रोकने की उपाय करने की जरूरत है ना कि यहां से हटाने की

नवीन मेल संवाददाता

धनबाद। जिला के केंदुआडीह में गैस रिसाव को लेकर बीसीसीएल प्रबंधन लगातार लोगों को आगाह कर रही है. इसी दिशा में बीसीसीएल प्रबंधन ने सोमवार के दिन को गैस से प्रभावित इलाके के उन सभी घरों की दीवार पर नोटिस चिपकाया. बीसीसीएल ने क्षेत्र को असुरक्षित बताते हुए लोगों शिफ्टिंग के लिए अपील की है. इस नोटिस में साफ-साफ लिखा है कि यह क्षेत्र असुरक्षित है, वर्तमान स्थिति में यहां रहना खतरनाक है. गैस की वजह से जान का खतरा है. प्रबंधन के काफी प्रयासों के बावजूद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है. इसलिए लोग फिलहाल इस क्षेत्र में न रहें. बीसीसीएल की ओर से लगाए जा रहे ये नोटिस प्रभावित क्षेत्र के हर घर की दीवारों पर चिपकाया जा रहा हैं, ताकि लोगों को जान माल का नुकसान ना हो. स्थानीय लोगों ने बीसीसीएल के द्वारा चिपकाए जा रहे पोस्टर का विरोध जता रहे हैं. लोगों का कहना है कि वर्षों से हम यहां रह रहें हैं, बीसीसीएल को गैस रोकने की उपाय करने की जरूरत है ना कि यहां से हटाने की, हर हाल में यह जगह छोड़कर नहीं जाएंगे. वहीं दूसरी ओर केंदुआडीह में जहरीली गैस रिसाव मामले को लेकर एनडीआरएफ की एक्सपर्ट टीम के साथ डीसी ने महत्वपूर्ण बैठक की. प्रभावित इलाके की लगातार रिपोर्ट और लोगों के विस्थापन को लेकर गंभीरता जताई. डीसी आदित्य रंजन ने एनडीआरएफ की एक्सपर्ट टीम कई निर्देश भी दिए हैं.

- डीसी की एनडीआरएफ के अधिकारी के साथ बैठक

डीसी ने कहा कि स्थिति संवेदनशील है और प्रत्येक मिनट का प्रभाव सीधे प्रभावित परिवारों की सुरक्षा से जुड़ा है. जिसे लेकर डीसी ने 2 मजिस्ट्रेट और 40 सुरक्षा बलों की तैनाती प्रभावित क्षेत्रों में करने का आदेश दिया है. निगरानी और व्यवस्था में कोई कठिनाई हो इसके मद्देनजर डीसी के द्वारा सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। धनबाद डीसी आदित्य रंजन का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित लोगों को बेलगड़िया और कर्माटांड़ टाउनशिप में शिफ्टिंग कराया जाना है. शिफ्टिंग का चयन लोग खुद कर सकते हैं.

लोगों का विस्थापन से इनकार, कहा मर जाएंगे, लेकिन नहीं छोड़ेंगे जमीन

या करमाटांड में शिफ्ट होने के लिए कह रहा है, लेकिन यह उनकी आजीविका के लिए संभव नहीं है. ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से कहा कि वे पीढ़ियों से इसी केंदुआडीह बस्ती में रह रहे हैं. उन्हें विस्थापित करने के बजाय,बीसीसीएल प्रबंधन को गैस निकालने के अपने प्रयासों को तेज करना चाहिए. अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हुए, लोगों ने बताया कि उन्हें बेलगड़िया या करमाटांड में न तो रोजगार मिलेगा और न ही कोई अन्य सुविधाएं. इसलिए, केंदुआडीह छोड़ने के बाद उनके लिए कहीं और रहना असंभव होगा. स्थानीय मोहम्मद साजिद ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, "हमारा सारा काम और आजीविका इसी इलाके से जुड़ी हुई है. अगर हम कहीं और चले गए तो क्या करेंगे? बीसीसीएल को हमारी समस्या का समाधान करना चाहिए विस्थापन समाधान नहीं है. गौरतलब हो कि गैस लीक की घटना को छह दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन स्थायी समाधान के लिए ठोस कदम न उठाए जाने के कारण लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है. ग्रामीणों ने कहा कि वे बीसीसीएल प्रबंधन से भूमिगत खदान का पंखा चालू करने और गैस निकालने के लिए ड्रिलिंग जैसी मांगें उठा रहे हैं, लेकिन प्रबंधन इन मांगों को गंभीरता से नहीं ले रहा है।

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय,लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या– 27 वर्ष 2025–26

पत्रांक :– गुमला, दिनांक :– 08/12/2025

1. विभाग का नाम :– जल संसाधन (लघु सिंचाई) विभाग, झारखंड सरकार, राँची।
2. विज्ञापन दाता का नाम :– कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला।
3. परिमाण विपत्र की विकी की तिथि :– 17.12.2025 से 18.12.2025 तक (03:00 बजे अपराह्न तक)
4. निविदा प्राप्त करने की तिथि एंव समय :– 19.12.2025 को 03:00 बजे अपराह्न तक
5. निविदा खोलने की तिथि एंव समय :– 19.12.2025 को 03:30 बजे अपराह्न
6. परिमाण विपत्र विकी का स्थान :– (1) कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला। (2) सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई अनुमंडल, गुमला।
7. निविदा प्राप्ति एंव निविदा खोलने का स्थान :– कार्यालय परिसर, लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला।
8. परिमाण विपत्र का मूल्य :– राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जों राष्ट्रीयकृत बैंक, गुमला में भुगतेय हो, मान्य होगा।
9. कार्य की विस्तृत विवरणी :–

ग्रुप सं0	योजना का नाम	प्रखंड	योजना मद का नाम	परिमाण विपत्र की राशि (रू0 में)	अग्रधन की राशि (रू0 में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रू0 में)	कार्य समाप्ति की अवधि	निविदादाता की समुचित श्रेणी
1	ग्राम – औरापाट में Farm based assets creation work का निर्माण कार्य।	डुमरी	Niti Aayog Award Money-PAHAL मद	20,75,800.00	42,000.00	5,000.00	तीन माह	श्रेणी–03
2	ग्राम – औरापाट में Construction of Solar Based Lift Irrigation का निर्माण कार्य।	डुमरी		21,75,900.00	44,000.00	5,000.00	तीन माह	श्रेणी–03
3	औरापाट नाला पर चेकडेम निर्माण।	डुमरी		24,65,500.00	50,000.00	5,000.00	तीन माह	श्रेणी–03
4	Construction of Check wall on Kukurbhuka Nala with Pipeline connection for Irrigation at Village- Lavabar	डुमरी	CSR मद	22,81,900.00	46,000.00	5,000.00	तीन माह	श्रेणी–03

निविदा की शर्तें :– 1. बैंक ड्राफ्ट निबंधित संवेदक के स्वयं के खाता से निर्गत हुआ हो तथा बैंक ड्राफ्ट की वैद्यता अवधि निविदा की प्रकाशन की तिथि से तीन माह तक का हो, मान्य होगा।
2. निविदा प्रपत्र बिकी के समय संवेदक को निबंधन प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र एवं अद्यतन युकेन संलग्न करना अनिवार्य होगा ततपश्चात ही निविदा प्रपत्र निर्गत किया जाएगे।
3. निविदा में 10% न्युनतम दर से अधिक न्युनतम दर उद्धृत करने पर प्राक्कलित राशि का 20% अथवा 30% अतिरिक्त जमा राशि का डाकघर सावधी जमा पासबुक/बैंक द्वारा निर्गत फिक्स डिपोजिट निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
4. **जो निम्न है:–** 1. 10% से 20 प्रतिशत कम दर की राशि का 20% तक।
2. 20% प्रतिशत से अधिक कम दर की राशि का 30% अतिरिक्त जमानत राशि देय होगा।
10. निविदा से संबंधित सभी सूचना अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के सूचनापट पर देखा जा सकता है।

E-mial ID – eemidgum@gmail.com.

कार्यपालक अभियंता,
लघु सिंचाई प्रमण्डल, गुमला

PR 368140 Minor Irrigation(25-26).D

सुप्रभात

विचार प्रवाह

प्रत्येक वस्तु का अपना स्थान होता है, परंतु जब आप अपने सच्चे सुख की उपेक्षा कर समय गंवाते हैं तो यह अच्छा नहीं। मैंने प्रत्येक अनावश्यक कार्य को छोड़ दिया ताकि मैं ध्यान करके ईश्वर को जान सकूं, ताकि मैं दिन और रात उनके दिव्य चैतन्य में मग्न रह सकूं। **- श्री श्री परमहंस योगानंद**

संपादकीय

इंडिगो से सीख और कार्रवाई

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो जिस अभूतपूर्व संकट से गुजर रही है, वह तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही, इससे बेबस यात्रियों को जिस तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वह और भी शर्मनाक है। देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर लाखों यात्री बेहद बुरी स्थितियों में फंसे रहे, किसी की परीक्षा छूटी, किसी की नौकरी का इंटरव्यू, तो कोई गंभीर मरीज डॉक्टर तक वक्त पर नहीं पहुंच सका। इस अफरा-तफरी में एक पिता की अपनी बेटी के लिए सेनेटरी पैड के लिए गुहार तक सुनने वाला कोई नहीं था। यात्रियों के मार्गदर्शन की व्यवस्था किस हद तक चौपट हो सकती है, यह हवाई अड्डों पर फैली अराजकता में साफ दिखा। किसी भी तरह की सेवा में संवेदना अनिवार्य होती है, लेकिन इंडिगो के नियामक तंत्र और सरकार की तरफ से भी इस पूरे संकट को लेकर जैसी धीमी प्रतिक्रिया आती दिखी, वह हैरान करने वाली है। इस तस्वीर को अगर आज की भारतीय मध्यवर्गीय जिंदगी का आईना कहा जाए, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसे अभिशाप कहें या वरदान कि हमने अपने जीवन को इतना तेज बनाया है कि चीजें आपस में उलझ गई हैं, तभी तो एक हवाई अड़चन ने मानो जीवन को ही ठप कर दिया। क्या किसी अन्य कारण से इतने लोग परेशान होते तो सारे माननीय और नेता ऐसे से चुप रहते ? साफ है कि उन्हें वीआइपी व्यवस्था देकर विशिष्ट नागरिक बना दिया गया है जिन्हें सामान्य लोगों की परेशानी से मतलब है। संविधान की मूल अवधारणा के विपरीत है यह।

समस्या की मूल वजह डीजीसीए द्वारा सभी एयरलाइंस के लिए पायलटों व अन्य क्रू सदस्यों के आराम और ड्यूटी के नियमों में किए गए बदलावों को बताया गया। हालांकि, सभी एयरलाइनों के पास नियमों के अनुपालन की तैयारी के लिए करीब बीस महीने का समय था, लेकिन इंडिगो के वरिष्ठ प्रबंधन ने शायद सोचा होगा कि वे अपने विशाल बाजार आकार के बल पर सरकार को नए नियमों को स्थगित करने के लिए मजबूर कर देंगे। इंडिगो आज अकेली नहीं जूझ रही, यह तो बस उस पूरे तंत्र का प्रतिबिंब है, जिसमें हम रह रहे हैं। एक एयरलाइन 65 से 70 फीसदी घरेलू बाजार पर कब्जा जमाए बैठी है, जिसे विशुद्ध अर्थशास्त्र में एकाधिकार कहा जाता है, जिस पर अंकुश लगना चाहिए। इंडिगो बोर्ड को आत्मचिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि उसकी गलतियों की जिम्मेदारी कोई और नहीं ले सकता। जरूरी है कि जो दोषी हैं, उन्हें सजा भी मिले। यह पूरा हंगामा सरकार के लिए भी सबक है। उसकी सख्ती से इंडिगो को यात्रियों को रिफंड देने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन सवाल तो यह भी है कि अगर पहले सक्रियता दिखाई गई होती, तो यह आपदा आती ही क्यों। ऐसे मुद्दों पर राजनीति तो होती है पर सामूहिक स्वर में समाधान की बात क्यों नहीं उठती?

इंडिगो बोर्ड को आत्मचिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि उसकी गलतियों की जिम्मेदारी कोई और नहीं ले सकता। जरूरी है कि जो दोषी हैं, उन्हें सजा भी मिले। यह पूरा हंगामा सरकार के लिए भी सबक है।

गैर-नागरिक मतदाता नहीं हो सकते

कांग्रेस और भाजपा के विरोध में खड़े अन्य दलों के नेता भारत के चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का जोरदार विरोध कर रहे हैं। हालांकि, संविधान और संसद से बनाए गए कानून चुनाव आयोग को समय-समय पर मतदाता सूची को अपडेट और संशोधित करने की जिम्मेदारी देते हैं, फिर भी ये पार्टियां इस प्रक्रिया का कड़ा विरोध कर रही हैं। उन्होंने इस प्रक्रिया को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाते हुए हस्तक्षेप करने की मांग की है। इन पार्टियों ने पहले बिहार में भी एसआईआर का विरोध किया था, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने कुछ शर्तों के साथ चुनाव आयोग को यह प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दे दी। आख़िरकार, इतने शोर-शराबे के बाद भी बिहार में लगभग किसी भी मतदाता ने यह शिकायत नहीं की कि उसका नाम गलत तरीके से मतदाता सूची से हटाया गया है। ये पार्टियां चाहे जितना शोर मचाएं, लेकिन वे चुनाव आयोग को उसकी जिम्मेदारी निभाने से नहीं रोक सकतीं। मतदाता सूची से उन लोगों के नाम हटाना जरूरी है जो अब नहीं रहे, घर बदल चुके हैं, या फिर गैरकानूनी तरीके से वोटर सूची में शामिल हो गए हैं। अगर हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, राजद और डीएमके जैसी पार्टियां एसआईआर का लगातार विरोध कर रही हैं। चुनाव आयोग की ओर से हाल ही में 12 राज्यों में यह प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा का भी इन पार्टियों ने जोरदार विरोध किया है। अजीब बात यह है कि इन पार्टियों ने एसआईआर के खिलाफ जो आपत्तियां उठाईं, उनमें से एक यह थी कि चुनाव आयोग गैर-नागरिकों को मतदाता सूची से बाहर कर देगा। लेकिन यही तो संविधान चुनाव आयोग से अपेक्षा करता है कि केवल भारतीय नागरिक ही वोटर बनें।

अगर आयोग यह जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा, तो अवैध घुसपैठियों और गैर-कानूनी प्रवासियों के लिए मतदाता सूची में घुसने के रास्ते खुल जाएंगे। यह भारत की एकता, अखंडता और हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, दोनों के लिए गंभीर खतरा होगा। सवाल यह है कि ये पार्टियां गैर-नागरिकों के नाम हटाने का विरोध क्यों कर रही हैं? यह मुद्दा शासन पर भी गंभीर असर डालता है, क्योंकि संविधान के अनुसार 25 वर्ष से ऊपर का हर वोटर विधायक या सांसद बन सकता है, और आगे चलकर किसी राज्य का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। इसलिए चुनाव आयोग की बड़ी जिम्मेदारी है कि गैर-नागरिकों को वोटर सूची में शामिल न होने दे। भारत के चुनाव आयोग की शक्तियां संविधान में साफ़ लिखी गई हैं।

अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को यह अधिकार देता है कि वह चुनावों की देखरेख, दिशा और नियंत्रण करे। इसमें कहा गया है: (1) संसद, हर राज्य की विधानसभा, और संविधान के तहत होने वाले राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव इन सभी के लिए मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी और अधिकार एक आयोग (जिसे संविधान में चुनाव आयोग कहा गया है) को दिए जाते हैं।

मतदाता सूची तैयार करने के विषय में संविधान का अनुच्छेद 326 यह घोषित करता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। यानी, हर वह व्यक्ति जिसका भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, जिसकी उम्र तय तारीख़ तक कम से कम 18 वर्ष हो, और जिसे गैर-निवास, मानसिक अस्वस्थता, अपराध या किसी भ्रष्ट या अवैध आचरण के कारण अयोग्य न ठहराया गया हो, वह मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार है। सीधी भाषा में कहा जाए तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि हर पंजीकृत वोटर-भारत का नागरिक हो, और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो साथ ही संविधान और कानून में बताई गई अन्य योग्यताओं को भी पूरा करता हो। इसके अलावा, नागरिकता से जुड़ी यह शर्त जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 में और भी स्पष्ट रूप से बताई गई है। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, वह मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के योग्य नहीं है।

धारा 21 चुनाव आयोग को यह अधिकार देती है कि वह तय नियमों के अनुसार मतदाता सूची तैयार करे और समय-समय पर उसमें संशोधन करे। इस तरह, संविधान और संसद से बनाए गए चुनाव कानून दोनों साफ़ कहते हैं कि केवल भारतीय नागरिक ही वोटर बन सकते हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए नागरिकता कितनी जरूरी है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण सोनिया गांधी का मामला है। सोनिया गांधी का नाम 1980 में मतदाता सूची में शामिल हो गया था, जबकि उस समय वह इटली की नागरिक थीं। शिकायत मिलने पर 1982 में उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया। उन्होंने अप्रैल 1983 में भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया और उसी महीने उन्हें नागरिकता दे दी गई। इसके बाद उनका नाम फिर से मतदाता सूची में शामिल किया गया, उस समय वह 1, सफदरजंग रोड पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ रहती थीं। इन सब तथ्यों के बाद यह कहना बिल्कुल अजीब लगता है कि चुनाव आयोग को नागरिकता की इस अनिवार्य शर्त पर ज़ोर नहीं देना चाहिए। दुर्भाग्य से, देश की सबसे पुरानी पार्टी के कुछ प्रवक्ता भी इन संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों से अनजान हैं। उनमें से एक ने तो कुछ समय पहले ट्वीट करके चुनाव आयोग के नागरिकता की जांच करने के अधिकार पर ही सवाल उठा दिया था। अगर ऐसा है, तो क्या हम मान लें कि संविधान के अनुच्छेद 324 और 326 को ही हटा दिया गया है? पिछली बार एसआईआर लगभग 20 साल पहले, 2002–2004 के बीच किया गया था। उस समय यह प्रक्रिया बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों में हुई थी। ज़रा सोचिए,पिछले 22 वर्षों में कितने लोग इन सूचियों में दर्ज थे जो अब नहीं रहे, घर बदल चुके हैं, या राज्य से बाहर चले गए हैं? इसलिए चुनाव आयोग को संविधान और संसद की ओर से दिए गए अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। उसे संविधान के प्रति वफ़ादार रहना चाहिए और किसी धमकी या आरोप से डरना नहीं चाहिए।

(एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। वह प्रसार भारती के चेयरमैन रह चुके हैं, इस समय वह नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय की कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष हैं।)

आज की बात

ए. सूर्य प्रकाश

लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के हो सकारात्मक प्रयास

हम 10 दिसंबर को मानवाधिकारों का उत्सव मनाते है। उस दिन की स्मृति में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। यह घोषणा हमारे समाजों के मानवाधिकार ढांचे की रीढ़ है, जहां हममें से प्रत्येक को बिना किसी भेदभाव के शांति और सुरक्षा के साथ रहने और फलने-फूलने का अधिकार है। 1950 में संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष की 10 दिसम्बर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाना तय किया था। 75 वर्ष पहले पारित हुआ विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र एक मील का पत्थर हैं। जिसने समृद्धि, प्रतिष्ठा व शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के प्रति मानव की आकांक्षा प्रतिबिंबित की है। आज यही घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बुनियादी भाग है। 10 दिसंबर 2025 को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक प्रतिज्ञाओं में से एक मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 77वीं वर्षगांठ है । 2025 में मानवाधिकार दिवस की थीम हमारी रोजमर्रा की अनिवार्यताएं, तीन सरल सत्यों पर जोर देती हैं। मानवाधिकार सकारात्मक हैं, मानवाधिकार आवश्यक हैं, और मानवाधिकार प्राप्य हैं। मानव अधिकार वे मूल अधिकार हैं जो इस धरती पर प्रत्येक व्यक्ति के पास हैं। मानवाधिकार मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता हैं। मानवाधिकारों में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति, राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम और शिक्षा का अधिकार और बहुत कुछ शामिल हैं। बिना किसी भेदभाव के हर कोई इन अधिकारों का हकदार है। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन मानवाधिकारों के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत रहा है। कुछ अधिकार ऐसे होते है जो व्यक्ति को जन्मजात मिलते है। उन अधिकारों का व्यक्ति के आयु, प्रजातीय मूल, निवास-स्थान, भाषा, धर्म पर कोई असर नहीं पड़ता। देश के विशाल आकार व विविधता तथा सम्प्रभुता संपन्न धर्म-निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा तथा एक भूतपूर्व औपनिवेशिक राष्ट्र के रूप में इसके इतिहास के परिणामस्वरूप भारत में मानवाधिकारों की परिस्थिति एक प्रकार से जटिल हो गई है। भारत का संविधान मौलिक अधिकार प्रदान करता है जिसमें धर्म की स्वतंत्रता भी अंतर्भूक्त है। संविधान की धाराओं में बोलने की आजादी के साथ-साथ कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन तथा देश के अन्दर एवं बाहर आने-जाने की भी आजादी दी गई है। भारतीय परिदृश्य में यह समझ पाना थोड़ा मुश्किल हैकि क्या वाकई में मनुष्य के लिए चिन्हित किये गए मानवाधिकारों की सार्थकता है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं।)

आपकी बात

रमेश सर्राफ धमोरा

भारत में बढ़ते प्रदूषण का कारण क्या वास्तव में हमारा गैरजिम्मेदाराना व्यवहार है?

पर्यावरण प्रदूषण आज मानवता के समक्ष सर्वाधिक भयावह चुनौतियों में से एक और इसका प्रमुख कारण है मानव जनित प्रदूषण।भारत में प्रदूषण की समस्या अक्सर उद्योगों, वाहनों, बढ़ते शहरी विस्तार और सरकारी तंत्र की कमियों से जोड़ी जाती है, परंतु सच्चाई यह है कि प्रदूषण को बढ़ाने में नागरिकों के गैरजिम्मेदाराना कृत्य भी बड़े और निर्णायक कारक हैं। एक आंकड़े के अनुसार वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 76 प्रतिशत उर्जा उत्पादन और उपभोग से जुड़ा हुआ है,जो मानव की असंयत उर्जा खपत की प्रवत्ति को दर्शाता है। वास्तव में देखा जाए तो पर्यावरण संकट किसी एक संस्था, नीति या व्यवस्था का परिणाम नहीं, बल्कि सामूहिक व्यवहार की गलत दिशा का प्रतिफल है। हमारी छोटी-छोटी लापरवाहियाँ मिलकर एक बड़े राष्ट्रीय संकट में बदल जाती हैं। सबसे सामान्य और हानिकारक व्यवहार है कचरे को अनियमित रूप से इधर- उधर फेंकने की प्रवृत्ति। अधिकांश शहरों में सड़कें, ग्रीन बेल्ट, सार्वजनिक स्थल, नाले, नदी, तालाब किनारे आदि सभी जगह धर, दुकान , फैक्टरी आदि से निकले कचरा का ढेर दिखना इस बात का प्रमाण है कि हमने स्वच्छता को आदत नहीं, केवल अवसर भर समझा है। कई लोग कचरे को खुले में जला देते हैं, जिससे उसके जहरीले तत्व वायु में फैलकर मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को नुकसान पहुँचाते हैं। सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बावजूद इसका निरंतर उपयोग नागरिक जिम्मेदारी की कमी को दर्शाता है। वाहनों का अनियंत्रित उपयोग, साझा न करने की प्रवृत्ति तथा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कम महत्व देने की सोच ने भी प्रदूषण बढ़ाने का काम किया है। छोटी दूरी पर भी निजी वाहन का उपयोग, समय पर प्रदूषण जांच न कराना, सर्विसिंग की अनदेखी करना और पुराने धुआँ छोड़ने वाले वाहनों का उपयोग तथा ई-वाहनों को कम महत्व देने का ही परिणाम है अवांछित कार्बन उत्सर्जन। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कचरा, पराली और पत्ते जलाने की परंपरा अब भी जारी है, जिससे पीएम2.5 और पीएम 10 जैसे सूक्ष्म कण तेजी से वातावरण में फैलते हैं। जल प्रदूषण के लिए भी नागरिकों के कई आचरण सीधे जिम्मेदार हैं। नदियों और तालाबों में मूर्तियाँ, फूल, कपड़े और घरेलू कचरा विसर्जित करना, धार्मिक आस्था के नाम पर जलस्रोतों को कचरा-घर बनाना पर्यावरणीय संवेदनहीनता का प्रतीक है। घरों, दुकानों, उद्योगों का बिना उपचार का गंदा जल नदी,तलाब, नालों आदि में छोड़ देना अंततः जलस्रोतों को विषैला बना देता है। ध्वनि प्रदूषण के मामले में भी नागरिकों की मनमानी किसी से छिपी नहीं है। तीव्र ध्वनि वाले डीजे, विविध अवसरों पर पटाखों का अत्यधिक उपयोग, धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में लाउडस्पीकरों की ऊँची आवाज, वाहनों में अनावश्यक होर्न आदि का उपयोग सब मिलकर शोर का ऐसा वातावरण बनाते हैं जो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। कई लोग देर रात तक ध्वनि स्तर के नियमों की खुली अवहेलना भी करते हैं। ऊर्जा और संसाधनों के दुरुपयोग में भी हमारा व्यवहार जिम्मेदार है। एसी और बिजली का अनावश्यक प्रयोग, पानी को बिना कारण बहने देना, बोरवेल का अत्यधिक दोहन और वर्षाजल-संग्रह को नजरअंदाज करना आदि भी संसाधनों पर दबाव बढ़ाते हैं। इसके साथ पेड़ों की कटाई, हरित-आवरण की अनदेखी और रोपित वृक्षों के संरक्षण में रुचि की कमी भी कहीं न कहीं प्रदूषण को और बढ़ाती है। ओन लाइन वस्तुओं को मंगाने की बढ़ती प्रवृत्ति,त्योहारों के दौरान प्लास्टिक सजावट, रासायनिक रंगों और पटाखों का अत्यधिक उपयोग यह दर्शाता है कि हम उत्सवों में स्वस्थ पर्यावरण को शामिल करना अब भी नहीं सीख पाए हैं। कचरा प्रबंधन नियमों, ट्रैफिक कानूनों और पर्यावरणीय दिशा-निर्देशों की लगातार अवहेलना "नियम केवल दूसरों के लिए हैं" वाली मानसिकता को उजागर करती है। सत्य यही है कि प्रदूषण केवल सरकारी असफलता का परिणाम नहीं, बल्कि हमारे गैरजिम्मेदाराना आचरण का दर्पण भी है। जब तक हम स्वयं पर्यावरणीय अनुशासन नहीं अपनाएंगे, तब तक सुधार केवल कागज़ों और घोषणाओं तक सीमित रहेगा और हम दिल्ली वासी जैसे पर्यावरण प्रदूषण को कोसते रहेंगे। क्योंकि समाधान नीति में नहीं, नागरिक के चरित्र में छिपा है। पर्यावरण प्रदूषण रोकने में सरकारों को भी जिम्मेदार संस्था के रूप भूमिका निभाने की आवश्यकता है क्योंकि वहां भी हममें से ही कोई बैठा है। पर्यावरण कानूनों को बिना भेदभाव के प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन करने की जरुरत है साथ ही स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ बनाना और अपशिष्ट प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था करना , जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए नागरिकों को प्रेरित करना भी उसके प्रमुख दायित्व में से एक हैं।

(ये लेखक के निजी विचार हैं।)

देश की बात

मनमोहन प्रकाश

फेसबुक वॉल से

एक्स से

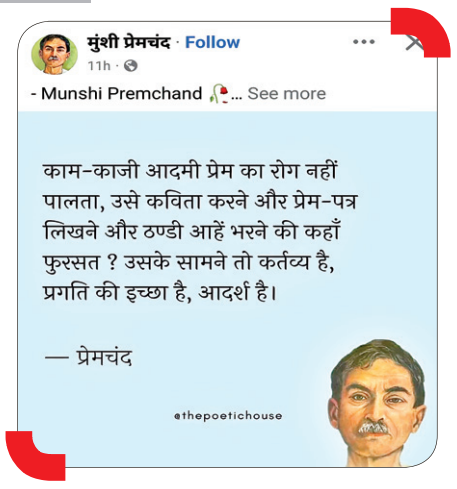

आज का दोहा

वे आये फिर मंच पर, कहने अपनी बात।
लोग पूछते रह गए, कब बीतेगी रात।।

सोमदत्त शर्मा, गाजियाबाद (उ.प्र.)

रचना भेजिए

समाचारों के संबंध में शिकायत या इस पेज के लिए आर्टिकल कृप्या भेजें artical.rnmail@gmail.com

कॉल/व्हाट्सएप 8292553444

संपादक

अत्यंत प्राचीन है भारत में मानवाधिकार की अवधारणा

वर्तमान में मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसम्बर को दुनिया भर में मनाया जाता है।संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसम्बर1948 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मानवता की अंतरात्मा को आहत करने वाले बर्बर कृत्यों के जवाब में मानवाधिकारों की पहली वैश्विक घोषणा और अंगीकार किया गया था। इसके अंगीकरण ने मानवाधिकारों को स्वतंत्रता, न्याय और शांति का आधार माना।मानवाधिकार दिवस की औपचारिक स्थापना 4 दिसम्बर1950 को महासभा की 317वीं पूर्ण बैठक में हुई, जब महासभा ने संकल्प 423 (V) की घोषणा की, जिसमें सभी सदस्य राज्यों और किसी भी अन्य इच्छुक संगठनों को इस दिन को मनाने के लिए आमंत्रित किया गया था।उच्चस्तरीय राजनीतिक सम्मेलनों, बैठकों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मानवाधिकारों के मुद्दों से संबंधित प्रदर्शनियों के लिए चिह्नित यहदिवस नए संयुक्त राष्ट्र की पहली प्रमुख उपलब्धियों में से एक है। यह मानवाधिकार शब्द दो शब्दों के योग से बना है -मानव और अधिकार। मानव, मनुष्य, व्यक्ति प्रायः समानार्थी हैं। मानवाधिकार एक सामासिक पद है। मानवानां अधिकारः मानवाधिकारः। भारतीय परंपरानुसार मनु का अपत्य अर्थात मनु की संतान होने के साथ-साथ जिसमें मननशीलता तथा कर्तव्य निष्ठा का सम्यक् सन्निवेश हो, वह मानव कहलाने का अधिकारी है। अधिकार शब्द के सबंध में कहा गया है- अधिक्रियते इति अधिकारः। अर्थात जो अधिकृत हो, वह अधिकार है। अधिकार शब्द अधि उपसर्ग कृ धातु से कर्मार्थक घञ प्रत्यय होने से सिद्ध होता है, जिसका अर्थ होता है- अधीन करना या स्वामित्व होना। इस प्रकार अधिकार शब्द स्वामित्व का बोधक है। अधि उपसर्ग प्रायः अधिकरण अर्थ में प्रयुक्त होता है तथा कृ धातु करने के अर्थ को द्योतित करता है। तथा घञ प्रत्यय करमार्थक है। इस प्रकार अधिकार शब्द का अर्थ हुआ कर्मीभूत किसी द्रव्य, सता, नियम आदि को अपने में धारण करना। अतः मनुष्य का अधिकार मानवाधिकार है। वर्तमान काल में मानवाधिकार कोपश्चिमी देशों की उपज और पूर्णतः एक नवीन अवधारणा के रूप में देखा जाता है, लेकिन भारत के लिए यह कोई नई अवधारणा नहीं है।भारत में मानवाधिकार की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है।संसार के प्राचीनतम ग्रंथ वेद और संस्कृतके ग्रंथों में मानवाधिकार की अवधारणा का एक व्यापक रूप व चिंतन उपलब्ध होना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहां सृष्टि के कण- कण में चेतना का स्वरूप मानकर उनसे आत्मवत व्यवहार का प्रतिपादन किया गया है।यद्यपि मानवाधिकार शब्द नवीन है, तथापि सैद्धांतिक रूप से इसकी अवधारणा मानव सभ्यता के आरंभिक काल से ही विद्यमान दिखाई पड़ती है। मनुष्य के सभी उद्वेगों, संवेगों तथा मूल प्रवृतियों का उल्लेख वेदों में यथास्थान मिलता है।मानवीय सभ्यता के प्राचीनतम ग्रंथ वेद मानवाधिकार संबंधी प्राचीन सनातन अवधारणा का सम्यक प्रकाशन करते हैं। ऋग, यजु, साम, अथर्ववेद सभी मानवाधिकार का वैदिक स्वरूप विश्व के व्यापक दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।वेदों में मानवाधिकारों की अवधारणा की स्पष्ट झलक मनुर्भव अर्थात मनुष्य बनो, जैसे मंत्रों के माध्यम से व्यक्त होती है।समानता, गरिमा और सभी के प्रति सम्मान के सिद्धांतों में अंतर्सन्निहित दिखाई देती है, जो सभी मनुष्यों के बीच आंतरिक एकता और आपसी रक्षा पर जोर देती है, और जीवन, स्वतंत्रता, और सामाजिक न्याय के मूलभूत अधिकारों, सभी के लिए समान अवसर, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और शुद्ध हवा आदि प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच का अधिकार का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करती है।वेदमें तन, सृधि और जीव अर्थात क्रमशः शरीर, निवास और जीवन की स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए इन्हें धर्म अर्थात कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है।इन अधिकारों और कर्तव्यों को मुख्यतः कर्तव्य अर्थात धर्म माना गया है। इन कर्तव्यों में स्वयं, अपने परिवार, अन्य लोगों, समाज और संपूर्ण विश्व के प्रति कर्तव्य शामिल हैं। वैदिक मतानुसार सभी मनुष्य जन्म से समान हैं और उनमें कोई श्रेष्ठ या निम्न नहीं है, जो आधुनिक मानवाधिकारों के गैरभेदभाव के सिद्धांत का आधार है। सभी मनुष्यों को एक दूसरे के प्रति दयालु और जिम्मेदार होने का उपदेश देता ऋग्वैदिक मंत्र मनुर्भव वर्तमान केमानवाधिकारों का मूल है।यजुर्वेद 36/18का मित्रस्य अर्थात मित्रता और अथर्ववेद3/30/4 में उल्लिखित अविद्वेषम् अर्थात द्वेष न करना जैसे विचार सभी के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार और सामंजस्य पर जोर देते हैं। अथर्ववेद 3/30/6 में ईश्वर ने पहिये की अक्ष में आरे के जुड़े होने की भांति आपस में मिलजुलकर परोपकारी सदाचारी विद्वान के नेतृत्व में चलने का आदेश दिया है।वेदों के अनुसार सभी को साथ मिलकर उन्नति करने का अधिकार है, जिससे समाज में समरसता और एकता बनी रहे।

(ये लेखक के निजी विचार हैं।)

अलग बात

अशोक 'प्रवृद्ध'

स्वामी, पारिजात माइनिंग इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) प्रा.लि. के लिए प्रकाशक एंव मुद्रक हर्षवर्द्धन बजाज द्वारा 502, मंगलमूर्ति हाईट्स, रानी बगान, हरमू रोड, रांची से प्रकाशित एवं एस एच प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में शिवासाई पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड), नियर टेंडर बागीचा पेट्रोल पम्प, रातू, रांची-835222, झारखंड द्वारा मुद्रित। रजिस्ट्रेशन नं: BIHHIN/1999/155, प्रधान संपादक : सुरेश बजाज, संपादक : हर्षवर्द्धन बजाज, कार्यकारी संपादक : सुनील सिंह 'बादल'*, समाचार संपादक : त्रिभुवन कुमार सिन्हा, प्रेस कार्यालय : रांची रोड, रेड़मा, मेदिनीनगर (डालटनगंज) पलामू-822102, फोन नंबर : 06562-796018, रांची कार्यालय : 502बी, पांचवी मंजिल, मंगलमूर्ति हाईट्स, रानी बगान हरमू रोड, रांची-834001, फोन नंबर : 0651-3553943, ई-मेल : news.rnmail@gmail.com, article.rnmail@gmail.com
(*पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेवार।)

दिल्ली में भारत-ब्रुनेई संयुक्त कार्य समूह की बैठक

नई दिल्ली। भारत और ब्रुनेई के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह (जेडब्लूजी) की पहली बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित की गई। यह बैठक दोनों देशों की द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और ब्रुनेई के रक्षा मंत्रालय की उप-स्थायी सचिव पोह कुई चून ने की। बैठक शुरू होने से पहले दोनों प्रतिनिधियों ने संयुक्त कार्य समूह की स्थापना से जुड़े विचारार्थ विषयों (टीओआर) पर हस्ताक्षर किए।

चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को दिया दिशा-निर्देश

30 दिन के अंदर अपना संविधान जमा करें

एजेंसी। नई दिल्ली

चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दलों से कहा है कि 30 दिनों के अंदर सभी संशोधनों के साथ अपने-अपने संविधान का अपडेटेड वर्जन उसके पास जमा करें। चुनाव आयोग ने यह निर्देश ऐसे समय में दिया है, जब सुप्रीम कोर्ट उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन से लेकर उसके संचालन तक को लेकर वैधानिक नियावली बनाने की मांग की गई है, ताकि इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

राजनीतिक दल अपना संविधान जमा करें

सोमवार को राजनीतिक दलों को भेजी चिट्ठी में चुनाव आयोग ने कहा है कि जब जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 29ए के तहत एक राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन होता है, तब उनकी ओर से रूल्स और रेगुलेशन को लेकर मेमोरेंडम भी जमा किया जाता है।

पार्टी का संविधान राजनीतिक दलों का दर्पण

चुनाव आयोग ने पॉलिटिकल पार्टियों से कहा है कि पिछली बार जब उन्होंने दस्तावेज सौंपा था, उसके बाद से उसमें जितने भी बदलाव हुए हैं, उन सबकी कॉपी भी साथ ही जमा करें। इन अपडेटेड कॉपी से पार्टी के अंदर वैधानिक जरूरतों के पालन होते रहने की पुष्टि होती है और यह सुनिश्चित हो जाता है कि जनता को यह पता रहे कि पार्टी किन नियमों के तहत संचालित हो रही है। चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक दलों को यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर दायर एक जनहित याचिका के बीच जारी किया गया है। अपनी याचिका में एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की मांग की है कि वो राजनीतिक दलों के संचालन के लिए वैधानिक नियम तैयार करें, जिसमें उसकी अंदरूनी संरचना, वित्तीय जानकारी, निर्णय लेने में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व तय करने का पूरा प्रावधान शामिल हो।

हस्तशिल्प आजीविका का साधन भी है और सांस्कृतिक पहचान भी : राष्ट्रपति

एजेंसी। नई दिल्ली

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को नई दिल्ली में वर्ष 2023 और 2024 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि कला हमारे अतीत की स्मृतियों, वर्तमान के अनुभवों और भविष्य की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है। प्राचीन काल से ही मनुष्य चित्रकला या मूर्तिकला के माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता रहा है। कला लोगों को संस्कृति से जोड़ती है। कला लोगों को एक-दूसरे से भी जोड़ती है।

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि यदि हमारी सदियों पुरानी हस्तशिल्प परंपरा जीवंत और संरक्षित बनी हुई है,

तो इसका श्रेय पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे कारीगरों की प्रतिबद्धता को जाता है। हमारे कारीगरों ने अपनी कला और परंपरा को बदलते समय के साथ ढाला है और साथ ही मूल भावना को भी जीवित रखा है। उन्होंने अपनी प्रत्येक कलात्मक रचना में देश की मिट्टी की खुशबू को संजोए रखा है। उन्होंने कहा कि हस्तशिल्प न केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं, बल्कि आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी हैं। यह क्षेत्र देश में 32 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। उल्लेखनीय है कि हस्तशिल्प से रोजगार और आय प्राप्त करने वाले ज्यादातर लोग ग्रामीण या दूरदराज के इलाकों में रहते हैं। यह क्षेत्र रोजगार और आय का विकेंद्रीकरण करके समावेशी विकास को बढ़ावा देता है। राष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक सशक्तीकरण के लिए हस्तशिल्प को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्षेत्र पारंपरिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को सहायता प्रदान करता रहा है। हस्तशिल्प न केवल कारीगरों को आजीविका का साधन प्रदान करता है, बल्कि उनकी कला उन्हें समाज में पहचान और सम्मान भी दिलाती है।

भारतीय हस्तशिल्प पर्यावरण के अनुकूल वैश्विक मांग बढ़ने की अपार संभावनाएं: राष्ट्रपति

राष्ट्रपति ने कहा कि हस्तशिल्प उद्योग की सबसे बड़ी ताकत प्राकृतिक और स्थानीय संसाधनों पर इसकी निर्भरता है। यह उद्योग पर्यावरण के अनुकूल है और इसका कार्बन उत्सर्जन कम है। आज दुनियाभर में पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ जीवनशैली की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में, यह क्षेत्र स्थायित्व में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

राष्ट्रपति को यह जानकर खुशी हुई कि जीआई टैग दुनिया भर में भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों की पहचान को मजबूत कर रहा है। उन्होंने सभी हितधारकों से अपने अनूठे उत्पादों के लिए जीआई टैग प्राप्त करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया।

ममता बनर्जी का केंद्र पर हल्ला बोल, कहा-

फंड रोकने से नहीं रुकेगा बंगाल का विकास

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार को किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है और सभी कल्याणकारी योजनाओं को स्वतंत्र रूप से चलाना जारी रखेगी। उन्होंने एनआरसी और सीएए के प्रति अपने कड़े विरोध को भी दोहराया और घोषणा की कि बंगाल कभी भी डिटेंशन कैंप की अनुमति नहीं देगा। एक जनसभा को संबोधित करते हुए, बनर्जी ने कहा कि हमें केंद्र से किसी मदद की आवश्यकता नहीं है; हम सभी योजनाएँ स्वयं चला रहे हैं। परसों, उन्होंने (केंद्र ने) हमें एक नोटिस जारी कर 6 दिसंबर तक तिमाही श्रम बजट जमा करने को कहा था। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आपके नोटिस का कोई महत्व नहीं है। बंगाल 100 दिनों का कार्य कार्यक्रम अपने दम पर चलाएगा।

मोदी से मिलने के बाद नडेला का कहा

भारत बनेगा एआइ हब

- एआई अवसर पर प्रेरक बातचीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, धन्यवाद।

एजेंसी। नई दिल्ली

माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने मंगलवार को घोषणा की कि वह भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के विकास हेतु आवश्यक बुनियादी ढाँचे और कौशल निर्माण हेतु 17.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश कर रहे हैं, जो एशिया में कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। उन्होंने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात के बाद एक्स पर एक पोस्ट में यह घोषणा की। नडेला ने ट्वीट किया भारत के एआई अवसर पर प्रेरक बातचीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, धन्यवाद। देश की महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट भारत के एआई-प्रधान भविष्य के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे, कौशल और संप्रभु क्षमताओं के निर्माण में मदद के लिए एशिया में अपना अब तक का सबसे बड़ा निवेश - 17.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर - करने की प्रतिबद्धता जता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ नडेला की यह मुलाकात इस साल की शुरुआत में उनके उस बयान के कुछ दिनों बाद हुई है जिसमें उन्होंने कहा था कि कंपनी अगले दो वर्षों में भारत में क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किलिंग में 3 अरब डॉलर का निवेश करेगी, जिसमें नए डेटा सेंटर की स्थापना भी शामिल है। कंपनी अगले पाँच वर्षों में देश में 1 करोड़ लोगों को एआई कौशल प्रशिक्षित करने में भी मदद करेगी। अपने माइक्रोसॉफ्ट एआई टूर के बेंगलुरु चरण में नडेला ने कहा कि भारत एआई नवाचार में तेज़ी से अग्रणी बन रहा है और देश भर में नए अवसर पैदा कर रहा है। आज हम बुनियादी ढांचे और कौशल विकास में जिस निवेश की घोषणा कर रहे हैं, वह भारत को एआई-प्रमुख बनाने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है और यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि देश भर के लोगों और संगठनों को व्यापक रूप से लाभ मिले।

प्रशासन का बड़ा एक्शन, 'बर्च बाय रोमियो लेन' क्लब पर चला बुलडोजर

पणजी। गोवा के नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की जान चली गई। क्लब के मालिक फरार हैं और उनके थाईलैंड भागने की आशंका है। अब प्रशासन ने इस नाइट क्लब के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए बुलडोजर चला दिया है। समुद्र के किनारे बने 'बर्च बाय रोमियो लेन' क्लब में आग लगने की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस घटना में 25 लोगों की मौत हुई। इसमें चार पर्यटक और 14 स्टाफ सदस्य शामिल हैं। सात पीड़ितों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। छह लोग घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है। इस भयावह घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया और सभी क्लबों के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए।

देश को विभाजित करने वाले जयचंद और मीरजाफर जैसे पापी : योगी

एजेंसी। गोरखपुर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज और देश को विभाजित करने वालों से सावधान रहने का आह्वान करते हुए कहा कि ऐसे लोग जयचंद और मीरजाफर जैसा पाप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तोड़ने के लिए बहुत से लोग हैं। कोई जाति के नाम पर, कोई क्षेत्र और कोई भाषा के नाम पर बांट रहा है। समाज और देश तोड़क इन तत्वों को जब सत्ता में आने का मौका मिलता है तो वे सिर्फ अपने और परिवार के बारे में सोचते हैं। परिवार के लिए प्रॉपर्टी, विदेश में होटल और द्वीप खरीदते हैं। ऐसे लोग देश को दरिद्र करने का षड्यंत्र करते हैं। जाति, क्षेत्र आदि के नाम के तात्कालिक लॉलीपॉप से

समाज और देश का कल्याण नहीं हो सकता। देश का कल्याण तभी होगा, जब भेदभाव नहीं होगा, सबमें एकता होगी।

मुख्यमंत्री योगी मंगलवार को सैनिक स्कूल गोरखपुर में देश के पहले सीडीएस (चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ) जनरल बिपिन रावत के नाम पर बने ऑडिटोरियम के उद्घाटन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बिपिन रावत की प्रतिमा का भी अनावरण किया और महान सैन्य नायक को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस प्रतिमा की स्थापना जनरल बिपिन रावत की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर जीबीआर मेमोरियल फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से कराई गई है। मुख्यमंत्री ने जनरल बिपिन रावत के जीवन पर आधारित एक पुस्तिका का भी विमोचन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जनरल बिपिन रावत के व्यक्तित्व और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को याद किया तथा देश के समसामयिक हालात पर भी चर्चा करते हुए विकसित भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिलाए गए पंच प्रणों को अपनाने की अपील की। सीएम योगी ने कहा कि आजादी के अमृत वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया था।

भारत पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं, जहां इस्लामिक कानून चलता हो : गिरिराज सिंह

एजेंसी। नई दिल्ली

मौलाना अरशद मदनी के 'वंदे मातरम' पर दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखा पलटवार किया और कहा कि मदनी हों या गजनी, यह पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश नहीं, जहां इस्लामिक कानून चलता हो। यह भारत है। गिरिराज सिंह ने मौलाना अरशद मदनी पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत में सभी को संविधान से ही चलना होगा, वह चाहे गजनी हो या मदनी। जो नहीं मानेगा, उसके लिए कानून अपना काम करेगा।उन्होंने कहा कि वंदे मातरम से सिर्फ उसी को ऐतराज होगा, जो भारत के संविधान को नहीं मानता हो। कानून किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं

बनता, कानून देश के लिए बनता है। सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता मिलने से पहले मतदाता बनने के सवाल पर गिरिराज सिंह ने कहा कि यह जांच का विषय है। इतने बड़े परिवार के लोग दोहरी नागरिकता रखें, यह जांच का विषय है। मौलाना अरशद मदनी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर कहा था कि हमें किसी के "वंदे मातरम" पढ़ने या गाने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है और अपनी इबादत में अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को शामिल नहीं कर सकता। उन्होंने आगे लिखा कि वंदे मातरम के चार छंदों में देश को देवता मानकर दुर्गा माता से तुलना की गई है। यह किसी भी मुसलमान की धार्मिक आस्था के खिलाफ है। इसलिए किसी को उसकी आस्था के खिलाफ कोई नारा या गीत गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मुसलमानों की देशभक्ति के लिए किसी के प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है। हमें मर जाना स्वीकार है, लेकिन शिर्क कभी स्वीकार नहीं।

यात्रियों को अब नहीं होगी परेशान, फ्लाइट का ऑपरेशन अब सामान्य : पीटर एल्बर्स

एजेंसी। नई दिल्ली

इंडिगो एयरलाइंस ने देश भर में सैकड़ों उड़ानों के रद्द होने और देरी के कारण भारतीय हवाई अड्डों पर मची अफरा-तफरी के लगभग एक हफ्ते बाद अपना परिचालन बहाल कर दिया है। एयरलाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स ने मंगलवार को जारी एक नए बयान में यात्रियों से माफ़ी मांगी है। इंडिगो के सीईओ एल्बर्स ने एयरलाइन के "बड़े परिचालन व्यवधानों" के कारण "उन्हें निराश" करने के लिए हजारों प्रभावित यात्रियों से माफ़ी मांगी है।

सीईओ पीटर एल्बर्स ने एक बयान

में कहा कु हमारे पिछले संवाद के बाद, मैं यह साझा करने के लिए यहाँ हूँ कि हमारी एयरलाइन, इंडिगो, अपने पैरों पर वापस आ गई है और हमारा परिचालन स्थिर है। जब एक बड़ा परिचालन व्यवधान हुआ तो हमने आपको निराश किया, और हमें इसके लिए खेद है। हवाई यात्रा की खूबसूरती यह है कि यह लोगों, भावनाओं, महत्वाकांक्षाओं और आकांक्षाओं को एक साथ लाती है, और हम जानते हैं कि आप विभिन्न कारणों से यात्रा कर रहे हैं। हज़ारों फंसे हुए ग्राहकों को राहत पहुँचाने की एयरलाइन की प्रतिबद्धता दोहराते हुए, सीईओ ने कहा कि आपमें से हज़ारों लोग यात्रा नहीं कर पाए, और हम इसके लिए बेहद खेद व्यक्त करते हैं।

एयरलाइन की 400 से अधिक उड़ानें हुई रद्द

नई दिल्ली। इंडिगो द्वारा रद्द की गई उड़ानों की भारी संख्या ने मंगलवार को पूरे भारत में हवाई यात्रा को प्रभावित करना जारी रखा, सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गईं और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हवाईअड्डा अधिकारियों के अनुसार, इस व्यवधान के कारण अब तक देश भर में 400 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा, जहाँ इंडिगो की 152 उड़ानें रद्द होने की पुष्टि हुई, जिनमें 76 आगमन और 76 प्रस्थान वाली उड़ानें शामिल हैं, अधिकारियों ने बताया। दक्षिणी हवाईअड्डों पर भी रद्दीकरण का असर दिखा। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर, 58 आगमन और 63 प्रस्थान वाली उड़ानें रद्द कर दी गईं, हवाईअड्डा प्राधिकरण ने घोषणा की कि अगला अपडेट शाम 6 बजे के बाद जारी किया जाएगा। चेन्नई में भी महत्वपूर्ण व्यवधान की सूचना मिली, जहाँ दिन भर में 18 प्रस्थान और 23 आगमन वाली उड़ानें रद्द कर दी गईं। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे ने 44 प्रस्थान और 14 आगमन वाली उड़ानों के रद्द होने की पुष्टि की। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर अपेक्षाकृत कम रद्दीकरण दर्ज किए गए, एक आगमन और तीन प्रस्थान रद्द होने की सूचना दी गई, जबकि कुछ उड़ानों के निर्धारित समय पर संचालित होने की पुष्टि की गई। अहमदाबाद में हवाई अड्डे के सुबह 8 बजे के अपडेट में 16 रद्दीकरणों की पुष्टि हुई, जिनमें नौ आगमन और सात प्रस्थान वाली उड़ानें शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि टर्मिनल या हवाई अड्डे पर कोई समस्या नहीं थी और सभी यात्रियों को सहायता प्रदान की जा रही थी।

न्यूज बॉक्स

वंदे मातरम् को नारा बनाने वाली कांग्रेस ही थी : खरगे

नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने वंदे मारतरम् को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर हमला किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू पर हमला करने से पहले भाजपा को इतिहास पढ़ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को नारा बनाने वाली कांग्रेस ही थी। कांग्रेस की परंपरा है कि वह अपने कार्यक्रमों की शुरुआत वंदे मातरम के साथ करे और भाजपा को भी ऐसा ही करके दिखाने की चुनौती दी। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान मंगलवार को खरगे ने कहा, कांग्रेस के नेता भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए और जेल गए, लेकिन भाजपा नेताओं ने अंग्रेजों के लिए काम किया। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जवाहरलाल नेहरू और अन्य कांग्रेस नेताओं का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जब व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए वंदे मातरम के केवल पहले दो पैराग्राफ गाने का निर्णय तत्कालीन कांग्रेस कार्यसमिति का सामूहिक निर्णय था, तो केवल जवाहरलाल नेहरू को ही क्यों निशाना बनाया गया? भाजपा ने नेहरू पर हमला करके समिति के सभी नेताओं और रवींद्रनाथ टैगोर का भी अपमान किया है। भाजपा को राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों का अपमान करने के लिए देश से माफ़ी मांगनी चाहिए।

एसआईआर के दूसरे चरण में अब तक 99.18 प्रतिशत फॉर्म डिजिटाइज्ड

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार को दोपहर 3 बजे तक का एसआईआर के दूसरे चरण का विस्तृत बुलेटिन जारी किया। 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 4 नवंबर से शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया 11 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) और राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स (बीएलए) द्वारा मतदाताओं से जुड़ी जानकारी इकट्ठा कर डिजिटल रूप से दर्ज की जा रही है। चुनाव आयोग ने बताया कि 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 50.99 करोड़ से अधिक मतदाता सूची में शामिल हैं और अब तक 99.97 प्रतिशत एन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण और 99.18 प्रतिशत का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है। लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, अंडमान-निकोबार, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, गुजरात और गोवा जैसे राज्यों ने 100 प्रतिशत एन्यूमरेशन फॉर्म वितरण कर दिया है। वहीं, इन राज्यों में फॉर्म डिजिटाइजेशन की बात करें तो लक्षद्वीप में 100 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 100 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 99.96 प्रतिशत और गुजरात में 99.94 प्रतिशत डिजिटाइजेशन का काम पूरा कर लिया गया है।

एसआईआर की समय-सीमा बढ़े बैलेट पेपर वापस लाए जाएं: मायावती

लखनऊ। संसद में चुनाव सुधार पर जारी चर्चा के बीच बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और

जनहितकारी बनाने के लिए तीन महत्वपूर्ण सुधारों की मांग की है। पार्टी का कहना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की वर्तमान समय-सीमा बेहद कम है, जिससे बीएलओ पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है और इससे वैध मतदाताओं, विशेषकर गरीब और प्रवासी मजदूरों, के नाम मतदाता सूची से छूटने का जोखिम बढ़ गया है। मायावती ने कहा कि जहां करोड़ों मतदाता हैं, वहां एसआईआर प्रक्रिया को जल्दबाजी में पूरा करने का प्रयास उचित नहीं है, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां 15.40 करोड़ से अधिक मतदाता हैं और निकट भविष्य में कोई चुनाव भी निर्धारित नहीं है। पार्टी ने स्पष्ट कहा कि जल्दबाजी के चलते अनेक वैध मतदाता—जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रदत्त संवैधानिक मतदान अधिकार के पात्र हैं—सूची से वंचित हो सकते हैं, जो पूर्णतः अनुचित है, इसलिए एसआईआर की समय-सीमा को अवश्य बढ़ाया जाना चाहिए। मायावती ने आपराधिक मामलों के खुलासे से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर भी टिप्पणी की।

तिरुमाला मिलावटी लड्डू-घी मामले में एक्शन, 2 अधिकारियों को हिरासत में लिया

नई दिल्ली। तिरुमाला मिलावटी घी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मंगलवार को टीटीडी (तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम) के दो अधिकारियों को हिरासत में ले लिया। अधिकारियों के अनुसार, मामले की चिकित्सा जाँच तिरुपति रुइया अस्पताल में भी की जा रही है। दोनों संदिग्धों की पहचान सुगंध और सुब्रह्मण्यम के रूप में हुई है। एसआईटी ने कहा है कि वह गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्तियों से 12 दिसंबर तक पूछताछ करेगी। इससे पहले 28 नवंबर को, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की निगरानी में विशेष जाँच दल (एसआईटी) ने टीटीडी लड्डू-घी में मिलावट मामले में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के इंजीनियरिंग विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को गिरफ्तार किया था, एक एसआईटी अधिकारी ने बताया। गुंटूर रेंज के आईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति, आरएसएसवीआर सुब्रह्मण्यम, पहले टीटीडी में महाप्रबंधक (खरीद) के रूप में कार्यरत थे और लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले घी सहित प्रमुख सामग्रियों की खरीद के लिए जिम्मेदार थे।

2036 तक बुजुर्गों की आबादी बढ़कर 22.74 करोड़ हो जाएगी : नित्यानंद राय

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को कहा कि अगले डेढ़ दशक में भारत की बुजुर्ग आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि

होने का अनुमान है, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्रित कल्याणकारी उपायों की बढ़ती आवश्यकता को रेखांकित करता है। कांग्रेस सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी द्वारा लोकसभा में उठाए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए, नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा गठित जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह के निष्कर्षों का हवाला देते हुए कहा कि 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या 2011 में 10.16 करोड़ से बढ़कर 2036 में 22.74 करोड़ होने की उम्मीद है, और कहा कि इसी अवधि के दौरान कुल जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी 8.4 प्रतिशत से बढ़कर 14.9 प्रतिशत होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की आबादी में तेज वृद्धि स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक और डिजिटल क्षेत्रों में चुनौतियां पेश करेगी। इन उभरती चिंताओं के जवाब में, राय ने कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना (अव्यय) को लागू कर रहा है, जो 1 अप्रैल, 2021 से संचालित एक व्यापक योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर में वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण है।

कटक में सूर्या ब्रिगेड ने साउथ अफ्रीका को 101 रनों से हराया

एजेंसी। नई दिल्ली

कटक के बाराबती स्टेडियम में आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है. ये टी20 सीरीज दो महीने बाद शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है. साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता है। कटक के बाराबती स्टेडियम में आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है. ये टी20 सीरीज दो महीने बाद शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है. इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था. भारत ने साउथ अफ्रीका के सामने 176 रनों का लक्ष्य रखा है. हार्दिक पंड्या ने नाबाद 59 रनों की पारी खेली. अब साउथ अफ्रीका की बैटिंग जारी है। 176 के जवाब में उतरी साउथ अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही. पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर अर्शदीप ने क्विंटन डिकॉक को चलता किया. डिकॉक खाता भी नहीं खोल सके. इसके बाद तीसरे ओवर में अर्शदीप ने स्टब्स को भी चलता किया. स्टब्स के खाते में 14 रन आए. छठे ओवर की पहली ही गेंद पर अक्षर पटेल ने कप्तान एडेन मार्करम को आउट कर दिया. मार्करम 14 रन बना सके. सातवां ओवर लेकर हार्दिक पंड्या आए. उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर मिलर को आउट कर दिया. यानी 50 रनों के भीतर ही अफ्रीका को चौथा झटका लगा. इसके बाद 8वें ओवर में वरुण ने साउथ अफ्रीका को 5वां झटका दिया इसके बाद 10वें ओवर में वरुण ने जानसेन को भी बोल्ड कर दिया और साउथ अफ्रीका को छठा झटका दिया. जानसेन ने 12 रन बनाए. 11वें ओवर में बुमराह ने ब्रेविस को आउट किया. इस विकेट के साथ ही बुमराह के टी20 करियर में 100 विकेट भी पूरे हो गए. इसी ओवर में बुमराह ने केशव महाराज का भी विकेट झटका. 12वें ओवर में अक्षर ने साउथ अफ्रीका को 9वां झटका दिया।

ऐसी रही पारी

कटक टी20 में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही और शुभमन गलि महज 4 रन बनाकर पहले ही ओवर में लुंगी एनगडिी की गेंद पर आउट हो गए. कुछ देर बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव भी भी 11 रन बनाकर लुंगी की गेंद पर पवेलयिन लौट गए. 6 ओवर के बाद भारत का स्कोर 40-2 था. 7वें ओवर में भारत को तीसरा झटका लगा, जब अभिषेक शर्मा 17 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद तिलक वर्मा और अक्षर पटेल में अच्छी साझेदारी पनप रही थी. लेकिन 12वें ओवर में तिलक वर्मा 26 रन बनाकर आउट हो गए. 14वें ओवर में भारत को 5वां झटका लगा जब भारत की अक्षर पटेल 23 रन

हार्दिक बैटिंग और बॉलिंग दोनों में चमके

टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज का शानदार आगाज किया है। पहले मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को 100 रन के पार भी नहीं पहुंचने दिया और जीत दर्ज कर **सीरीज में 1-0** की बढ़त बना ली। गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन ने टीम को यह जीत दिलाई।

न्यूज बॉक्स

सूर्यकुमार यादव और कोच ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए

पुरी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मंगलवार से 5 टी20 मैचों की सीरीज शुरू हो रही है। पहला टी20 मुकाबला कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाना है। मैच से पहले भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर पुरी स्थित जगन्नाथ धाम पहुंचकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। कप्तान और कोच के अलावा, युवा खिलाड़ी तिलक वर्मा, फील्डिंग कोच टी. दिलीप, बैटिंग कोच सीतांशु कोटक और सपोर्ट स्टाफ के दूसरे सदस्यों ने भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। सूर्यकुमार यादव की पत्नी देविशा शेट्टी भी मंदिर पहुंची थीं पुरी जिला एथलेटिक एसोसिएशन के सचिव रबी शंकर प्रतिहारी ने कहा, "यह सच में बहुत अच्छा है कि टीम को भगवान का आशीर्वाद मिला। टीम इंडिया जरूर सफल होगी। टीम मैनेजर, कोच, कैप्टन और दूसरे खिलाड़ी यहां आशीर्वाद लिए हैं। टीम के सदस्य और सहयोगी स्टाफ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंदिर परिसर में दाखिल हुए। खिलाड़ियों की झलक पाने के लिए फैन्स बड़ी संख्या में जमा थे, इसलिए उनकी सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था करनी पड़ी।"

प्रीमियर लीग: मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वॉल्व्स को 4-1 से हराया

मैनचेस्टर। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने प्रीमियर लीग में लगातार अपनी 5वीं जीत दर्ज की। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वॉल्व्स को 4-1 से हराया। टीम की जीत में ब्रूनो फर्नांडीस के दो गोल का अहम योगदान रहा। इस जीत के साथ ही मैनचेस्टर यूनाइटेड ने प्रीमियर लीग के टॉप छह में जगह बना ली। फर्नांडीस का पहले हाफ का गोल हाफ टाइम से ठीक पहले जीन-रिकनर बेलेगार्ड ने कैंसिल कर दिया था, लेकिन ब्रायन मबेउमो ने दूसरे हाफ की शुरुआत में ही यूनाइटेड की बढ़त वापस दिला दी।

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए टॉम ब्लंडेल

वेलिंगटन। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले एक और बड़ा झटका लगा है। विकेटकीपर-बल्लेबाज़ टॉम ब्लंडेल हैमस्ट्रिंग चोट के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। ब्लंडेल को यह चोट पिछले हफ्ते क्राइस्टचर्च में खेले गए पहले टेस्ट के दौरान बल्लेबाजी करते समय लगी थी। ब्लंडेल के बाहर होने के बाद 25 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज़ मिचेल हे का टेस्ट डेब्यू तय माना जा रहा है। हे बुधवार से बेसिन रिजर्व में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड की ओर से पहली बार टेस्ट क्रिकेट में उतरेंगे। इससे पहले न्यूजीलैंड को एक साथ तीन और खिलाड़ियों के चोटिल होने का सामना करना पड़ा था। तेज़ गेंदबाज़ मैट हेनरी, नाथन स्मिथ (साइड इंजरी) और ऑलराउंडर मिचेल सेंटनर सीरीज के बाकी मैचों से बाहर हो चुके हैं। उनके स्थान पर न्यूजीलैंड क्रिकेट ने ऑलराउंडर क्रिस्टियन क्लार्क और तेज़ गेंदबाज़ माइकल रे को टीम में शामिल किया है। मिचेल हे अब तक न्यूजीलैंड के लिए व्हाइट-बॉल क्रिकेट में 19 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं, जिसमें 12 टी20 और 7 वनडे शामिल हैं।

आईपीएल 2026 ऑक्शन

वेंकटेश अय्यर और रवि बिश्नोई सबसे ऊंचे बेस प्राइस वाले भारतीय

एजेंसी। नई दिल्ली

आईपीएल 2026 ऑक्शन से ठीक एक हफ्ते पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने शॉर्टलिस्ट किए गए खिलाड़ियों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है। 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाले टाटा आईपीएल 2026 ऑक्शन में कुल 350 खिलाड़ी बोली के लिए उपलब्ध रहेंगे। इस ऑक्शन की सबसे खास बात यह है कि 2 करोड़ रुपये की सबसे ऊंची बेस प्राइस वाली कैटेगरी में शामिल भारतीय खिलाड़ियों में सिर्फ वेंकटेश अय्यर और रवि बिश्नोई को ही जगह मिली है। आईपीएल 2026 ऑक्शन के लिए कुल 1390 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 350 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। इस फाइनल लिस्ट में 240 भारतीय और 110 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। जिनमें इंग्लैंड से सबसे ज्यादा 21

खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया से 19, न्यूजीलैंड से 16, साउथ अफ्रीका से 15, श्रीलंका से 12, वेस्टइंडीज से 9, अफगानिस्तान से 10, बांग्लादेश से 7 और आयरलैंड से 1 खिलाड़ी शामिल है। भारतीय ऑलराउंडर जलज सक्सेना 39 साल की उम्र में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी होंगे, जबकि अफगानिस्तान के वाहिदुल्लाह जदरान महज 18 साल से थोड़ी अधिक उम्र के साथ ऑक्शन में सबसे युवा खिलाड़ी हैं। इस बार 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस में कुल 40 खिलाड़ियों ने एंट्री ली है। इस कैटेगरी में कैमरन ग्रीन, स्टीव स्मिथ, डेविड मिलर, क्विंटन डी कॉक, वानिंदु हसरंगा, लियाम लिविंगस्टोन, मैथीशा पथिराना, एनरिक नॉर्खिया, जेसन होल्डर, डेरिल मिचेल, जॉश इंग्लिस, मुजीब उर रहमान और नवीन-उल-हक जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय सितारे शामिल हैं। भारतीय खिलाड़ियों में केवल वेंकटेश अय्यर और रवि बिश्नोई ही इस हाईएस्ट बेस प्राइस स्लैब में हैं। राहुल चाहर और चारिथ असलंका जैसे खिलाड़ी फ्रेंचाइजियों का ध्यान खींच सकते हैं।

विराट कोहली अपना स्पोर्ट्सवियर ब्रांड 'वन8' बेच रहे हैं, करेंगे 40 करोड़ का निवेश

एजेंसी। नई दिल्ली

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली अपना स्पोर्ट्सवियर ब्रांड वन8 एजिलिटास स्पोर्ट्स को बेच रहे हैं। एजिलिटास स्पोर्ट्स एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग-टू-रिटेल स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है। इसे अभिषेक गांगुली ने शुरू किया था।

विराट कोहली इस व्यापारिक समझौते के तहत एजिलिटास में एक निवेशक के तौर पर शामिल हो रहे हैं। वह कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने के लिए एजिलिटास में 40 करोड़ रुपये निवेश करेंगे। एजिलिटास उत्पादन, आर एंड डी, ब्रांड-निर्माण और खुदरा वितरण के क्षेत्र में काम करती है। 2023 में, कंपनी ने भारत की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स फुटवियर बनाने वाली मोचिको शूज को खरीदा। इससे कंपनी की घरेलू और निर्यात क्षमता मजबूत हुई थी। वन8 एक स्पोर्ट्सवियर ब्रांड है। विराट कोहली इसके को-फाउंडर रहे हैं। यह ब्रांड स्पोर्ट्सवियर, कपड़े, फुटवियर और एक्सेसरीज तक फैला हुआ है। एजिलिटास की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, "कोहली और गांगुली के बीच आपसी सहयोग पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। कुछ वास्तविक उत्पादन के औपचारिक बातचीत से शुरू हुई प्रक्रिया जल्द ही वन8 के रूप में हमारे सामने आ गई।" कंपनी ने आगे कहा कि कोहली के पास सिर्फ वन8 में निवेश करने का विकल्प था। उन्होंने उत्पादन, डिजाइन, आर एंड डी, और देश भर में कंपनी की वितरण क्षमता देखने के बाद एजिलिटास में शेयरधारक बनने का फैसला किया।

व्यापार/लाइफ व साइंस

नागरिकों को अनऑथराइज्ड डिजिटल लोन ऐप्स के शोषण से बचा रहे : वित्त मंत्री

- आरबीआई ने इस वर्ष 1 जुलाई से अपनी वेबसाइट पर 'डिजिटल लेंडिंग ऐप्स (डीएलए)' नाम से एक निर्देशिका शुरू की है

एजेंसी। नई दिल्ली

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, सरकार और केंद्रीय बैंक आरबीआई ने नागरिकों को अनऑथराइज्ड डिजिटल लोन ऐप्स से सुरक्षित रखने के लिए समय-समय पर कई पहलें लॉन्च की हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश में अनऑथराइज्ड डिजिटल लोन ऐप्स पर अंकुश लगाने के लिए आरबीआई और अन्य संबंधित नियामकों/ हितधारकों के साथ लगातार मिलकर काम कर रही है। आरबीआई ने इस वर्ष 1 जुलाई से अपनी वेबसाइट पर 'डिजिटल लेंडिंग ऐप्स (डीएलए)' नाम से एक निर्देशिका शुरू की है, जिसमें आरबीआई की विनियमित संस्थाओं (आरई) की ओर से डिप्लॉय सभी डीएलए शामिल हैं। इस निर्देशिका का उद्देश्य किसी डीएलए के किसी विनियमित संस्था से जुड़े होने के दावे की पुष्टि करने में ग्राहकों की मदद करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया, "अनऑथराइज्ड डिजिटल लोन ऐप्स की पहचान किए जाने के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 69 ए के तहत पब्लिक एक्सेस के लिए इंफोर्मेशन को ब्लॉक करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार है।" आरबीआई ने इस वर्ष 8 मई को भारतीय रिजर्व बैंक (डिजिटल लेंडिंग) निर्देश, 2025 जारी किए हैं। इन निर्देशों में रिकवरी, डेटा प्राइवेसी और ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र के बारे में प्रावधान हैं जो आरई, उनकी ओर से लगाए गए लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स (एलएसपी) और डिजिटल लेंडिंग ऐप (डीएलए) के लिए अनिवार्य हैं। वित्त मंत्री के अनुसार, आरबीआई और बैंक 'साइबर क्राइम' की रोकथाम के लिए शॉर्ट एसएमएस, रेडियो कैंपेन और प्रचार के माध्यम से जागरूकता अभियान चला रहे हैं।

अनऑथराइज्ड डिजिटल लोन ऐप्स से सुरक्षा

सरकारी पहल
सरकार और आरबीआई ने नागरिकों को अनऑथराइज्ड डिजिटल लोन ऐप्स से सुरक्षित रखने के लिए कई पहलें लॉन्च की हैं।

आरबीआई निर्देशिका
आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर 'डिजिटल लेंडिंग ऐप्स (डीएलए)' नाम से एक निर्देशिका शुरू की है, जिसमें आरबीआई की विनियमित संस्थाओं (आरई) की ओर से डिप्लॉय सभी डीएलए शामिल हैं।

आईटी अधिनियम
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 69 ए के तहत पब्लिक एक्सेस के लिए इंफोर्मेशन को ब्लॉक करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने गरीबों को 95.5 लाख घर दिए

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की दो स्कीमों के तहत लाभार्थियों को 95.54 लाख घर दिए गए। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने संसद को यह जानकारी दी। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सप्लीमेंट्री सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने बताया कि 2020 के एक स्लम सर्वे से पता चला है कि देश भर में 1.39 करोड़ घरों वाले 6.5 करोड़ लोग स्लम में रह रहे थे।

झारखंड में बड़े अवसर मौजूद, जल्द आएगा निवेश : गौतम अदाणी

नवीन मेल संवाददाता

धनबाद। अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने मंगलवार को कहा कि झारखंड और धनबाद में बड़े अवसर मौजूद हैं और आने वाले समय में राज्य काफी आगे जाएंगा। मीडिया से बातचीत करते हुए अदाणी ग्रुप के चेयरमैन ने कहा, "झारखंड और धनबाद में बड़े अवसर मौजूद हैं और आने वाले समय में राज्य काफी आगे जाएंगे।" वहीं, धनबाद में अदाणी ग्रुप के निवेश पर सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि जल्द निवेश आएगा।

इससे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स), धनबाद में शताब्दी समारोह में बोलते हुए गौतम अदाणी ने कहा था कि अदाणी ग्रुप अगले पांच वर्षों में एनर्जी ट्रांजिशन में 75 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश करेगा। कार्यक्रम में अदाणी ग्रुप के चेयरमैन ने कहा कि वह लगातार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बनाने के लिए निवेश कर रहे हैं।

गौतम अदाणी ने बताया कि ग्लोबल ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन हमारे समय का सबसे बड़ा उद्योग बनकर उभर रहा है, जिसका मूल्य आने वाले दशकों में कई ट्रिलियन डॉलर होगा।

गौतम अदाणी ने कहा, "इससे बिजली आधारित मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन स्टील, ग्रीन फर्टिलाइजर, हाइड्रोजन इकोसिस्टम और महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा, जिस पर एआई और डिजिटल अर्थव्यवस्थाएं निर्भर करती हैं।"

ट्रेड डील में देरी से बाजार में उथल-पुथल
दो दिन में 7 लाख करोड़ डूबे

एजेंसी

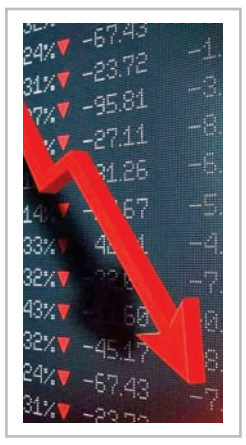

नई दिल्ली। एशियाई बाजारों में गिरावट के बीच भारतीय शेयर बाजार के मंगलवार (9 दिसंबर) को लाल निशान में बंद हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले चावल पर टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। इससे निवेशकों की धारणा पर नकारात्मक असर पड़ा है और अमेरिका के साथ ट्रेड डील की उम्मीदों को भी झटका लगा है।

तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 300 से ज्यादा अंक गिरकर 84,742 पर खुला। खुलते ही इसमें गिरावट देखने को मिली। कारोबार के दौरान यह 700 से ज्यादा अंक गिर गया था। अंत में यह 436.41 अंक या 0.51 फीसदी गिरकर 84,666.28 पर बंद हुआ।

इसी तरह, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 (निफ्टी-50) भी गिरावट के साथ 25,867 अंक पर खुला। कारोबार के दौरान यह 25,728 अंक के इंट्रा-डे लो तक गया। अंत में 120.90 अंक या 0.47 प्रतिशत गिरकर 25,839.65 पर बंद हुआ।

जियोजित इंवेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा, "घरेलू शेयर बाजार आज कमजोर खुला। अमेरिकी फेड की नीति बैठक से पहले निवेशक सतर्क दिखे। रुपये की कमजोरी, एफआईआई की लगातार बिकवाली और अमेरिका–भारत ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता ने भी बाजार पर दबाव डाला। आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। जबकि पीएसयू बैंक, रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में खरीदारी रही। स्मॉल-कैप शेयरों ने अन्य इंडेक्स की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया।"उन्होंने कहा, "वैश्विक बाजारों में भी दबाव बढ़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जापान में बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है और उम्मीद है कि बैंक ऑफ जापान अपनी दिसंबर बैठक में सख्त रुख अपना सकता है। बाजार में आम तौर पर फेड के 25 बेसिस पॉइंट की दर कटौती और बैंक ऑफ जापान केदरों में वृद्धि की उम्मीद की जा रही है।

सरकार ने पीएलआई ऑटो स्कीम में 5 आवेदनकर्ताओं को दिया 1,350.83 करोड़ रुपए का इंसेंटिव

एजेंसी। नई दिल्ली

प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) ऑटो स्कीम के तहत देश में पांच आवेदनकर्ताओं (11 नवंबर तक) को 1,350.83 करोड़ रुपए का इंसेंटिव जारी किया गया है। यह जानकारी सरकार द्वारा मंगलवार को संसद में दी गई। इस स्कीम को सरकार द्वारा 25,938 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय से लागू किया गया था।

केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने एक प्रश्न के उत्तर में राज्यसभा को बताया कि इस योजना के तहत मार्च 2028 तक (वित्त वर्ष 2019-20 के आधार वर्ष पर) बिक्री लक्ष्य 2,31,500 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, और 30 सितंबर, 2025 तक 32,879 करोड़ रुपए की बिक्री हासिल की गई है।"पीएलआई ऑटो स्कीम में एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (एएटी) उत्पादों के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव है। जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दर बढ़ी है, घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) की आवश्यकता और ईवी वैल्यू चेन का स्थानीयकरण एएटी उत्पादों में भी बढ़ रहा है।

राजस्व वसूली में सुस्ती पर डीसी सख़्त, सभी विभागों को चेतावनी

लक्ष्य हर हाल में पूरा करें, अब ढिलाई बर्दाश्त नहीं : उपायुक्त

- खनन विभाग की वसूली 16% पर अटकी, कई विभाग लक्ष्य से दूर

नवीन मेल संवाददाता

मेदिनीनगर। राजस्व वसूली की कमजोर रफ्तार पर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी समीरा एस मंगलवार को बेहद कठोर रुख में दिखीं। जिले के विभिन्न विभागों की समीक्षा के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजस्व लक्ष्य प्राप्ति में अब किसी भी प्रकार की सुस्ती स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी पदाधिकारियों को दो-टूक चेतावनी दी गई कि निर्धारित लक्ष्य हर हाल में पूरा करना होगा, अन्यथा कार्रवाई तय है।

खनन विभाग की वसूली सिर्फ 16%, डीसी ने जताई कड़ी नाराजगी : खनन विभाग की समीक्षा में पता चला कि 58433.31 लाख रुपये के लक्ष्य के मुकाबले केवल 9489.985 लाख रुपये महज 16.24 प्रतिशत वसूले गए हैं। इस पर उपायुक्त ने कड़ा असंतोष जताते हुए खान निरीक्षक से जवाब तलब किया। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र में भारी संभावनाएँ होते हुए भी राजस्व संग्रहण का यह स्तर न केवल निराशाजनक है, बल्कि गंभीर लापरवाही का संकेत है। परिवहन विभाग ने जहां 73.70 प्रतिशत वसूली कर ली है, वहीं मोटरयान निरीक्षक के स्तर पर स्थिति संतोषजनक नहीं रही। 449 लाख के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 210.16 लाख रुपये (46%) की वसूली पर डीसी ने नाराजगी जताई और तुरंत सुधार का निर्देश दिया।

उत्पाद विभाग की वसूली 57.95 प्रतिशत पर है। उपायुक्त ने कहा कि अवैध बिक्री और लापरवाही पर अब सख्ती से छापामारी की जाएगी। विभाग को चेतावनी दी गई कि लक्ष्य अधूरा रहा तो कार्रवाई से बचना संभव नहीं होगा।

नगर निगम की वसूली भी सिर्फ 56.29 प्रतिशत पर होने से उपायुक्त नाखुश रहीं।

अवर निबंधन, राष्ट्रीय बचत, विद्युत आपूर्ति विभाग सहित अन्य विभागों की समीक्षा में भी कमियाँ सामने आईं। उपायुक्त ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि तत्काल प्रभाव से राजस्व वसूली तेज करने की ठोस योजना लागू करें।

बैठक में अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, तीनों एसडीओ, सहायक समाहर्ता, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचल अधिकारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

म्यूटेशन व भूमि-कार्यों में लापरवाही पर सीओ को फटकार

दाखिल-खारिज, सकसेशन म्यूटेशन, पार्टीशन म्यूटेशन और भूमि सीमांकन मामलों की समीक्षा में कई अंचलों में कार्य लंबित पाए गए। इस पर उपायुक्त ने सीओ को स्पष्ट निर्देश दिया कि तय समयसीमा में सभी मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। भूमि हस्तांतरण और ई-रेवेन्यू कोर्ट के मामलों में धीमी प्रगति पर भी उपायुक्त ने नाराजगी जताई।

पथरिया कला में जबरन धान काटने के मामले में 16 आरोपियों पर केस

चैनपुर। थाना क्षेत्र अंतर्गत पतरिया गांव निवासी विगम सिंह पिता स्व. कर्मदेव सिंह के आवेदन पर चैनपुर थाना में 16 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा ने बताया कि आवेदन के आधार पर जयद्रथ सिंह, रामलाल सिंह, छठनी देवी, मंजू देवी, युक्ति देवी, अमरावती कुंवर, राजमणि देवी, सुदर्शन सिंह, कलावती देवी एवं उमेश सिंह सभी ग्राम पथरिया कला पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप है कि ये सभी खाता संख्या 35, प्लॉट संख्या 82, 84, 85, 95 में दर्ज 75 डिसमिल जमीन पर लगी धान की फसल को भाला, लाठी, बलुआ व गड़ासा के बल पर काट कर अपने घर ले गए।

बरवाडीह में फर्जी लगान रसीद का मामला उजागर

बेतला (लातेहार)। बरवाडीह प्रखंड के कुटमू निवासी ने उपायुक्त के माध्यम से आवेदन देकर भूमि विवाद का मामला उजागर किया। उनका आरोप है कि तत्कालीन अंचल अधिकारी मनोज कुमार और वादी उमाशंकर प्रसाद ने खाता संख्या 81 के कुछ प्लॉट की 2016-17 तक की लगान रसीद फर्जी तरीके से जारी की। आवेदन में बताया गया कि खाता धारक नारायण बैठा, चलितर बैठा और हरेश बैठा के नाम से ऑनलाइन रसीद 2017 से 2025-26 तक जारी होती रही, जबकि हाल की सर्वे में भूमि उनके नाम पर दर्ज नहीं थी। निवासी ने अंचल अधिकारी और वादी पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है।

बालूमाथ बाजार में पुलिस का अवैध शराब विरोधी अभियान 50 लीटर महुआ शराब नष्ट

नवीन मेल संवाददाता

बालूमाथ। मंगलवार को बालूमाथ थाना पुलिस ने हाट बाजार में अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थानों पर बिक रही अवैध महुआ शराब और हड़िया को जब्त करते हुए नष्ट कर दिया। थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि लंबे समय से स्कूल व सार्वजनिक स्थलों के पास अवैध शराब बिक्री की शिकायत मिल रही थी और नशे में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 50 लीटर से अधिक महुआ शराब व हड़िया नष्ट की गई। पुलिस को देखकर अवैध विक्रेता भागने लगे, जिनमें कई लोगों का पीछा कर शराब जब्त की गई। थाना प्रभारी ने चेतावनी दी कि आगे पकड़े जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। अभियान में देवेंद्र कुमार, शमीम खान, चंद्रशेखर दुबे, संजय चौधरी एवं महिला आरक्षियों की सक्रिय भूमिका रही।

मनरेगा और आवास योजनाओं की समीक्षा

सिमरिया (चतरा)। सिमरिया प्रखंड कार्यालय सभागार में मंगलवार को मनरेगा और आवास योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रदेव प्रसाद ने की। बैठक में प्रखंड कार्यालय के कर्मी, पर्यवेक्षक, कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा व आवास), मुखिया, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक और कनीय अभियंता उपस्थित रहे। सभी एजेंडों पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेष रूप से अबुआ आवास के तहत लंबित किश्त भुगतान, आधार सीडिंग, पीएमएवाईजी/अबुआ आवास लाभार्थियों की अभिसरण स्थिति, मनरेगा मानव दिवस सृजन, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना, एबीपीएस आधारित भुगतान प्रणाली और पुरानी लंबित योजनाओं का समापन पर ध्यान दिया गया। बीडीओ ने निर्देश दिए कि प्रत्येक पंचायत में धान अधिप्राप्ति हेतु केंद्र स्थापित किया जाए। पंचायत सचिवों को अव्यवहृत सरकारी भवनों की सूची उपलब्ध करानी होगी। 103 आंगनबाड़ी केंद्र 'सक्षम' के रूप में चिन्हित हैं, जिनमें पोषण वाटिका निर्माण अनिवार्य है। कनीय अभियंताओं को कूप निर्माण के लिए स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया।

अनपढ़ विधवा से छल, 5 डिसमिल के बदले 24 डिसमिल जमीन हड़पी

नवीन मेल संवाददाता

लातेहार। बालूमाथ प्रखंड में एक विधवा को उसकी जमीन से वंचित किए जाने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मौजा बालूमाथ, खाता संख्या 298, प्लॉट 2985 की 24 डिसमिल जमीन विधवा लौकी देवी की जीवनभर की जमा-पूंजी थी, परंतु स्थानीय मुखिया नरेश लोहार और शिवनाथ ठाकुर पर जमीन हड़पने का गंभीर आरोप लगा है।परिवार के अनुसार, विधवा को मात्र 5 डिसमिल जमीन बेचने का झांसा दिया गया, जबकि रजिस्ट्री 24 डिसमिल की करा ली गई। इसके बाद उक्त जमीन मोतीउल रहमान के नाम सिर्फ 5 लाख रुपये में बेच दी गई, जबकि इसकी वास्तविक कीमत 2 लाख रुपये प्रति डिसमिल से भी अधिक बताई जाती है।

अनपढ़ होने का फायदा उठाकर की गई इस धोखाधड़ी से परिवार टूट चुका है। बेटा मुकुंद लोहार ने बताया कि वे कई बार आंचल कार्यालय, एलआरडीसी व डीसी कार्यालय में शिकायत कर चुके हैं, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित परिवार ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र न्याय नहीं मिला, तो वे आमरण अनशन और भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे। उन्होंने प्रशासन से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई कर गरीबों के हक की रक्षा करने की मांग की है।

चंदवा सीएचसी में आज लगेगा दिव्यांगता प्रमाण पत्र शिविर

चंदवा। लातेहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न सीएचसी और पीएचसी में दिव्यांगता प्रमाणन शिविर लगाए जा रहे हैं। जारी आदेश के अनुसार इन शिविरों में योग्य दिव्यांगजनों को प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाएगा। सदर अस्पताल लातेहार की विशेषज्ञ टीम प्रमाणन कार्य करेगी। बुधवार को चंदवा सीएचसी में शिविर लगेगा, जिसमें चिकित्सा पदाधिकारी, नर्सिंग स्टाफ, यूडीआईडी कार्ड प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर मौजूद रहेंगे। सिविल सर्जन ने सभी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अधिक से अधिक दिव्यांगजन शिविर तक पहुँचें, इसके लिए व्यापक प्रचार किया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र आवेदन आवश्यक दस्तावेज पूरे होने पर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा।

महुआडांड़ में मोबाइल छिनतई का आरोप, एक गिरफ्तार और दो फरार

- आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, फरार आरोपियों की लगातार तलाश

नवीन मेल संवाददाता

महुआडांड़। मोबाइल छिनतई के आरोप में महुआडांड़ थाना कांड संख्या 53/25, दिनांक 08/12/2025 के तहत कार्रवाई की गई। आरोपी आकिब अली, उम्र लगभग 19 वर्ष, पिता यूसुफ अली, निवासी गुड़गुटोली, थाना महुआडांड़, जिला लातेहार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में मण्डल कारा, लातेहार भेज दिया। घटना में शामिल दो अन्य नामजद आरोपी अभी फरार हैं। इनमें साहिल उर्फ चिल्ड, पिता मो मुर्सिल, निवासी जरहाटोली और खलील अंसारी, पिता स्व इस्माईल अंसारी, निवासी अम्बवाटोली शामिल हैं। पुलिस उनकी लगातार छापामारी कर रही है और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने का प्रयास कर रही है।पुलिस ने छिनतई के मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि किसी भी परिस्थिति में इस तरह के अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। आम लोगों से भी अनुरोध किया गया है कि इस तरह की घटनाओं में सतर्क रहें और किसी भी अपराध में संलिप्त न हों।

सीजीएल परीक्षा में सफल प्रतिभागी बने युवाओं के प्रेरणास्रोत

नवीन मेल संवाददाता

टंडवा (चतरा)। टंडवा प्रखंड और आसपास के गांवों के कई युवाओं ने सीजीएल परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। सफल अभ्यर्थियों में अंशुमान तिवारी (कढ़नी), रुपेश कुमार, पीयूष कुमार, मयंक कुमार सिंह (बुकरु), राहुल कुमार (रोल-बदबिगहा), परितोष कुमार सिन्हा (खद्धैया), मंजीत कुमार, रोहित कुमार सिंह, पवन कुमार सिंह, धीरज कुमार सिंह (कबरा), आशुतोष कुमार (सेरनदाग), प्रभाकर कुमार (सराढु) और उज्ज्वल कुमार मिश्र (कुड़लौंगा) शामिल हैं। सांसद प्रतिनिधि ईश्वर दयाल पांडेय ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये युवा तैयारी कर रहे अन्य प्रतिभागियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।

सड़क पार करते समय बाइक की टक्कर से स्कूली छात्र घायल

लातेहार। शहर के बानपुर मुहल्ले में मंगलवार को दो स्कूली बच्चों को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में 12 वर्षीय साहिल अंसारी, पिता अब्दुल शमद अंसारी, निवासी अमंवाटीकर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल बच्चे को लातेहार सदर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद पुष्टि की कि बच्चे का दाहिना पैर फ्रैक्चर हो गया है। पुलिस ने बाइक चालक को हिरासत में लेकर मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद क्षेत्र में लोगों में आक्रोश फैला और उन्होंने सड़क पर यातायात नियंत्रण बढ़ाने और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।

पांच सूत्री मांगों को लेकर मेदिनीनगर नगर निगम कर्मियों की भूख हड़ताल, कामकाज ठप

नवीन मेल संवाददाता

मेदिनीनगर। नगर निगम के कर्मचारी मंगलवार को पांच सूत्री मांगों-दैनिक वेतनभोगियों का नियमितीकरण, वेतन संरचना में सुधार, सेवा शर्तों में स्पष्टता, पदोन्नति नीति लागू करने एवं कार्यस्थल सुविधाओं में बढ़ोतरी-को लेकर एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे। यह कार्यक्रम झारखंड लोकल बॉडीज इम्प्लॉइज फेडरेशन के बैनर तले आयोजित किया गया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सरकार ने कई बार आश्वासन दिया, पर कार्रवाई नहीं हुई। हड़ताल से नगर निगम का कार्य पूर्णतः ठप रहा और कामकाज के लिए पहुंचे लोगों को बिना सेवा प्राप्त किए वापस लौटना पड़ा। कर्मचारी संघ अध्यक्ष विशुन राम ने चेतावनी दी कि समाधान नहीं होने पर वे अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

सोनिया गांधी के जन्मदिन पर मिशन बालिका विद्यालय में पौधरोपण

नवीन मेल संवाददाता

मेदिनीनगर। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के जन्मदिन पर 9 दिसंबर 2025 को मिशन बालिका विद्यालय में पूर्व जिला अध्यक्ष जैश रंजन पाठक उर्फ बिट्टू पाठक ने पौधारोपण किया। विद्यालय के बच्चों के बीच पौधे भी वितरित किए गए।जैश रंजन पाठक ने कहा कि सोनिया गांधी का सार्वजनिक जीवन त्याग, सेवा और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में यूपीए सरकार ने 10 वर्षों तक महत्वपूर्ण योजनाएँ लागू कीं।

बीडीओ ने दिखाई मानवता, दिव्यांग व्यक्ति ने किया सराहना

लातेहार। बरवाडीह प्रखंड कार्यालय में बीडीओ रेश्मा रेखा मिंज जनता दरबार के दौरान एक वृद्ध दिव्यांग व्यक्ति चूलाही सिंह की समस्या देखी। उन्होंने तुरंत पीएचडी विभाग के सहायक अभियंता को निर्देश देकर जलमीनार की मरम्मत कराई। इसके अलावा, दिव्यांग व्यक्ति का आधार अपडेट और डीबीटी भी कराया गया। वृद्ध व्यक्ति ने बीडीओ की सराहना करते हुए कहा, "मैडम ने तुरंत काम कर दिया।" बीडीओ ने कहा कि इयूटी के साथ मानवता निभाना भी बहुत जरूरी है।

पेज एक के शेष

नागरिकता से पहले...

याचिका में यह भी कहा गया कि यदि 1983 में ही नागरिकता मिली, तो 1980 में नाम शामिल कराने के लिए किन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया? क्या उस समय फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराया गया? राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वे आरोपों पर विस्तृत जवाब दाखिल करें। बता दें कि इससे पहले, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सितंबर 2025 में दायर उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच कराने की मांग की गई थी। बाद में, इसी आदेश को चुनौती देते हुए रिवीजन पिटीशन दाखिल की गई, जिस पर कोर्ट ने अब जवाब मांगा है।

सरकार के खजाने...

एनडीए की सरकारों ने लिया है ज्यादा कर्ज : वित्त मंत्री ने एक रिपोर्ट दिखाते हुए दावा किया कि जीडीपी के एवज में तीन प्रतिशत से ज्यादा राशि नहीं ले सकते। लेकिन बिहार में डबल इंजन की सरकार है। वहां 6 प्रतिशत बाजार से ऋण लिया गया है। आंध्र प्रदेश ने 4.4, राजस्थान ने 3.7, छत्तीसगढ़ ने 4.9 प्रतिशत ले रखा है। लेकिन हमारी सरकार ने सिर्फ 2.2 प्रतिशत बाजार से लोन लिया है। इस बार हम भी 16,400 करोड़ रुपए लोन लेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि मंईयां सम्मान को सिर्फ 13,500 करोड़ दिया जा रहा है। शेष 78 हजार करोड़ रुपए दूसरी स्कीम के लिए है। राज्य सरकार के सभी विभाग को 30 नवंबर तक की सैलरी मिल चुकी है। आरोप लगाया कि सदन में सिर्फ 10 भाजपा विधायक मौजूद थे और ये लोग विधि व्यवस्था पर चर्चा की बात करते हैं। पुलवामा में सुरक्षा देने में भारत सरकार फेल साबित हुई। करप्शन में शामिल अधिकारी जेल में हैं। पहलगाम की घटना पर एक सिपाही तक सस्पेंड नहीं किया गया। लाल किला के पास शाम में बम धमाका हो गया। नौ लोगों की जान चली गई। इसकी जवाबदेही किसकी है। मंत्री ने कहा कि नक्सल नियंत्रित हुआ है। लेकिन भारत सरकार ने एसआरई फंड देना बंद कर दिया। इस वजह से संसाधन उपलब्ध कराना मुश्किल हो रहा है।

374 घाटों पर...

उन्होंने बताया कि एमडीओ (माइन डवेलपर ऑपरेटर) के चयन में राजस्व का नुकसान नहीं हुआ है।वहीं मामले में भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि पूरे राज्य भर में बालू का अवैध उत्खनन हो रहा है। मंत्री इस मामले में सदन को गुमराह कर रहे हैं। झारखंड में कहीं भी 100 रुपए प्रति सीएफटी बालू नहीं मिल रहा है। कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने मंत्री से जानना चाहा कि पलामू जिले में 71 कौन से बालू घाट हैं जहां सस्ता बालू सरकार लोगों को उपलब्ध करा रही है। उन्होंने मंत्री से पलामू के उन 71 बालू घाटों की सूची की मांग की जहां सस्ते दर पर बालू दिया जा रहा है। विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने सरकार से जानना चाहा कि क्या यह सही है कि जेएसएमडीसी (झारखंड राज्य खनिज विकास निगम) की ओर से राज्य में बालू घाटा के संचालन की व्यवस्था के दौरान काफी कम दर पर एमडीओ का चयन किये जाने के कारण राज्य को राजस्व का बहुत बडा नुकसान हुआ है।

इलाज के लिए...

अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध कराएगी।प्रदीप यादव ने मंत्री से ऐसे बच्चों को रक्तरदान करनेवालों के लिए आई कार्ड बनाने और ऐप बनाने की भी मांग की। उन्होंने बताया कि थैलिसिमिया और सिकल सेल जैसी बीमारियों से पीड़ित बच्चों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए कर्नाटक 20 लाख, बिहार 15 और अरूणाचल प्रदेश में 15 लाख रुपए की सहायता राशि देती है, लेकिन झारखंड में ऐसी सुविधा नहीं है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार कोल इंडिया के सहयोग से इन बीमारियों के लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता करती है। प्रदीप यादव ने मंत्री से झारखंड के थैलिसिमिया से पीड़ित बच्चों को रक्तदान से संबंधित व्यवस्था के बारे में पूछा इसपर मंत्री ने कहा कि यह सुविधा राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में मौजूद है। मंत्री के इस जवाब पर प्रदीप यादव ने नाराजगी प्रकट की और मंत्री पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने मंत्री से एक माह में सभी प्रमंडलों में ऐसी व्यवस्था करने की मांग की। प्रदीप यादव ने कहा कि थैलिसिमिया का इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ही संभव है। इसपर मंत्री ने कहा कि वे आउट ऑफ वे जाकर इसपर काम करेंगे।

दुमका में श्रवण...

इसके साथ ही एजेंसी ने विनय चौबे के करीबी विनय सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह की तलाश में बिहार के लखीसराय में भी छापेमारी की थी। खबर लिखे जाने तक छापेमारी जारी थी।

शराब घोटाले में...

की जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें पाया गया है कि मेसर्स विजन हॉस्पिटलिटी एवं कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स मार्शन इनोवेटिव सिक्यूरिटी प्राइवेट लिमिटेड ने फर्जी बैंक गारंटी के सहारे शराब का व्यापार कर सरकार को नुकसान पहुंचाया। वीएचएससीपीएल ने 5.35 करोड़ और एमआईएसएसपीएल ने 5.02 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी दिया था। महेश सीताराम वीएचएससीपीएल के एमडी हैं। परेश ठाकोर वीएचएससीपीएल के निदेशकों में से एक हैं। विक्रम ठाकोर और बिपिन जाधव भाई परमार भी वीएचएससीपीएल के निदेशकों में से एक हैं। इसके अलावा जगन ठाकोर एमआईएसएसपीएल के निदेशक हैं। बता दें कि प्रारंभिक जांच पूरी करने के बाद एसीबी ने मई महीने में शराब घोटाला केस में प्राथमिकी दर्ज की थी। इस प्राथमिकी में वरीय आईएएस अधिकारी विनय चौबे, उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह और विनय सिंह समेत 10 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। केस दर्ज होने के बाद एसीबी ने विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। इस केस में अब तक एक दर्जन से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी एसीबी ने की है। जिसमें से कई आरोपियों को बेल मिल चुकी है। एसीबी ने इस मामले में अपनी जांच जारी रखी है।

पूर्व उत्पाद आयुक्त...

आईएएस अमित कुमार 4 अगस्त 2021 से 10 जुलाई 2022 तक उत्पाद आयुक्त के पद पर पदस्थापित थे। तब उत्पाद सचिव के पद पर आईएएस विनय कुमार चौबे पदस्थापित थे। एसीबी ने जांच में पाया है कि विनय कुमार चौबे ने छत्तीसगढ़ सिंडिकेट से जुड़े शराब कारोबारियों को फायदा दिलाने के उदेश्य से शराब नीति बनायी। इस दौरान पांच करोड़ रुपये से वह लाभान्वित भी हुए। वहीं, शराब सिंडिकेट के कहने पर ही उनके द्वारा अरुणपति त्रिपाठी को सलाहकार नियुक्त किया गया। बाद में शराब की सप्लायी से लेकर ट्रेकिंग व ट्रेसिंग, मैनपावर का ठेका छत्तीसगढ़ सिंडिकेट से जुड़े कारोबारियों को दिया गया। तब बतौर उत्पाद आयुक्त अमित कुमार की भूमिका की पड़ताल में भी एसीबी जुटी है।

रांची के हालात...

समिति में राज्य के मुख्य सचिव, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के एमडी, डीजीपी, शहरी विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव, रांची स्मार्ट सिटी कारपोरेशन के चेयरमैन सह एमडी, नगर आयुक्त रांची, उपायुक्त रांची, एसएसपी रांची, ट्रैफिक एसपी, अतिरिक्त सालिसिटर जनरल और हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष व सचिव सदस्य होंगे। यह जनहित याचिका झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने दाखिल की है। इसमें रांची शहर की सफाई, यातायात, बिजली व्यवस्था, जलापूर्ति और अन्य जन मुद्दों पर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि रांची की व्यवस्था सुधारना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। समिति एसोसिएशन की ओर से उठाए गए मुद्दों के समाधान पर विचार-विमर्श करेगी ताकि राजधानी की हालत को सुधारा जा सके।

झारखंड पुलिस सेवा...

जिसके बाद भारत सरकार के अवर सचिव चंदन कुमार ने यह आदेश जारी किया है। वर्ष 2020 की चयन सूची में अविनाश कुमार, वर्ष 2022 की चयन सूची में शिवेंद्र, राधा प्रेम किशोर, मुकेश कुमार महतो, दीपक कुमार का नाम है। वहीं, वर्ष 2023 की चयन सूची में मंजरूल होदा, राजेश कुमार, रोशन गुड़िया, श्रीराम सामड का नाम है। 2023 की चयन सूची में भी शिवेंद्र, राधा प्रेम किशोर और मुकेश कुमार महतो के नाम रेगुलेशन के तहत शामिल किए गए हैं। तीन अधिकारियों को प्रोविजनल प्रमोशन गृह मंत्रालय की अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि तीन अधिकारियों- शिवेंद्र, राधा प्रेम किशोर और मुकेश कुमार महतो का चयन अभी अनंतिम (प्रोविजनल) है। अधिसूचना के मुताबिक, इन तीनों अधिकारियों के नाम सेलेक्ट लिस्ट में शामिल जरूर किए गए हैं, लेकिन इनका फाइनल प्रमोशन इनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के क्लियर होने और राज्य सरकार द्वारा इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट (सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र) दिए जाने पर निर्भर करेगा। जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती, इनका चयन प्रोविजनल माना जाएगा। अन्य अधिकारियों का चयन सामान्य प्रक्रिया के तहत किया गया है। इस अधिसूचना के बाद राज्य पुलिस सेवा के इन अधिकारियों के आईपीएस संवर्ग में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है।

जामताड़ा में 5...

ये सभी पेड़ के नीचे बैठकर साइबर अपराध को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने पकड़े गए साइबर अपराधियों के पास से 9 मोबाइल और 12 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए हैं। पकड़े गए साइबर अपराधियों द्वारा फर्जी सिम कार्ड का प्रयोग कर ठगी के लिए किया जा रहा था। बताया जाता है कि उनके मोबाइल से जब्त सिम कार्ड दूसरे राज्य ओडिशा और पश्चिम बंगाल के हैं। जिसको लेकर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है।

KASHYAP'S DENTAL CLINIC

Dr. Vaibhav Kashyap

Oral & Dental Surgeon, C.c. Endodontist & Implantologist Certified Orthodontist, MIDA

" Smiles & More"

छात्र-छात्राओं के लिए 50% की छूट

Facilities

- आरसीटी
- पायरिया का ईलाज
- टेढ़े-मेढ़े दाँतों का ईलाज
- स्माईल डिजाइन
- इनविजिवल क्लिप
- दंत रोपण
- फिक्स दाँत लगाना
- अत्याधुनिक मशीन और तकनीक के द्वारा ईलाज

CHAMBER
SKYLINE - 4006, 4th Floor, Kadru, Opp. Dr. Lal's Hospital, Ranchi
Contact No. : 9199533383, 7903835453
Time : 9 am to 2 pm & 4 pm to 8 pm
Sunday : 9 am to 2 pm
E-mail : vaibhav.kashyap2011@gmail.com

संसदीय समिति की रिपोर्ट : स्वायत्त संस्थाओं में देरी, नियुक्ति में पक्षपात पेपर लीक और त्रुटियां, एनटीए पर भरोसा कम

समिति ने पेन-एंड-पेपर परीक्षाओं का समर्थन किया, क्योंकि सीबीएसई व यूपीएससी की परीक्षाएं सालों से 'लीक-प्रूफ' रही हैं

कृष्णमोहन सिंह

नई दिल्ली। संसद में सोमवार को शिक्षा विभाग की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत आने वाली स्वायत्त संस्थाओं की समीक्षा वाली रिपोर्ट पेश की। इस समिति में सुनेत्रा अजित पवार, रेखा शर्मा, घनश्याम तिवारी, संबित पात्रा, रविशंकर प्रसाद व बांसुरी स्वराज जैसे सांसद सदस्य हैं। रिपोर्ट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, जिसमें कहा गया कि एनटीए ने 'बहुत ज्यादा भरोसा नहीं जगाया है'। समिति ने सुझाव दिया कि एनटीए को तुरंत अपनी कमियों को दूर करना चाहिए और पिछले छह सालों में जमा 448 करोड़ रुपये के सरप्लस का इस्तेमाल परीक्षाओं को खुद आयोजित करने या वेंडर्स की निगरानी मजबूत करने के लिए करना चाहिए। एनटीए ने कुल 3,512.98 करोड़ रुपये वसूले, जिनमें से 3,064.97 करोड़ खर्च हो चुके हैं।रिपोर्ट में परीक्षाओं में देरी और त्रुटियों का जिक्र है। पिछले कुछ सालों में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट समय पर घोषित नहीं हुए, जिससे विश्वविद्यालयों में एडमिशन प्रक्रिया, शैक्षणिक सत्र की शुरुआत और छात्रों पर अनावश्यक दबाव बढ़ा। समिति ने एनटीए को परीक्षाएं और रिजल्ट समयबद्ध तरीके से आयोजित करने की सलाह दी। 2024 में एनटीए ने 14 प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कीं, लेकिन कम से कम पांच में बड़ी समस्याएं रहीं: यूजीसी-नेट, सीएसआईआर-नेट और नीट-पीजी स्थगित हुई; नीट-यूजी में पेपर लीक हुआ; सीयूईटी के रिजल्ट टल गए। जनवरी 2025 में हुई जेईई मेन परीक्षा में फाइनल आंसर की में कम से कम 12 सवालों में त्रुटियां पाई गईं, जिन्हें हटाना पड़ा। समिति का कहना है कि ऐसी घटनाएं छात्रों का सिस्टम पर भरोसा कम करती हैं और एनटीए को भविष्य में ऐसी गलतियां रोकनी चाहिए। समिति ने पेन-एंड-पेपर परीक्षाओं का समर्थन किया, क्योंकि सीबीएसई और यूपीएससी की परीक्षाएं कई सालों से 'लीक-प्रूफ' रही हैं। कंप्यूटर-बेस्ड परीक्षाओं पर सवाल उठाए गए। रिपोर्ट में यूजीसी के ड्राफ्ट रेगुलेशंस पर भी चर्चा है। जनवरी 2025 में जारी यूजीसी (मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ टीचर्स) रेगुलेशंस, 2025 पर 15,066 फीडबैक आए, जिनमें 10 राज्य सरकारें, 92 एसोसिएशंस, 52 यूनिवर्सिटीज, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, एआईसीटीई और आईसीएआर शामिल हैं। ये विश्लेषण के दौर से गुजर रहे हैं। विपक्ष ने ड्राफ्ट पर विरोध जताया, क्योंकि यह राज्य यूनिवर्सिटीज में चांसलर (ज्यादातर गवर्नर) को वाइस-चांसलर नियुक्ति में ज्यादा अधिकार देता है। समिति ने सुझाव दिया कि यूजीसी इसे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के साथ चर्चा करे। अप्रैल 2025 से खाली यूजीसी चेयरमैन पद को तुरंत भरने की मांग की गई। फरवरी 2025 में जारी ड्राफ्ट यूजीसी (प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन) रेगुलेशंस, 2025 को अंतिम रूप देने में देरी पर चिंता जताई। सुझावों में ओबीसी छात्रों के उत्पीड़न को जाति-आधारित परिभाषित करना, विकलांगता को भेदभाव का केंद्र बनाना और संस्थानों को मनमाने फैसले न लेने के स्पष्ट उदाहरण शामिल हैं।अन्य सुझावों में लद्दाख के हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स को मान्यता देने और उसके मॉडल की जांच का प्रस्ताव है। नाक में हाल के ब्राइबरी केस की जांच के नतीजे समिति को साझा करने को कहा। कुल मिलाकर यह रिपोर्ट उच्च शिक्षा प्रणाली की कमजोरियों- एसमैन व सत्ताधारी पार्टी से जुड़े लोगों की कुलपति पद , प्रतियोगिता परीक्षा लेने वाली एजेंसियों के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति से लेकर पेपर लीक तक को उजागर करती है, जो छात्रों के भविष्य को प्रभावित कर रही हैं।

- कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं पर सवाल उठाए गए
- रिपोर्ट में यूजीसी के ड्राफ्ट रेगुलेशंस पर भी चर्चा है-

विपक्ष ने ड्राफ्ट पर विरोध जताया, क्योंकि यह राज्य विश्वविद्यालयों में चांसलर (ज्यादातर गवर्नर) को वाइस-चांसलर नियुक्ति में ज्यादा अधिकार देता है

ट्रेनों की देरी, सड़कों पर जाम , हवाई यात्रा का संकट, कितना नुकसान?

प्रदूषण दूना , मानसिक तनाव दोगुना, आर्थिक हानि 2 लाख करोड़ रु. से ज्यादा

कृष्णमोहन सिंह

नई दिल्ली। एक सज्जन बहुत ही दार्शनिक भाव से कहे- 'अच्छे दिन से लबालब जनता को ट्रेन लेट, सड़क जाम और इंडिगो संकट से बहुत फ़र्क़ नहीं पड़ता। ज्यादातर "होइहें सोई जो राम रचि राखा" के भाव से ओत-प्रोत हैं।' एक अन्य व्यक्ति कह रहे हैं - एक भारतीय के लिए समय की कोई कीमत उतनी नहीं जितनी आप सोच कर परेशान हैं। दैनिक जीवन में ट्रेनों की देरी, सड़कों पर जाम व अब हवाई यात्रा का संकट—ये सब मिलकर अर्थव्यवस्था व व्यक्तिगत उत्पादकता को चूस रहे हैं। भारत में ट्रेनें औसतन 30-60 मिनट से लेकर कई-कई घंटे लेट रहती हैं, सड़कें घंटों के जाम में फंसी रहती हैं, और विमानन कंपनियां बहाने बनाती हैं। लेकिन 2025 के अंत तक, डेटा व तथ्य इस समस्या को और गहरा दिखाते हैं। रेलवे की बात करें तो, दिसंबर 2025 में घने कोहरे ने हालात बिगाड़ दिए। नॉर्दर्न रेलवे ने 1 दिसंबर 2025 से 1 मार्च 2026 तक 56 ट्रेनें निलंबित कर दीं, जिनमें गरीब रथ एक्सप्रेस (12207/12208) और अकाल तख्त एक्सप्रेस शामिल हैं। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 24 ट्रेनें रद्द कीं, जबकि कुल 350 ट्रेनें प्रभावित हुईं। दिल्ली-लखनऊ-गोरखपुर रूट पर ट्रेनें 5-12 घंटे लेट चल रही हैं।रेल यात्री डेटा के अनुसार, 2024 में औसत देरी 18 मिनट घटी, लेकिन वंदे भारत की देरी 21% बढ़ी। आर्थिक नुकसान?- एक रिपोर्ट के मुताबिक, देरी से सालाना 1.5 लाख करोड़ रुपये का घाटा, जिसमें यात्रियों का खोया समय (प्रति व्यक्ति 2-3 घंटे प्रतिदिन) प्रमुख है। रही बात सड़कों की तो सड़कें शहरों का काला धब्बा हैं। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2025 के अनुसार, कोलकाता (34 मिनट 33 सेकंड प्रति 10 किमी), बेंगलुरु (34 मिनट 10 सेकंड) और पुणे दुनिया के टॉप-5 सबसे धीमे शहरों में हैं। बेंगलुरु के निवासी सालाना 117 घंटे (लगभग 13 कार्य दिवस) जाम में खो देते हैं, जबकि मुंबई में 103 घंटे। चेन्नई (30 मिनट 20 सेकंड) और हैदराबाद (31 मिनट 30 सेकंड) भी पीछे नहीं। 2024-25 में वाहनों की संख्या 25.5 मिलियन बढ़ी, 88% निजी वाहन। नतीजा? प्रदूषण बढ़ा, मानसिक तनाव दोगुना, और आर्थिक हानि 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक—जिसमें ईंधन बर्बादी व उत्पादकता नुकसान शामिल है।सबसे ताजा झटका है इंडिगो का संकट। 2 दिसंबर 2025 से शुरू होकर, नए 'फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट' नियमों (पायलट रेस्ट 48 घंटे, नाइट ड्यूटी सीमित) के कारण 5 दिसंबर को 1,000+ उड़ानें रद्द हुईं—जिनमें दिल्ली से सभी डिपार्चर शामिल। कुल 2,000-4,000 उड़ानें प्रभावित, लाखों यात्री फंसे। डीजीसीए ने सीईओ पीटर एल्बर्स को शो-कॉज नोटिस जारी किया, जबकि सरकार ने किराया कैप लगाया। इंडिगो का दावा: 10 दिसंबर तक सामान्यीकरण, लेकिन पूर्ण बहाली फरवरी 2026 तक। आर्थिक प्रभाव? यात्रियों का खोया समय (20+ घंटे प्रति व्यक्ति) और 610 करोड़ रुपये रिफंड—कुल हानि 5,000 करोड़ से ऊपर। ये देरी केवल असुविधा नहीं, बल्कि आर्थिक बम हैं। विश्व बैंक अनुमान- समय का मूल्य (वैल्यू ऑफ टाइम) प्रति व्यक्ति 200-500 रुपये/घंटा मानें तो सालाना 3-4 लाख करोड़ का नुकसान। इन नुकसान व परेशानियों से बचने के लिए सब कुछ देश के एक -दो सबसे धनी उद्योगपतियों के हवाले ज्यादातर उद्योग - धंधे करने के बजाय अन्य उद्योगपति जो ईमानदार हों , को प्रश्रय दिया जाए, ट्रैफिक सिस्टम, मेट्रो विस्तार, क्रू ट्रेनिंग व कंजेशन प्राइसिंग समयबद्ध करके बेहतर बनाया जाए।

जापान में भीषण भूकंप के बाद लगातार तेज आफ्टरशॉक्स से दहशत में लोग, अलर्ट जारी

टोक्यो । सोमवार की देर रात उत्तरी जापान में 7.5 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिसमें 23 लोग घायल हो गए और प्रशांत तटवर्ती इलाकों में सुनामी आ गई। अधिकारियों ने संभावित झटकों और महाभूकंप के बढ़ते खतरे की चेतावनी दी है। जापानी सरकार अभी भी सुनामी और देर रात आए भूकंप से हुए नुकसान का आकलन कर रही है। यह भूकंप रात लगभग 11:15 बजे प्रशांत महासागर में, जापान के मुख्य होंशू द्वीप के सबसे उत्तरी प्रान्त, आओमोरी के तट से लगभग 80 किलोमीटर (50 मील) दूर आया था। भूकंप के बाद लगातार आ रहे आफ्टरशॉक्स की वजह से लोग दहशत में हैं। स्थानीय नागरिक, सुविधा स्टोर के मालिक नोबुओ यामादा ने बताया, "मैंने पहले कभी इतने बड़े भूकंप का अनुभव नहीं किया, सौभाग्य से हमारे क्षेत्र में बिजली की लाइनें अभी भी चालू थीं।

पटना-दिल्ली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन संचालन एक माह में

ब्यूरो

नई दिल्ली। दिसंबर 2025 के अंत या जनवरी 2026 से पटना से दिल्ली के बीच देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है। यह ट्रेन केवल 8 घंटे में 1000 किलोमीटर की दूरी पूरी करेगी। आम स्पीड 160 किमी/घंटा व ज्यादा से ज्यादा 180 किमी/घंटा तक जाएगी। यानी सुबह दिल्ली पहुंचकर पूरा दिन काम कर सकते हैं या शाम को पटना से निकलकर सुबह दिल्ली उतर सकते हैं।

ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे:

- 11 थर्ड एसी (611 बर्थ)
- 4 सेकंड एसी (188 बर्थ)
- 1 फर्स्ट एसी (24 बर्थ)

कुल 827 यात्री सफर कर सकेंगे। किराया राजधानी एक्सप्रेस जितना ही रखा जाएगा।

किराया राजधानी एक्सप्रेस के बराबर

दिन वाली वंदे भारत की शिकायतें और इस ट्रेन में सुधार :

- लोग दिन वाली (सीटिंग) वंदे भारत में अक्सर ये शिकायत करते थे-

सीटें बहुत सख्त हैं, कमर दर्द हो जाता है। लेग रूम बहुत कम है। खिड़की के पास चार्जिंग पॉइंट नहीं।टॉयलेट गंदे हो जाते हैं।खाना ठंडा और महंगा मिलता है।

नई स्लीपर वंदे भारत में ये सारी समस्याएं दूर करने की बात कही जा रही है: गद्दे और तकिए बहुत नरम और आरामदायक रखे गए हैं। हर बर्थ के पास अपना चार्जिंग सॉकेट और रीडिंग लाइट है।टॉयलेट टच-फ्री और बायो-वैक्यूम वाले हैं, हमेशा साफ रहेंगे। फर्स्ट एसी में तो शावर (गर्म पानी से नहाने की सुविधा) भी है। खाना ट्रेन की अपनी मॉड्यूलर किचन में ताजा बनेगा।

सीजेआई गवई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश को वकीलों ने चप्पलों से पीटा

जब जूता फेंका था तो कहा था- 'भगवान ने सपने में आकर उन्हें ये काम करने कहा था'

ब्यूरो

नई दिल्ली। देश के तबके सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर की 9 दिसंबर 2025 को वकीलों ने धुनाई कर दी। यह हुआ दिल्ली के कड़कड़डूमा में कोर्ट में। यहां वकीलों ने पं.राकेश किशोर की चप्पलों से पिटाई की। और पिटाई के दौरान राकेश किशोर कहता रहा कि मुझे क्यों पीट रहे हो, सनातन धर्म की जय हो।मालूम हो कि वकील राकेश किशोर ने हाल ही में गवई जब सीजेआई पद पर थे और सर्वोच्च न्यायालय के कोर्ट नं.1 में एक केस की सुनवाई कर रहे थे , तो उनके ऊपर पं.राकेश किशोर ने जूता फेंका था। जिस पर काफी हंगामा हुआ है। हालांकि, इस घटना के बाद तबके सीजेआई गवई ने राकेश किशोर को माफ कर दिया था। लेकिन मंगलवार 9 दिसंबर 2025 को कड़कड़डूमा कोर्ट में वकीलों ने राकेश किशोर की पिटाई कर दी। यह घटना तब हुई जब राकेश किशोर कड़कड़डूमा कोर्ट में मौजूद थे। उसी वक्त कुछ वकीलों ने उन पर हमला कर दिया। राकेश पर धक्का-मुक्की व चप्पलों से हमला किया गया। बड़ी मुश्किलों से कोर्ट सुरक्षा कर्मियों ने बीच-बचाव करके उन्हें बाहर निकाला। मालूम हो कि तब सीजेआई गवई पर जूता फेंकने के बाद बार काउंसिल ने राकेश किशोर को निलंबित कर दिया था। तमाम आलोचनाओं के बाद राकेश किशोर ने कहा था कि उन्हें अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। किशोर ने कहा था कि भगवान ने सपने में आकर उन्हें ये काम करने कहा था। लेकिन 9 दिसंबर को पिटाई के बाद राकेश किशोर ने यह नहीं बताया की भगवान ने सपने आकर 'वकील तुमको चप्पलों से पीटेंगे' बताया था या नहीं। राकेश किशोर एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जो दिल्ली बार काउंसिल में 2009 से पंजीकृत हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निलंबन के बाद वह आगे की कार्रवाई तक कोई भी केस नहीं लड़ सकते हैं। मालूम हो कि 6 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 में सुनवाई के दौरान, राकेश किशोर ने तत्कालीन सीजेआई बी.आर. गवई पर जूता फेंका था। हालांकि, वो जूता बीच में ही गिर गया था। यह घटना तब सुबह लगभग 11:35 बजे हुई, जब सुप्रीम कोर्ट में खजुराहो के जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की सिर कटी मूर्ति की पुनर्स्थापना से जुड़े मामले पर सुनवाई चल रही थी।

- पिटाई के दौरान राकेश किशोर कहता रहा कि मुझे क्यों पीट रहे हो, सनातन धर्म की जय हो...

सीडीएफ बनते ही आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ उगला जहर भारतीय सेना करारा सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार

एजेंसी । नई दिल्ली

आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेज़ बनते ही भारत के खिलाफ जहर उगला है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के सैन्य ढाँचे में सीडीएफ का पद नया है और पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ढाँचे के सीडीएस पद को एक तरह से कॉपी किया है। हम आपको बता दें कि मुनीर सीडीएफ के अलावा पहले से ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बने हुए हैं। इस प्रकार अब पाकिस्तान की सेना, वायुसेना, नौसेना और उसकी परमाणु क्षमता, सबका शीर्ष नियंत्रण एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित है। अपने नए पद पर नियुक्ति के बाद जीएचक्यू में पहले संबोधन में आसिम मुनीर ने भारत को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भारत ने कोई भी आक्रामक कदम उठाया, तो पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पहले से कहीं अधिक कठोर और विनाशकारी होगी। हम आपको याद दिल दें कि मुनीर ने पिछली बार भी कहा था कि यदि पाकिस्तान पर अस्तित्व का संकट आया तो वह अभूतपूर्व प्रतिक्रिया देगा। अब सीडीएफ बनते ही उन्होंने फिर भारत को चेतावनी भरा संदेश दिया है।

मुनीर की चेतावनी बेअसर : भारत की ताकत के सामने पाकिस्तान की रणनीति खोखली

देखा जाए तो आसिम मुनीर का सीडीएफ के रूप में भारत के लिए पहला संदेश कोई सामान्य सैन्य वक्तव्य नहीं है। अब पाकिस्तान की सेना, नौसेना, वायुसेना और सबसे महत्वपूर्ण बात यानि परमाणु हथियारों का नियंत्रण, एक ही व्यक्ति के हाथ में है। ऐसे में मुनीर के द्वारा भारत के प्रति दिया गया कठोर प्रतिक्रिया वाला बयान स्वाभाविक रूप से क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चिंता पैदा करता है। किन्तु वास्तविकता यह है कि यह चेतावनी न तो भारत को डरा सकती है और न ही पाकिस्तान की स्थिति को मजबूत कर सकती है। बल्कि यह बयान पाकिस्तान की भीतरी राजनीति और आर्थिक अस्थिरता से जनता का ध्यान हटाने का प्रयास अधिक प्रतीत होता है।

बॉर्डर 2 से अहान शेट्टी का फर्स्ट-लुक जारी...

टैंक गन थामे नेवी ऑफिसर लुक में नजर आए

फिल्म बॉर्डर 2 से अहान शेट्टी का फर्स्ट-लुक मंगलवार को जारी किया गया। इसमें वह एक नेवी ऑफिसर के किरदार में नजर आ रहे हैं और काफी दमदार लग रहे हैं। उनके लुक को देखकर लोग उनकी तुलना सुनील शेट्टी से भी कर रहे हैं, जिन्होंने पहले बॉर्डर में अहम किरदार निभाया था। मेकर्स की ओर से जारी किए गए पोस्टर में अहान शेट्टी को युद्ध के बीच में दिखाया गया है। उनके चेहरे पर खून के निशान हैं और उनकी आंखों में दृढ़ता झलक रही है, साथ ही अहान के हाथों में टैंक की गन है। इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, लहरों से भी मजबूत। तूफान से भी भयानक। इसके साथ ही बताया गया है कि यह फिल्म अगले साल 2026 में 23 जनवरी को रिलीज होगी। वहीं, इस पोस्टर पर सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। एक ने लिखा, क्या कमाल का फर्स्ट लुक पोस्टर है अहान की असली एंट्री तो अब होने जा रही है बॉलीवुड में। दूसरे ने लिखा है, अहान शेट्टी अपने पापा सुनील शेट्टी की तरह ही नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बॉर्डर 2 में अहान नहीं बल्कि अन्ना सुनील शेट्टी ही हैं।

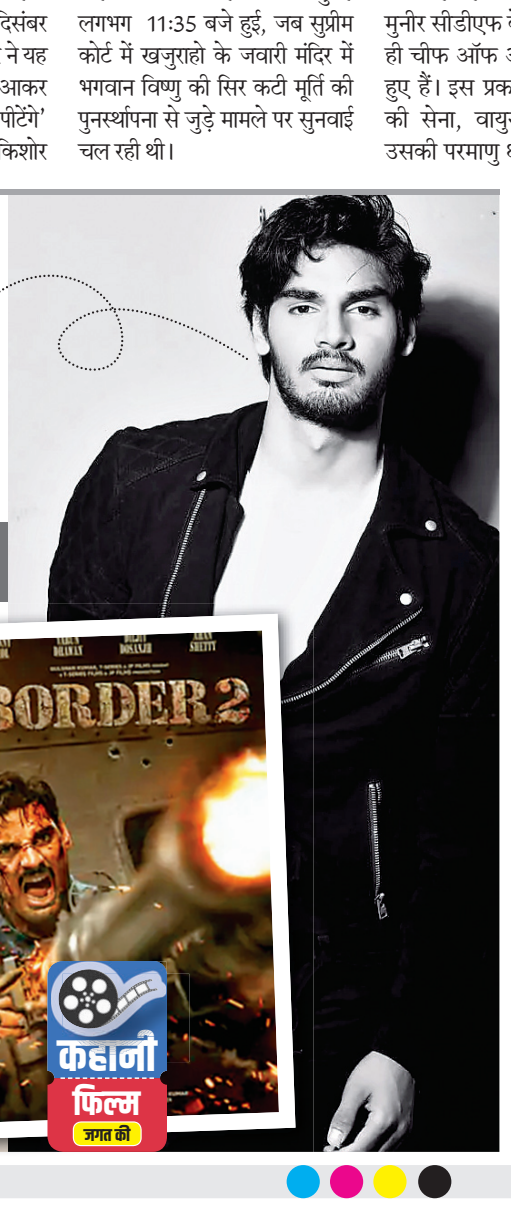

कैसे विवादों में आई थी फिल्म : बॉर्डर-2 तब विवादों का केंद्र बन गई थी, जब फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने दिलजीत दोसांझ की कास्टिंग पर सवाल उठाया। एफआईसीई ने कहा था कि दिलजीत ने हाल ही में एक पाकिस्तानी अभिनेत्री के साथ प्रोजेक्ट किया था।

अफगानिस्तान में फिर डोली धरती, 4.5 के बाद अब आया 3.8 तीव्रता का भूकंप

नई दिल्ली । राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के एक बयान में कहा गया है कि मंगलवार को अफ़ग़ानिस्तान में 3.8 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप 70 किलोमीटर की गहराई पर आया। इससे पहले, दिन में 10 किलोमीटर की उथली गहराई पर 4.5 तीव्रता का एक और भूकंप आया, जिससे यह आफ्टरशॉक के लिए अतिसंवेदनशील हो गया। भूकंप आमतौर पर गहरे भूकंपों की तुलना में ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उथले भूकंपों से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों की सतह तक पहुँचने की दूरी कम होती है, जिसके परिणामस्वरूप ज़मीन ज़्यादा हिलती है और इमारतों को ज़्यादा नुकसान और ज़्यादा हताहत होने की संभावना होती है। रेड क्रॉस के अनुसार, अफ़ग़ानिस्तान में शक्तिशाली भूकंपों का इतिहास रहा है, और हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला एक भूगर्भीय रूप से सक्रिय क्षेत्र है जहाँ हर साल भूकंप आते हैं। शराफत ज़मान अमर के अनुसार, 4 नवंबर को उत्तरी अफ़ग़ानिस्तान में एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिसमें कम से कम 27 लोग मारे गए और 956 अन्य घायल हो गए।

दर्दनाक हादसा : जकार्ता की 7 मंजिला इमारत में भीषण आग, 22 की मौत

एजेंसी । नई दिल्ली

इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में मंगलवार को एक कार्यालय भवन में आग लग जाने से कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। आग की लपटें सात मंजिला इमारत में फैल गईं, जिससे आसमान में घना काला धुआं उठने लगा और मध्य जकार्ता में कार्यालय भवन में काम करने वाले कर्मचारियों और आस-पास रहने वाले स्थानीय निवासियों में दहशत फैल गई।

एएफपी समाचार एजेंसी ने मध्य जकार्ता के पुलिस प्रमुख सुसात्यो पुरनोमो कोंड्रो के हवाले से बताया कि आग लगने से 20 पीड़ितों में 7 पुरुष और 15 महिलाएँ शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मृतकों में एक गर्भवती महिला भी शामिल है। मध्य जकार्ता के एक मोहल्ले में आग लगने से आस-पास के निवासियों और कर्मचारियों में भी दहशत फैल गई है। स्थानीय कोम्पास टीवी के अनुसार, आग बुझा दी गई है, लेकिन इमारत को खाली कराने के प्रयास जारी हैं क्योंकि कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। स्थानीय समाचारों में आगे बताया गया है कि आग के केंद्र में स्थित इमारत टेरा ड्रोन इंडोनेशिया का कार्यालय है, जो खनन से लेकर कृषि क्षेत्रों तक के ग्राहकों को हवाई सर्वेक्षण गतिविधियों के लिए ड्रोन उपलब्ध कराता है।

कोम्पस टीवी से बात करते हुए, सेंट्रल जकार्ता मेट्रो पुलिस प्रमुख, वरिष्ठ आयुक्त सुसात्यो पुर्नोमो कोंड्रो ने बताया कि आग पहली मंजिल पर लगी थी और कर्मचारी आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े। पहली मंजिल पर एक बैटरी थी, जिसमें आग लग गई, फिर कर्मचारी उसे बुझाने में कामयाब रहे, फिर पता चला कि जलती हुई बैटरी फैल गई, क्योंकि पहली मंजिल गोदामों में से एक है।